हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

14.03.2022/1405/RKS/वाई के-1

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का जन्म दिवस पर बधाई देने पर धन्यवाद प्रकट किया गया।)

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरंभ

<u>प्रश्न संख्याः 5115</u>

श्री जवाहर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। नगर निगम, मण्डी के समखेतर वार्ड नम्बर, 101 में जो दुकान किराये पर दी गई है वह पहले सहकारिता विभाग के पास थी। लेकिन अब यह दुकान हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, मण्डी के नाम है। इस दुकान का किराया 800/-रुपये मासिक प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 800/-रुपये मासिक किराया किस वर्ष से दिया जा रहा है? प्रश्न के उत्तर में आज तक कुल किराया 19,200/- रुपये वसूलने की बात कही गई है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह वसूली कब से कब तक की गई है? यह दुकान श्री शशी भूषण, फोटो स्टूडियों के नाम से ली गई है लेकिन वहां पर किसी और ही ठेकेदार का दफ्तर चला हुआ है। यह दुकान श्री शशी भूषण को कब अलॉट की गई थी और इस दुकान में ठेकदार का दफ्तर कब से चला हुआ है, इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए? इस दुकान की कीमत लाखों रुपये है इसलिए मेरा आग्रह है कि इस दुकान को अतिक्रमण से छुड़ाया जाए। अगर विभाग इस दुकान की पगड़ी ले तो इसकी पगड़ी भी लाखों रुपये बनती है। आज की तारीख में इस दुकान का किराया 15-20 रुपये बनता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इस दुकान को अतिक्रमण से बचाया जा सके। इस दुकान को कब तक वापिस ले लिया जाएगा और जो पिछला किराया है उसे कब तक वसूल किया जाएगा, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए?

14.03.2022/1405/RKS/वाई के-2

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ने मण्डी की दुकान के बारे में प्रश्न किया है। वास्तव में यह दुकान सहकारिता विभाग की नहीं है। यह दुकान जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ, मण्डी की है जिसे श्री शशी भूषण, सुपुत्र श्री देवकी नन्द शर्मा, जिला मण्डी को फोटो स्टूडियो हेतु मु0 800/-रुपये मासिक किराये पर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यह दुकान लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन के बाद जब इसका विघटन हुआ तो देनदारियों इत्यादि को चुकता करने के लिए इसकी सारी सम्पत्तियां

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1410/बी.एस./वाई0के0/-1

प्रश्न संख्याः 5115 क्रमांगत...

शहरी विकास मंत्री जारी...

जो इत्यादि थीं, वे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, मण्डी के पास हस्तांतरित कर दी गई हैं। यह बैंक की भूमि है, जिसे फैडरेशन से हस्तांतरित किया है। यह उस पर निर्मित दुकान है और इस पर अवैध कब्जा कर रखा है, यह शशी भूषण नाम का व्यक्ति है। बैंक ने दिनांक 14.10.2013 को इस भूमि की निशान देही करवाई थी और जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ दुकान खाली करने के लिए 21.01.2017 को माननीय सब डिविजनल क्लैकटर, मण्डी के कोर्ड में मामला दायर किया था। अब यह फैसला दिनांक 14.02.2020 को बैंक के पक्ष में आया हैं और अब दुकान को खाली करवाया जाएगा। इसमें वर्ष 2020 से आज तक किराए की कोई वसूली नहीं की गई है। आज तक केवल जो किराया आया है वह मात्र 19,200 रुपए आया है, इसके अलावा किराए के बारे में बताया नहीं गया है। वर्ष 2000 से ले करके आज तक इसका किराया नहीं दिया गया है। अब कोर्ट ने कार्रवाई कर दी है, यदि ये दूसरे कोर्ट में नहीं जाते हैं तो इस दुकान को खाली करवा दिया जाएगा।

श्री जवाहर ठाकुर : अध्यक्ष जी, इसमें एक चीज जो दर्शाने की लिए पूछी गई थी, उसे नहीं दर्शाया गया है कि इस दुकान को कब से दिया गया है। दूसरा 800 रुपए के हिसाब से आज तक कितना किराया बनता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विभाग या सरकार अब इस कब्जे को कब और कैसे छुड़ाएगी?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि डिस्ट्रिक्ट फैडरेशन ने निशियली किराए पर इसे दिया था और उन्हीं की यह भूमि है और उनकी लिक्विडेशन हो गई है, जब लिक्विडेशन हो जाती है, तो सारी देनदारियां इत्यादि देनी होती हैं। इसलिए यह सारी सहाकारी बैंक में चली गईं हैं और यह आजकल सहकारी बैंक के कब्जे में है। हमारी जो अभी तक की सूचना है, उसके अनुसार अभी तक 19,200 रुपए वसूल कर लिया गया है। बाकी किराया वर्ष 2000 से नहीं लिया गया है। जो सोसायटी बनी थी, जिससे यह लिक्विडेशन में आई है और किराए पर दिया था, उसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं

14.03.2022/1410/बी.एस./वाई0के0/-2

है। इसका रिकार्ड बैंक में होना चाहिए या विभाग के पास होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो ट्रेस किया गया है, उसमें अभी तक ट्रेसआउट नहीं हुई है। इसकी इंक्वायरी हम हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से भी और पुराना जो लिक्विडिटर इत्यादि होंगे उनसे अवश्य करेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे कि यह दुकान कब से थी और कितना इसका किराया है। जिसके पास यह दुकान किराए पर दी गई थी, उससे सारा किराया वसूल किया जाएगा। यदि इस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो इसको खाली करवाया जाएगा, उसके लिए जो भी लिगल प्रोसेस होगा उसमें हम सख्त कार्रवाई अमल में लाएगें।

प्रश्न समाप्त/

14.03.2022/1410/बी.एस./वाई0के0/-3

प्रश्न संख्याः 5116

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके जन्म दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं, सामूहिक रूप से तो हमने दे दे थी, आप युग-युग जिएं ऐसी कामना मैं करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1415/ए.जी.-एन.जी. /1

प्रश्न संख्या - 5116.....जारी

श्री राकेश सिंघा जारी.....

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सरकार की कुछ परेशानियां भी हल करेगा, खासतौर पर आऊटसोर्स कर्मियों की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश दे दिया है, उसकी उल्लंघना न आप कर सकते हैं और न कोई और। यहां पर अनेक माननीय सदस्य आऊटसोर्स के मुद्दे उठाते रहते हैं। माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं और इन्होंने इस महामारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जब इसमें जी.वी.के. के कर्मी हुआ करते थे तब उन्होंने सरकार के खर्चे पर हैदराबाद में ट्रेनिंग ली थी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि will the Government retain all the workers जो जी.वी.के. द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनके ख़िलाफ Disciplinary Action etc. जैसे कोई भी चार्ज़िस नहीं थे और खासतौर पर बहुत सी महिलाएं ई.एम.टी. थीं व Maternity में चली गई। They were on the family way. मेरे

पास 2-3 ऐसे केस हैं who are on their family way, उन्होंने कोरोना में काम किया था और जब वे ज्वाइनिंग देने गईं they were refused. मुझे पता है कि no Government can be insensitive to the problems of the women. इसलिए क्या उन सबकी रिटेंशन होगी? दूसरा प्रश्न यह है कि आऊटसोर्स कर्मी के लिए क्या सरकार Maternity Leave देगी या नहीं? This has to be categoric because अभी ऐसा नहीं किया है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह भी है कि यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है क्योंकि इंजरी या दुर्घटना होने पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए यही काम आती है इसलिए who is the principal employer. किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी है। या तो एन.एच.एम. जिम्मेवारी लेगा या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लेगा।

14-03-2022/1415/ए.जी.-एन.जी. /2

मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन है जो इसका Principal Employer है? माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये प्रति माह हर कर्मी को दिया जाएगा वह पैसा क्या सरकार देगी और माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 से देने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय, इतनी जानकारी मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण सेवा (108 व 102 एम्बुलैंस सेवा) का वैंडर बदल चुका है। वैंडर बदल जाने के कारण आपकी व हमारी चिंता स्वभाविक है क्योंकि वे सभी कर्मी आपसे व हमसे लगातार मिलते रहे हैं। माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि उन सभी कर्मियों को रखा जाएगा या नहीं। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि इस वर्ष 15 जनवरी से नए वैंडर ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। उनके साथ सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी है और उन्होंने दिनांक 14-01-2022 तक जी.वी.के. के पे-रोल पर जितने भी कर्मी थे उन सभी को रखने का आश्वासन दिया है। इसमें एक अपवाद हो सकता है कि किसी कर्मी के ख़िलाफ कोई बहुत गम्भीर आरोप हो तो वह कर्मी इस एग्रीमेंट से बाहर हो सकते हैं

अन्यथा उन्होंने सभी कर्मियों को रखने का आश्वासन दिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि Principal Employer कौन है। इस बारे में हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि जहां तक भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1420/JS/AG/1

प्रश्न संख्याः 5116ः-----जारी----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही इसमें कार्य किया जा सकता है। हमारी जो केन्द्र सरकार है, यानि एन.एच.एम. के तहत कार्यक्रम के तहत ही ये सेवाएं चलाई जाती हैं। इसमें गाइडलाइन और नियम वे ही तय करते हैं। उसके मुताबिक ही प्रिंसिपल इम्प्लॉयर कम्पनी है, यानि सरकार प्रिंसिपल इम्प्लॉयर नहीं है। आपने स्वयं कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश भी इसमें स्पष्ट करता है कि Principal Employer, learned Chief Judicial Magistrate का जो आदेश है, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि प्रिंसिपल इम्प्लॉयर वह कम्पनी है न कि सरकार है। इस निर्णय के खिलाफ जिन कर्मचारियों को यह तर्कसंगत नहीं लगा, वे उच्च न्यायलय में इसके खिलाफ गए हैं। मुझे लगता है, उनका जो पक्ष है, वह यह है कि प्रिंसिपल इम्प्लॉयर सरकार घोषित हुई है। हमें भी माननीय उच्च न्यायालय से उस आदेश की प्रतीक्षा है। भविष्य में जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश होंगे, निश्चित तौर पर उनकी अनुपालना होगी। यह बात ठीक है कि जो बढ़ा हुआ मानदेय देने की बात हुई है, उसके आदेश कोर्ट ने किए हैं, वह जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं बनती है, मैं यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। माननीय उच्च न्यायालय के जो भी ओदश होंगे उनकी अनुपालना निश्चित तौर पर होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश कर्मी हिमाचल के हैं, यहां के वाशिंदें हैं। इस योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार उनके हर मामले को सहानुभूतिपूर्वक

देखेगी भी और जो भी सरकार को करना पड़ेगा, वह भी करेगी। जब 12,000 रुपये से 15,000 रुपये करने का मामला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, हालांकि प्रिंसिपल इम्प्लॉयर हम नहीं थे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया तो करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की राशि बनती थी, हमारी जिम्मेदारी न होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में फैसला दिया कि यह राशि हम देंगे। यह राशि माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों के बाद, केबिनैट के

14.03.2022/1420/JS/AG/2

निर्णय के बाद उनको दे दी गई। आपके जो अन्य प्रश्न हैं the maternity leave to the outsourced is a broader term which has to be decided holistically. **इसमें हम विचार करेंगे और यह मामला हमारे ध्यान में आया है, इसमें जो भी हमारे करने का होगा we will definitely take a sympathetic view and try to help the affected employees.** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य के प्रश्न थे, उन सबके मैंने यहां पर ज़वाब दे दिए हैं।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ज़वाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर तो हमें मान कर चलना है कि जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं he is not the employee of the Himachal Pradesh Government. He is working on behalf of the Himachal Pradesh Government. वह हिमाचल प्रदेश की सरकार की वजह से यहां पर काम करता है। मुझे बताएं कि क्या रिट पिटीशन इडिंविजुअल के खिलाफ आ सकती है? रिट पिटीशन सिर्फ स्टेट के खिलाफ आती है। Writ petition cannot be brought against any individual. Writ petition cannot be brought against Rakesh Singha or Shri Jai Ram Thakur. Writ Petition will be brought against the State. स्टेट है और इसीलिए जब स्टेट है वह प्रिंसिपल इम्प्लॉयर निश्चित रूप से, क्योंकि वह काम, तब हमने

उन्हें ट्रेनिंग में क्यों भेज दिया? Why did the Himachal Pradesh Government send the EMTs for training?

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

14.03.2022/1425/SS-AS/1

प्रश्न संख्या : 5116 क्रमागत

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

जो हमारे ई0एम0टीज0 हैं वे हमने क्यों भेजे? You see we cannot take this position, महेन्द्र सिंह जी, आप exonerate हो गए हैं। जो आपने आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनानी है, प्रिंसीपल इम्प्लॉयर कोई नहीं है इसलिए सारा कम्पनी देखे। आप ऐसा मत करो। अगर हम कम्पनी पर छोड़ देंगे और प्रिंसीपल इम्प्लॉयर नहीं रखेंगे तो अराजकता पैदा होगी तथा आप समझ रहे हैं कि कम्पनियां गला घोंट देती हैं। They don't spare anyone. कि आपको आना है। "नहीं" शब्द नहीं कहना है। जो हम आई0पी0एच0, फॉरैस्ट या किसी भी डिपार्टमैंट का काम कर रहे हैं the State will take the responsibility to implement the law. हम कम्पनी पर छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। कम्पनी भाग गई। वह तो हैदराबाद चली गई। हाई कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बन गया। वे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कैसे अमल करेंगे? इसलिए मुझे इस प्रश्न पर फर्दर क्लैरिटी चाहिए। अगर प्रिंसीपल इम्प्लॉयर कम्पनी है तो the writ petition could has not fall into the High Court only because वह स्टेट इंवोल्वड थी इसलिए रिट पटीशन लाई थी। तब बाकी लोग क्यों पार्टी बन गए? एन0एच0एम0 क्यों बन गया, हैल्थ डिपार्टमैंट क्यों बन गया, हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों बन गई, केन्द्र सरकार क्यों बन गई? इंडविजुअल रिट पटीशन में पार्टी नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इन से जानना चाहूंगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं हालांकि मैंने उनका जवाब काफी विस्तार से देने का प्रयास किया है। हर इम्प्लॉयर चाहे वह आउटसोर्स हो, चाहे वह कंट्रैक्चुअल हो, चाहे वह रेगुलर हो; हम किसी नियम या कानून से बंधे हैं। आपने कहा कि कम्पनी गला घोंट देती है, मैं एग्री करता हूं कि कई बार

शोषण भी होता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये सेवाएं भलीभांति हमारे प्रदेश के अंदर चली हैं और इस योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को अपना रोज़गार अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप जो कह रहे हैं, देखिए यह न मेरे कहने से होगा और न आपके कहने से होगा। जिनके तहत यह कार्यक्रम चल रहा है वे गाइडलाइन्स हमको समझनी होंगी और उनका पालन

14.03.2022/1425/SS-AS/2

हमको करना पड़ेगा। दूसरे माननीय न्यायालय ने भी बड़े स्पष्ट तौर से कहा है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। Para-44, "Judged in the light of my findings" ये लर्नड सी0जे0एम0 लेबर कोर्ट कह रहे हैं on issues No. 1 and 7 above, the Petition is allowed with cost and the workers of the Petitioner Union are held entitled for differential amount of minimum wages and overtime from Respondent No. GVK (EMRI) w.e.f. 15.02.15. and as calculated in *Annexure-C* इसी की कंटीन्यूशन में आगे कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि गवर्नमैंट इस मामले में प्रिंसीपल इम्प्लॉयर नहीं है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। The Hon'ble Judge is saying in his judgment, "I am of the considered view that the State Government in the present case does not fall within the definition of the employer as defined under Section-2 (e) of the Minimum Wages Act and, therefore, cannot be held degree liable for non-payment of minimum wages, over time wages to the workers of the petitioner union." How can we go out this judgment? और इस निर्णय को इम्प्लॉयर्ज ने they have challenged this judgment in the Hon'ble High Court and we are waiting for the judgment of the Hon'ble High Court. I want assure the Hon'ble Member that whatsoever will be the directions of the Hon'ble High we will follow it. दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कर्मचारियों के हितों का प्रश्न है चाहे हमारे एन0एच0एम0 के कर्मचारी हैं, अभी एक और प्रश्न इसी संबंध में आगे आ रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल जागरूक है। हम अपने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करेंगे। अगर कम्पनी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करती है तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक प्रॅफोर्मैंस गारंटी के तौर पर दो करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास पड़ा हुआ है। **पूरा सैटल करेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। कोई कोताही सरकार की**

ओर से नहीं बरती जाएगी। जो माननीय सदस्य का वक्तव्य था उससे मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे कि it is not sensitive to the issues of the employees those who are working in 108 Ambulance Service. यह बिल्कुल गलत है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। **इनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना होगा, वह उठाएगी।**

जारी श्रीमती के0एस0

140320221430/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 5117

श्री अरुण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है कि प्रदेश में कुल 143 पुलिस चौकियां हैं जिनमें से 112 पुलिस चौकियां स्थाई व 31 अस्थाई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 31 अस्थाई चौकियां खोली गई हैं, यहां पर संशय यह रहता है कि यहां पर समयानुसार कभी बटालियन से या कभी कहीं और से कर्मचारियों को भेजा जाता है। ये जहां भी खुली हैं, ज़रूरत के अनुसार ही इनको खोला गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और आश्वासन भी चाहता हूं कि क्या सरकार यहां पर स्थाई तौर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने जा रही है क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही ये सरकार द्वारा खोली गई हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को पढ़कर सुनाया कि प्रदेश में कुल 143 पुलिस चौकियां हैं जिनमें से 112 पुलिस चौकियां स्थाई व 31 अस्थाई हैं। यह बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि पुलिस चौकी या थाने को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो यह देखा जाता है कि ज़रूरत कितनी है, क्राइम रेट कितना है, एरिया कितना है और उसके साथ-साथ अगर ऐसा अनुभव किया जाता है कि यहां ज़रूरत है तो समय-समय पर पुलिस चौकियां खोली जाती हैं। कई स्थानों पर जहां अस्थाई रूप से खोली जाती हैं, ज़रूरत के मुताबिक उनका संचालन किया जाता है। जब सरकार को लगता है कि अब यहां पर स्थाई रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी तो स्थाई रूप से भी व्यवस्था की जाती है।

जहां तक माननीय सदस्य ज़िक्र कर रहे हैं कि जो अस्थाई पुलिस चौकियां हैं, वहां पर व्यवस्था स्थाई नहीं है, एक एडहॉक सिस्टम वहां पर रहता है कभी कहीं से तो कभी कहीं से वहां पर पुलिस कर्मचारियों को भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, अस्थाई पुलिस चौकी के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मोटे तौर पर इस व्यवस्था को समय-समय पर पुलिस विभाग मॉनिटर करता है और वहां पर ज़रूरत के मुताबिक पोस्टिंग दी जाती है। जब अनुभव किया जाता है कि उससे

140320221430/केएस/एएस/2

ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं और जगह ज़रूरत है तो कई बार उसमें थोड़ी कमी भी की जाती है। इस व्यवस्था को जिला के एस.पी. मोनिटर करते हैं । अस्थाई पुलिस चौकी खोलने के लिए वे ही सक्षम होते हैं। अस्थाई और स्थाई पुलिस चौकी में भिन्नता यह है कि स्थाई पुलिस चौकी सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है और पद एवं वाहन स्वीकृत किए जाते हैं। यानि गवर्नमैंट की ओर से उसको नोटिफाई करने के साथ-साथ वहां पद सृजित किए जाते हैं ताकि वहां पर स्थाई व्यवस्था की जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि कामकाज की दृष्टि से अस्थाई और स्थाई पुलिस चौकी में बड़ा अंतर नहीं है। काम उसका भी वही है।

श्रीमती अव द्वारा जारी---

13.03.2022/1435/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 5117 --------- क्रमागत

मुख्य मंत्री ---- जारी

में बड़ा अंतर नहीं है, काम दोनों जगह लगभग एक जैसा ही होता है। स्थाई चौकियों के लिए केवल एस्टेब्लिशमैंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पॉवर को स्थाई रूप से रखने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन होती है। अस्थाई चौकियों के लिए व्यवस्था थोड़ी अस्थाई रहती है, मगर नेचर ऑफ वर्क में कोई अंतर नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले

कल ही हमीरपुर के बड़सर विधान सभा क्षेत्र में गया था। वहां पर पुलिस चौकियों को स्थाई करने की मांग आई थी। मैंने जब उनके पैरामीटर्ज के बारे में पता किया तो बताया गया कि इसकी वहां पर जरूरत है। वहां पर बढ़ते क्राइम के साथ-साथ उस क्षेत्र की जियोग्राफिकल कंडिशन को देखते हुए मैंने कल वहां पर दोनों पुलिस चौकियों को स्थाई रूप देने की घोषणा की है। **इसके अलावा भी यदि कहीं किसी को ऐसा लगता है तो उसका परीक्षण और निरीक्षण करने के उपरांत उसको स्थाई करने की दिशा में जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी; अवश्य उठाएंगे।**

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डहर की पुलिस चौकी भी अस्थाई है और उस चौकी के अंतर्गत बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त्, उसके साथ बिलासपुर जिला भी लगता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हमारी डहर की चौकी को भी स्थाई किया जा रहा है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डहर में भी अस्थाई पुलिस चौकी है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि उसके साथ बोर्डर एरिया भी लगता है तो वह बिलासपुर जिला का लगता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वह थोड़ा आइसोलेटिड एरिया है और डहर सुन्दरनगर से काफी दूर भी पड़ता है। वैसे भी, डहर पुलिस चौकी को अस्थाई से स्थाई में परिवर्तित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की दृष्टि से इन चौकियों को खोलने के लिए मापदण्ड बनाए गए हैं। **यह मामला विचाराधीन है और इसको एग्ज़ामिन करने के उपरांत कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।**

प्रश्न समाप्त

13.03.2022/1435/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 5118

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संदर्भ में प्राप्त उत्तर में यह स्पष्ट नहीं है कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु फण्ड्स का प्रावधान शुरू कर दिया है या नहीं। यदि हां, तो उसका क्या स्टेटस है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही दो-

दो सीमेंट उद्योग स्थापित होने के कारण वहां पोल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए आज हमें वहां इस प्रकार की बसें चलाने की बहुत जरूरत है। इसके अतिरिक्त, बहुत सारे रूट्स ईकोनॉमिकल वाएबल न होने के कारण भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रति किलोमीटर कॉस्ट ज्यादा आती है। जबकि इलेक्ट्रिक बसिज ईकोनॉमिकल वायेबल होती हैं इसलिए उन रूट्स पर ये बसिज बेहतर साबित हो सकती हैं। लेकिन इस उत्तर में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार ने इस विषय के संदर्भ में कहां तक विचार किया है और हमारे स्थानीय लोगों को इन बसिज की सुविधा कब तक मिलेंगी?

मंत्री टी **सी द्वारा जारी**

14/03/2022/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्याः 5118 .. क्रमागत्

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जहां भी इलैक्ट्रिकल बसिज चलाईं जाएंगी, वहां पर उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना पड़ेगा और उनके लिए चार्जिंग स्टेशन और शैड बनाने पड़ेंगे। इलैक्ट्रिकल बसिज बाकी बसों के तुलना में महंगी होती है लेकिन सरकार सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की बसिज चलाने का प्रयास कर रही हैं। माननीय सदस्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी इस प्रकार की इलैक्ट्रिकल बसिज चलाई जाएंगी लेकिन उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और उस पर सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है। हमने शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए इस प्रकार की बसें लेनी शुरू कर दी हैं और इनको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नई इलैक्ट्रिकल बसें लेने का कार्य प्रारम्भिक अवस्था में चल रहा है और निश्चित तौर पर आपके विधान सभा क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

प्रश्न समाप्त।

14/03/2022/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

प्रश्न संख्याः 5119

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि डैहर की जो-जो जरूरतें थीं उनको आपने पूरा किया है। चाहे वह सिविल हॉस्पिटल की बात हो, 12 करोड़ रुपये आई0टी0आई0 के लिए या 25 करोड़ रुपये की पीने के पानी की योजना हो। इसके अलावा आपने डैहर में लोक निर्माण भवन व अटल आदर्श विद्यालय भी प्रदान किया है। डैहर मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का केन्द्र है और वहां पार्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए जमीन चयनित कर ली गई है और जब आप प्रवास पर आए थे तो आपने इसकी घोषणा भी की थी। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पार्किंग के लिए शीघ्रातिशीघ्र धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डैहर सुन्दरनगर का एक खूबसूरत इलाका है जो अब बहुत तेजी के साथ विकसित होता जा रहा है। वहां पर विभिन्न संस्थान खुल चुके हैं। माननीय सदस्य ने वहां के लिए जो मांग की, हमारी सरकार ने उनको पूरा किया है। डैहर विकसित होता जा रहा है और वहां जनसंख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसके कारण वहां की जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। मैंने वर्ष 2021 में वहां पार्किंग की घोषणा की थी। इसके लिए जमीन का इंतजाम हो चुका है और अब लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी ड्राइंग बनाई जा रही है। जैसे ही इसकी ड्राइंग और एस्टिमेट बन जाएगा, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी और इस पार्किंग का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ताकि वहां के लोगों की जो पार्किंग की समस्या है, उसका समाधान हो सकें।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

14-03-2022/1445/NS/HK/1

प्रश्न संख्या : 5119 .....क्रमागत

मुख्य मंत्री .....जारी

आज की तारीख में हम अनुभव कर रहे हैं कि शहरों में ही पार्किंग की जरूरत नहीं बल्कि गांवों भी इतने बड़े होते जा रहे हैं कि वहां पर पार्किंग आवश्यक हो गई है। मैं अलग-अलग अवसर पर अलग जगहों पर जाता हूं तो इन सब बातों को विशेष आग्रह के साथ कहने की कोशिश करता हूं कि जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए अपनी पंचायत के अंतर्गत जहां बड़े गांव हैं वहां पर जितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं लोग साधन और सुविधाओं की दृष्टि से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आर्थिकी मजबूत होती जा रही है और हर घर में गाड़ियां आती जा रही हैं इसलिए पार्किंग की व्यवस्था भी उसी अनुरूप की जाए। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पंचायत प्रधानों के साथ इस बात का आग्रह किया है ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

प्रश्न संख्या : 5120

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) : उपस्थित नहीं।

14-03-2022/1445/NS/HK/2

प्रश्न संख्या : 5121

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बन्जार बस स्टैंड के लिए जो पार्किंग बननी थी उसके लिए बजट का प्रावधान होने के बाद काम भी शुरू हो गया है और बन्जार बस स्टैंड में मरम्मत का काम भी शुरू होना था वह भी शुरू हो गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो और बस स्टैंड बनने हैं। एक सैंज और दूसरा बालीचौकी में बनना है। इन दोनों स्थानों की वन विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और एफ0सी0ए0 का फाइनल अप्रूवल आना शेष है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आने वाले समय में इन दोनों बस स्टैंड के लिए डी0पी0आर0 और निर्माण के लिए धनराशि दें ताकि हम इनका जल्दी फाउंडेशन स्टोन रख सकें और जैसे ही फाइनल अप्रूवल आती है तो हम इन दोनों बस स्टैंड का शिलान्यास कर सकें। क्या आप इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल बन्जार बस अड्डे के निर्माण, रख-रखाव व मरम्मत हेतु धनराशि और पार्किंग के निर्माण के विषय में प्रश्न किया था तो इसकी

सारी सूचना इनको उपलब्ध करवा दी है। इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवा दी है और ठेकेदार ने काम भी पूरा कर दिया है। केवल एक ही स्थान ऐसा जहां काम चल रहा है और दिसम्बर, 2022 तक काम पूरा करने के लिए कहा है। माननीय सदस्य ने जो दो बस अड्डों सैंज और बालीचौकी के बारे में कहा है। ये अपने आप से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इनमें एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस फाइनल स्टेज में है**। जब क्लीयरैंस हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पर फंड की व्यवस्था भी की जाएगी और वहां पर जो जरूरत होगी उसका पूरा इंतजाम किया जाएगा।**

14-03-2022/1445/NS/HK/3

प्रश्न संख्या : 5122

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है मुझे लगता है कि यह अधूरी सूचना है। इस सूचना का एक हिस्सा गायब कर दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि विभाग ने जो उत्तर भेजा है वह पूर्ण नहीं है। इसके बारे में क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एम0ओ0यू0 साइन हो गया था? एम0ओ0यू0 के अनुसार 50:50 प्रतिशत दोनों सरकारों का खर्च होगा। यह एम0ओ0यू0 श्री आनन्दपुर साहिब से श्री नैना देवी शक्ति पीठ तक रोपवे बनाने का साइन हुआ था। अध्यक्ष महोदय, दोनों सरकारों के बीच में

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1450/RKS/एच के-1

प्रश्न संख्याः 5122.. जारी

श्री राम लाल ठाकुर ... जारी

जब एम.ओ.यू. साइन हुआ तो उसके अनुसार आनंदपुर से नैना देवीजी शक्तिपीठ तक रोपवे बनाया जाना प्रस्तावित था। बिलासपुर के टोबा गांव से नैना देवीजी के लिए रोपवे बनाने हेतु जमीन एक्वायर की गई। उस वक्त मैंने व स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि यह रोपवे हिमाचल में स्थापित किया जाना है तो पंजाब सरकार से 50 प्रतिशत हिस्सा क्यों

लिया जा रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी यह बात स्पष्ट नहीं हुई। एम.ओ.यू. के बाद सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस रोपवे को शामिल किया। इस कार्य हेतु दिनांक 04.03.2020 को बिड्स मंगवाने बारे समाचार पत्रों में NIT जारी किया गया था। इस NIT में 6 बार संशोधन करके शुद्धिपत्र जारी किए गए। दिनांक 03.04.2019 को एक Joint Venture Special Purpose Vehicle (SPV) Company गठित की गई। इस कंपनी में चेयरमैन, पर्यटन विभाग, पंजाब के तथा मैनेजिंग डायरैक्टर, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सचिव नामित किए गए। इस कंपनी में चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज, पंजाब सरकार के व चार ही हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित किए गए। इतने डायरेक्टर्ज बनाने के बावजूद भी वहां पर बिड करने वाला कोई नहीं आ रहा है। आपकी सरकार का थोड़ा-सा समय बचा है लेकिन आज तक आपने इस निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कोई पग नहीं उठाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि अधूरी सूचना देने के क्या कारण हैं और नैना देवीजी तक रोपवे का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुरूप प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। यह बात अलग है कि इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन हम मन के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मन की बात हर माह के अंतिम रविवार को आती है और उस समय आप मन की बात सुन सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न

14.03.2022/1450/RKS/एच के-2

पूछा है उसके बारे में हमने विस्तार से उत्तर दे दिया है। हम यह भी कह रहे हैं कि टेंडर अवार्ड होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्ष 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय भी इस रोपवे के लिए एम.ओ.यू. साइन हुआ था। ...व्यवधान... आपने उसके बारे में नहीं पूछा है। वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आनंदपुर साहिब से जो नैना देवीजी

तक रोपवे बन रहा है, यह दो अलग-अलग धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। आनंदपुर साहिब सिक्खों की आस्था का केंद्र है और श्री नैना देवीजी हिन्दुओं की श्रद्धा का केंद्र है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1455/बी.एस./वाई0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

हमारे सिक्खों की आस्था का केन्द्र है, और हमारी नैनादेवी जी, हमारी आस्था का केन्द्र है। पंजाब से और इसके साथ लगते क्षेत्रों से लाखों की तादात पर श्रद्धालु वहां पर आते हैं। आपको याद होगा कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि एक बार बहुत बड़ी घटना भी वहां पर घटी थी। वहां आने-जाने की व्यवस्था आसान हो, सहज हो और अच्छी सुविधा हो, इसके अलावा यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा केन्द्र डवल्प हो सकता है। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े थे, माननीय सदस्य जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इनके मन में भाव था कि ये आनन्दपुर साहब से शुरू न हो करके बिलासपुर के अन्तर्गत जो टोबा गांव हैं, वहां से शुरू किया जाए। इस बात को ले करके माननीय सदस्य ने पूर्व सरकार में बड़े जोर से आग्रह भी किया था और अंतत्तोगत्वा अगस्त, 2013 में कांग्रेस सरकार ने उस एम0ओ0यू0 को रद्द कर दिया। उसके बाद 27 दिसम्बर, 2017 को हमारी सरकार बनी थी, उसके बाद फिर से आग्रह आया और हमारा जो विजन डाक्यूमेंट है, उसमें हमने कहा भी है कि हम इसे करेंगे। उसमें हमने आगे बढ़ करके काम भी किया है। हमने इच्छा जाहिर की और पंजाब के मुख्य मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और उसके बाद उन्होंने मुझे व्यक्तिग तौर पर भी फोन किया और कहा कि मेरी भी इच्छा है और मैं इसे करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा करें और हम इसका एम0ओ0यू0 नए तरीके से बनाएंगे और फिर इसे शुरू करेंगे। उसके बाद इस दिशा में हम आगे बढ़े। जो एम0ओ0यू0 साइन किया गया है, वह 28.09.2018 को किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से चण्डीगढ़ गया था और एम0ओ0यू0 के प्रोसेस को पूरा किया। जब इसमें आगे काम करने की बात आई, इसमें 3.8 किलोमीटर कुल लम्बाई है। जैसे ही इसके टैंडर प्रक्रिया आगे बढ़ी

तो इसमें कुछ इश्यूज आए, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि वी0जी0एफ0 के लिए आग्रह आया और हमने उस अनुरूप इसमें निर्णय नहीं लिया। क्योंकि वी0पी0एफ0 तो वहां दिया जाता है जहां वाइविलिटी उस प्रोजैक्ट मैं न हो। हमें इसमें कोई शंका नहीं थी, क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पर्यटक भी वहां आते हैं। इसलिए हमें लगा कि

14.03.2022/1455/बी.एस./वाई0के0/-2

उसमें इस तरह की आवश्यकता नहीं है। जो एम0ओ0यू0 साइन हुआ, उसके बाद आगे बढ़ करके 03.04.2019 को एक Joint Venture Special Purpose Vehicle (SPV) company गठित की गई, और इसके चेयर मैंन और मेनेजिंग डायरेक्टर, पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशानिक सचिव नामित किए गए और इस कंपनी में चार बोर्ड ऑफ डारेक्टर, पंजाब सरकार के और चार ही हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित किए गए। इस तरह से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यह बात सत्य है कि बार-बार टैंडर करने के बाद उसमें अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो हमने एम0ओ0यू0 साइन किया है, उसे पूरा किया जाना चाहिए, अब इसमें जो टैक्निकल एडवाइजर हैं उनको हमने सोचा है कि उन्हें चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जो चीजें व्यावहारिक रूप से की जा सकती हैं। जिसके लिए कोई ठेकेदार या कंपनी इसकी बिडिंग में आगे आ सके और बिडिंग में हिस्सा ले करके इस प्रोजैक्ट को हम शुरू कर सकें।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1500/वाई.के.-एन.जी. /1

प्रश्न संख्या - 5122.....जारी

मुख्य मंत्री जारी.....

यह हमारी इच्छा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि केन्द्र सरकार ने एक बेहतरीन शुरूआत की है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का भी सुझाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे इलाके जहां पर सड़क पहुंचाने में कठनाई होती है और वहां पर पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है व वहां पर सड़क निर्माण के लिए खर्च भी बहुत अधिक होता है, उस दृष्टि से केन्द्र सरकार का जो हाल ही में बजट आया है उसमें 'पर्वत माला' के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। मैं समझता हूं कि इस योजना के अंतर्गत भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि बहुत लम्बा समय निकल गया है और अभी तक इसका काम भी शुरू नहीं हुआ है तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा लग रहा है कि यह काम शुरू हो जाना चहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इसे अलग से मोनिटर करेंगे व टेकनिकल एडवाइज़र को बदलने और टैंडर की बीड कंडीशन को ठीक करने की जो बात है तो हम उसे करेंगे ताकि व्यवहारिक रूप से इसमें कोई कम्पनी या ठेकेदार आकर कार्य शुरू कर सके और श्री नैना देवी जी का स्थान एक पवित्र स्थान है तथा वहां पर लोगों की आवजाही सरल व सहज हो सके।

प्रश्न काल समाप्त।

14-03-2022/1500/वाई.के.-एन.जी. /2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय सदन को सोमवार, 14 मार्च, 2022 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को सोमवार, 14 मार्च, 2022 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार है :-

सोमवार, 14 मार्च, 2022 1. शासकीय/विधायी कार्य।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 मांगों

पर चर्चा एवं मतदान।

मंगलवार, 15 मार्च, 2022 1. शासकीय/विधायी कार्य।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 :

(i) मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(ii) विनियोग विधेयक -पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

14-03-2022/1500/वाई.के.-एन.जी. /3

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माननीय सदन में वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री जी इस माननीय सदन में अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को यूक्रेन में फंसे हिमाचलवासियों से सम्बंधित नवीनतम जानकारी से अवगत करवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों के संदर्भ में मैं बार-बार इस माननीय सदन को अवगत करवाता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का हरेक छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया था वह वहां पर सुरक्षित हो और वहां से सुरक्षित भारत में वापिस आ सके इसके लिए प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार ने लगातार आपस में समन्वय के साथ काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के सभी छात्र व अन्य व्यक्ति युक्रेन से सुरक्षित व सकुशल निकल आए हैं। अब कोई भी हिमाचलवासी युक्रेन में नहीं है। युक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सकुशल वापिसी के लिए पूर्ण संवेदनशीलता से केन्द्र सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया। यूक्रेन का एयरस्पेस बंद होने के कारण पड़ोसी देशों में चार केन्द्रीय मंत्रियों को विशेषरूप से तैनात किया। युक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती देशों से विशेष उड़ान के माध्यम से 'ऑप्रेशन गंगा' के तहत वापिस लाया गया तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक की सकुशल वापिसी सुनिश्चित की गई। मैं इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार

व्यक्त करता हूं। दिल्ली अथवा मुम्बई पहुंचने पर प्रदेशवासियों को वापिस उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यूक्रेन की स्थिति एक वैश्विक संकट है और यह संकटकाल शीघ्र समाप्त हो ऐसी कामना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की ओर से जो प्रयत्न युक्रेन में फंसे हुए हमारे हिमाचल के बच्चे व लोगों के किए गए थे उसके संदर्भ में यहां मैंने जानकारी दी है। मुझे इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों से और केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से हम हरेक हिमाचलवासी को सुरक्षित वापिस अपने घर तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

अगल वक्ता.....श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1505/JS/AG/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी इसमें प्वाईंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप बैठिये कार्यवाही पूरी होने दें।

14.03.2022/1505/JS/AG/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित के 44वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

14.03.2022/1505/JS/AG/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

i. समिति के 147वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और
ii. समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 91वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष माहोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2021-22), समिति का 43वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः31-जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2021-22),समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

14.03.2022/1505/JS/AG/4

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः30-विविध सामान्य सेवायें के अन्तर्गत भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्षः अब श्री हीरा लाल,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः 28- शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह वर्मा,सभापति, ग्रामीण विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः14- पशुपालन विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

14.03.2022/1505/JS/AG/5

<u>विधायी कार्य</u> :

<u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब माननीय जल शक्ति मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

जल-शक्ति मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय जल शक्ति मंत्री हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करेंगे।

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित हुआ।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

14.03.2022/1510/SS-AG/1

अध्यक्ष महोदय क्रमागतः

अब माननीय शहरी विकास मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मन्त्री हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

शहरी विकास मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

14.03.2022/1510/SS-AG/2

श्री राकेश सिंघा जी, आप एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा द्वारा बजट सत्र का समापन कल होगा और इस सुअवसर पर आज दिनांक 14.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्री, मंत्रिगणों एवं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन समय ठीक 7.15 बजे होटल पीटरहॉफ में किया गया है। अतः आप सभी को निमंत्रण है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

माननीय सदस्य डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

14.03.2022/1510/SS-AG/3

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल (सोलन) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज आपका शुभ जन्मदिन है उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। परमात्मा करे कि आप दीर्घ आयु हों और स्वस्थ आनंदमय जीवन जिएं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास दो वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ऑनलाइन किए गए थे। ये सब विधायक प्राथमिकता की योजनाएं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। परन्तु पिछले दिनों उन्हीं उद्घाटनों व शिलान्यास पट्टिकाओं का एक बार फिर से स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया और हैरानी की

बात है कि ऐसे सदस्यों ने लोगों को बुलाकर किया जोकि स्वयं चुनाव हारे हुए थे। एक धाम का इंतजाम करके, कार्ड बांटकर, एक प्रकार से फुलफ्लैज फंक्शन का आयोजन किया गया और वे भी प्रत्याशी ऐसे थे जो चुनाव में स्वयं हारे हुए थे। मेरा मानना है कि ये सब काम संविधान और लोकतंत्र के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों के ध्यानार्थ इस विषय को लाना चाहता हूं। इससे जनता में व्यापक आक्रोश और शांति भंग होने का भी अंदेशा होता है because it is not appreciated. अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व जनता में उकसाने वाले कार्यों पर अविलम्ब रोक लगाई जाए, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री श्रीमती के0एस0 द्वारा

14.03.2022/1515/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। हमारे वरिष्ठ सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल जी ने बात कही है तो हो सकता है कि जो इन्होंने कहा वह सत्य हो। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाओं में हम कई बार शिलान्यास कर देते हैं और उसके पश्चात् किसी वजह से, टैक्निकल चीजों के कारण वहां पर काम की शुरूआत नहीं हो पाती। जब विलम्ब होता है, उसमें ऐसी स्थिति होती है कि शिलान्यास तो नहीं, शिलान्यास तो एक ही बार होगा, बार-बार नहीं होगा लेकिन भूमि पूजन का कार्य करने की व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से नहीं, आपकी ही तरफ से शुरू हुई थी। हमने जितने भी शिलान्यास किए हुए थे, जहां-जहां कार्य शुरू नहीं हुआ था, आपकी सरकार द्वारा वहां पर भूमि पूजन किया गया। नारियल फोड़ने का इन्तज़ाम किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि शायद वहां पर कोई स्टोन नहीं लगा होगा। हमारे तो शिलान्यास करने के बाद कई जगह पर आपके समय में भूमि पूजन का फट्टा लगा दिया जाता था। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को ले कर, हम भी कहेंगे कि भूमि पूजन करो लेकिन फट्टा न लगाएं, ऐसा आदेश हम ज़रूर करेंगे। माननीय सदस्य जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, शांडिल जी आपके लिए तो बहुत ही विकट परिस्थिति है कि आपका मुकाबला ही वहां पर अपने दामाद के साथ हुआ है। जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि वे

हारे हुए हैं, उनके प्रति तो कम से कम आपकी संवेदना होनी ही चाहिए क्योंकि दामाद बेटे के बराबर होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दोबारा शिलान्यास की जगह फिर पट्टिका न लगे, भूमि पूजन की प्रक्रिया करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की चीजें न हों ताकि आपकी भावना को ठेस न पहुंचे।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः अध्यक्ष महोदय, पट्टिका लगाने के भेष में फुलफ्लैज्ड बना देते हैं। एक प्रकार से ऐसा लिख देते हैं कि यह कार्यक्रम आज ही बन रहा है, सब लोग आ जाएं तो लोग भ्रमित से हो जाते हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मैंने यह प्वाइंट उठाया है। धन्यवाद

14.03.2022/1515/केएस/एएस/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में इस प्रश्न को ले कर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रख रहा हूं कि आज दो बिल इंट्रोड्यूस किए गए और इनकी कॉपी जिस दिन ये स्थगित किया गया था, रात को आई जब बहुत से लोग घर चले गए थे। मैं भी चला गया था। एक बिल बहुत इम्पोर्टेंट है जो माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें हमने पहले ऑर्डिनेंस लाया। जिसमें हम ऑर्डिनेंस लाते हैं अध्यक्ष महोदय, आपसे भी विनती है, आप इस सदन के कस्टोडियन हैं। It is not one line amendment. It is very deeper. इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए ऐसे बिलों को आप समय पर लाएं जिसमें आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं ताकि सदन में खुलकर चर्चा हो, यह मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। नियम भी यह कहते हैं कि at least seven days. Unless आप अनुमति दे दें और मौका मिलना चाहिए। आज शाम तक हमने अमैंडमैंट देनी है। अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

13.03.2022/1520/av/as/1

श्री राकेश सिंघा---- जारी

थोड़ा एप्लिकेशन ऑफ माईंड करना है। उसके बाद ही हम उस पर कुछ सुझाव दे सकेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ व्यवस्था दें।

13.03.2022/1520/av/as/2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय श्री जगत सिंह नेगी, आप बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। हमारी विधान सभा के साथ जो 7 मंजिला पुस्तकालय भवन बना हुआ है उसमें रोज़ाना लगभग 500 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मगर वहां पानी और स्वीपर आदि की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त, वहां पर लिफ्ट तो शुरू ही नहीं हुई क्योंकि उसके लिए जो दो साल पहले ट्रांसफॉर्मर लगना था; वह अभी तक नहीं लगा है। आप जानते हैं कि इस वर्ष भी दो महीने से ज्यादा कोविड महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी अव्यवस्थित रही। वहां पर बच्चे सीट लेने के लिए सुबह 06 बजे पहुंच कर लाइन में खड़े हो जाते हैं जबकि वह पुस्तकालय 08.30 बजे(पूर्वाह्न) खुलता है। उसके पश्चात शाम को भी 06 बजे उसको बंद कर दिया जाता है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इसको 24X7 खुला रखिए। वहां अगर शिक्षा विभाग के लोग नियुक्त नहीं है तो उसमें होम गाड्र्स या पुलिस विभाग के लोग लगाइए। अगर उनको लगाना भी मुश्किल हैं तो चार व्यक्ति सेना से ले लें। वहां पर एक पार्ट टाइम स्वीपर रखा हुआ है जो दिन में केवल दो घंटे के लिए आता है जबकि एक दिन में वहां लगभग 500 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं वहां की इस प्रकार की अव्यवस्था खुद देख कर आया हूं। आप वहां के इस प्रकार के हालात को ठीक कीजिए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस नये पुस्तकालय को शुरू किए हुए दो वर्ष का ही समय हुआ है। इसका अच्छा भवन बना है और स्पेस की उपलब्धता के अनुसार वहां सभी सुविधाएं देने का प्रयत्न किया गया है। मगर उसके बावजूद भी वह स्पेस कम पड़ रहा है। इस बारे में कुछ बच्चे हमें भी दो-तीन बार मिले हैं। वहां जगह कम पड़ जाती है इसलिए बच्चों को काफी समय पहले आकर सीट के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। हमें मालूम है कि वहां पर इस प्रकार की कठिनाई है। इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में शिमला में पुस्तकालय खोलने हेतु हमें कहीं और स्थान मिल जाए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। इसके

13.03.2022/1520/av/as/3

अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी के तहत भी शिमला में 4-5 अलग-अलग स्थानों पर बुक कैफे बनाने का प्रस्ताव है परंतु उसमें अभी समय लगेगा। मैं मानता हूं कि बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा कि इस पुस्तकालय को 24X7 खुला रखा जाए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इसको मोनिटर करने के लिए मैकेनिज्म डवलप करके मैन पॉवर प्लान करना पड़ेगा। **अभी हम एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि यह हो जाएगा मगर सारी चीजों को एग्ज़ामिन करके इस बारे में विचार किया जाएगा। अब सर्दी का मौसम निकल गया है और गर्मी के मौसम में बच्चे ज्यादा देर बैठ सकते हैं, इसलिए हमें यदि व्यावहारिक लगेगा तो इस बारे में अवश्य विचार किया जाएगा।**

13.03.2022/1520/av/as/4

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। आज दिनांक 11.3.2022 को प्रस्तुत मांग संख्या 7-

पुलिस व संबंद्ध संगठन पर आगे चर्चा होगी। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नन्द लाल हिस्सा लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 मार्च, 2022 को जो यहां पर कटौती प्रस्ताव आए हैं, उस पर हमारा वक्तव्य लगभग पूरा हो चुका था। उसको केवल कंक्लूड करना बाकी था

टी सी द्वारा जारी

14/03/2022/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री नन्द लाल, रामपुर : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 मार्च, 2022 को जो कटौती प्रस्ताव यहां पर लाया गया था उस पर मेरा वक्तव्य लगभग पूरा हो चुका था, उसको कन्कलूड करना शेष रह गया था। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 'पटाखा कांड' और 'लिकर कांड' सामने आए जिसके बारे में पुलिस को पता तक भी नहीं था। इस तरह से पता नहीं और कितने अवैध धंधे चल रहे होंगे? क्या इसके लिए किसी को जिम्मेवारी ठहराया गया है? क्या लोकल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनके क्षेत्राधिकार में क्या चल रहा है? सरकार को अभी तक इस पर इनिशिएट लेकर के एक्शन लेना चाहिए था। मेरा यह सुझाव है कि आपका जो इंटैलीजेंस इनपुट है उसको बढ़ाया जाए। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है so you are just sitting like dumb. इसलिए आपको खुफ़िया तंत्र को बढ़ाना चाहिए ताकि जो इस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पहले से खबर रहे। पुलिस विभाग में complacency और indiscipline को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं अपने एरिया की बात करना चाहूंगा। झाकड़ी में पहले एक डी0एस0पी0 बैठते थे। वहां पर जो एस0जे0वी0एन0एल0 का प्रोजैक्ट है, उसमें बाहर से बहुत-ज्यादा लोग आ गए इसलिए वहां पर एक डी0एस0पी0 अलग से लगाया गया था

लेकिन कुछ सालों के बाद उनको हटा दिया गया। मेरा आग्रह रहेगा कि बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए वहां पर पुनः डी0एस0पी0 को लगाया जाए। खोलीघाट एरिया नशे का गढ़ बनता जा रहा है। इसके अलावा ब्रौ, जगातखाना और गौरा इत्यादि एरिया में भी नशे का धंधा चल रहा है। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि खोलीघाट और गोपालपुर में दो पोस्टें खोली जाएं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 12 स्थायी और 31 अस्थायी पोस्टें हैं। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि अगर अस्थायी पोस्टें खोली गईं हैं तो इनका कोई कारण रहा होगा। इन अस्थायी पोस्टों को जब स्थायी करना होता है तो इनके लिए सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि गलत कार्य करने वाले लोग

14/03/2022/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

खत्म हो गए और आप अस्थायी पोस्टों को बंद कर दें। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र से जो दो पोस्टों का केस पुलिस मुख्यालय में आया है, उस पर भी विचार करें। ब्रौ और जगातखाना एरिया निरमंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है जोकि वहां से बहुत दूर है। इनको डी0एस0पी0 रामपुर के अंडर रखा जाए। इससे वहां क्राइम और नशे पर भी चैक रहेगा। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह रायजादा जी भाग लेंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

14-03-2022/1530/NS/DC/1

श्री सतपाल सिंह रायजादा, ऊना : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'पुलिस और सम्बद्ध संगठन' कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई है और सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने किस

प्रकार से पुलिस की भर्तियों में बैकडोर एंटरी की शुरूआत की तथा इसमें जो अनियमितताएं बरती गईं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाजपा सरकार ने एस0पी0 के द्वारा किस प्रकार से धांधली की, मैं यह बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में पुलिस भर्ती में एक लड़का मेरिट में तीसरे स्थान पर था। एस0पी0 साहब ने जो कमेटी गठित की और मैं बताना चाहूंगा कि उस कमेटी ने इस लड़के को किस तरीके से बाहर निकाला और इंटरव्यू के बहाने से अपने लोगों की किस तरीके से एड्जस्टमैंट की? इस इंटरव्यू के लिए राज्पाल महोदय से स्पेशल परमिशन ली गई थी। इंटरव्यू के बहाने जिस लड़के के 62 नम्बर थे और कमेटी में तीन जजों द्वारा 5,5,5 नम्बर दिए तथा उस लड़के के 62 नम्बर होने के बावजूद वह सबसे नीचे चला गया। जिनके 58 नम्बर थे उनको 9 व 10,10 नम्बर देकर ऊपर कर दिया गया। दूसरे लड़के जिनके 58 नम्बर या इससे कम थे उनको कैसे नौकरी दी गई इसका मेरे पास पूरा डाटा है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। उसके नीचे जितने भी उम्मीदवार हैं उनको 8,9 व 10 नम्बर और कुछ को तो तीनों जजों द्वारा 10,10,10 नम्बर दे दिए गए क्योंकि तीन जज होते हैं तो 3 से डिवाइड होता है। उस लड़के को तीनों जजों ने 5,5,5 नम्बर दिए तो उसके 5 ही नम्बर बने। इस लड़के के साथ जिस तरीके से धांधली की गई यह पुलिस विभाग में एस0पी0 द्वारा की गई और यह शर्मनाक बात है। यह गठित कमेटी द्वारा किया गया यह बहुत बड़ा दोष है। यह इसलिए किया गया क्योंकि उस बच्चे के पिता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया यह बहुत शर्मनाक है। कोई भी विचारधारा हो सकती है और कल किसी की भी सरकार हो सकती है लेकिन इस तरीके से किसी बच्चे के साथ करना बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास यह सारा डाटा उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, जब आर0टी0आई0 के तहत बार-बार जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी तो एक बार उस लड़के ने आर0टी0आई0 लेने के लिए 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया तो उसको दोबारा पत्र आया कि आप 50 रुपये की जगह 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएं तभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आर0टी0आई0 की

14-03-2022/1530/NS/DC/2

इन्फॉर्मेशन लेट की गई। इस पुलिस भर्ती में राज्यपाल महोदय से स्पेशल परमिशन ली गई ताकि एडिशनल नम्बर दिए जा सकें। इसमें एक लड़के के 58 नम्बर हैं और उसको इंटरव्यू में 9.67 नम्बर दिए तथा कुल नम्बर 67.67 बने। एक लड़का अनूप सिंह नाम का है उसके

58 नम्बर थे और इंटरव्यू के 9.67 नम्बर जुड़े तो 67.67 बन गए। अध्यक्ष महोदय, एक लड़का शुभम है उसके भी 58 नम्बर थे इंटरव्यू में 9.67 नम्बर दिए गए और कुल मिला करके 67.67 नम्बर हो गए तथा जिसके 62 नम्बर थे उसको इंटरव्यू में 5 नम्बर देकर 67 नम्बर कर दिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी धांधली की गई यह बहुत शर्मनाक है। मैं बोलना चाहूंगा कि सितारे कोई भी हों किसी बच्चे के भविष्य के साथ ऐसे खेलना गलत है। मैं यह नहीं बोलता हूं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1535/RKS/एच के-1

श्री सतपाल सिंह रायजादा... जारी

हो सकता है कि हमारी सरकार के समय में भी ऐसी अनियमितताएं बरती गई हों लेकिन मेरा मकसद यही है कि किसी बच्चे के साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके अभिभावक किसी भी विचारधारा के हों लेकिन बच्चे के साथ इस तरह का भेदभाव करना शोभनीय नहीं है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से ऊना में माफियाराज ने खूब जोर पकड़ा है। हमने इसकी रोकथाम के लिए काफी धरना-प्रदर्शन किए और कई बार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से भी मिले। लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर सरकार को खनन से आमदनी हो रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऊना में 1600 करोड़ रुपये से निर्मित स्वां चैनेलाइजेशन को तोड़कर जिस तरीके से खनन किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। हमने बार-बार खनन को रोकने की कोशिश की। एक बार मैं खनन माफियाओं को चैक करने के लिए स्वयं रात को 11.00 बजे वहां पहुंचा। उस समय 30-40 ट्रक सड़क पर लाइन में लगे हुए थे। मैंने वहां पर तैनात पुलिस वालों को बुलाया और उनसे पूछा कि रात को खनन कैसे हो रहा है? आपको मालूम होगा कि रात को खनन करना बिल्कुल बंद है। पुलिस वालों ने कहा कि इसके लिए उपायुक्त महोदय की तरफ से आदेश पारित हुए हैं ताकि दिन में

ट्रेफिक जाम से बचा जाए। मैंने उसी समय उपायुक्त महोदय को फोन लगाया। मैं उपायुक्त महोदय का धन्यवादी हूं कि उन्होंने रात के 11.00 बजे मेरा फोन उठाया। जब मैंने उन्हें इस विषय के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं निकाले हैं। हो सकता है कि खनन वालों ने इस तरह के ऑर्डर निकाले हों लेकिन इसकी सूचना मुझे नहीं मिली है। मैंने संबंधित खनन विभाग के अधिकारी को फोन लगाया लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने पुलिस वालों को कहा कि आप इन सभी ट्रक्स का चालान कीजिए। उसके बाद मैं वहां से वापिस आ गया। जब दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट मांगी तो उसमें सिर्फ दो ही ट्रकों का चालान किया गया था। अगर मैं इसको पुलिस प्रायोजित

14.03.2022/1535/RKS/एच के-2

खनन माफिया न कहूं तो और क्या कहूं? जब पुलिस के मुख्य अधिकारी वहां पर गए तो उनसे पत्रकारों ने अवैध खनन के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस के अधीन नहीं आता है और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जब पुलिस विभाग के मुखिया ने ही यह कह दिया तो उसके बाद खुब लूट हुई। एन.जी.टी. वालों ने भी खनन पर रोक लगाई है लेकिन आज भी वहां धड़ले से खनन हो रहा है। चाहे शराब माफिया हो, या ड्रग्स माफिया, इसको रोकने के लिए सिस्टम की बहुत कमी है। ऊना में जिस तरीके से एक अपाहिज व्यक्ति की दुकान को किसी रसूकदार व्यक्ति को दे दिया गया, वह देखने की चीज है। उस व्यक्ति को सारी एन.ओ.सीज. एक ही दिन में मिल गई। बाद में यह केस न्यायालय में गया। माननीय न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों ने एन.ओ.सीज. दी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन पांच महीने से अधिक का समय हो गया न उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई और न ही इस विषय पर कोई कमेटी गठित की गई। यदि कमेटी गठित की भी होगी तो उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कैसा प्रशासन है?

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1540/बी.एस./एच0के0/-1

श्री सतपाल सिंह रायजाता जारी...

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को तकरीबन पांच कहीने हो गए हैं, परंतु अभी तक न उनके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और न कोई कमेटी बनी है, यदि बनी भी है, तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कैसा प्रशासन है? मैं पुलिस को ले करके कुछ बातें कहना चाहता हूं, यदि पुलिस के पास आम व्यक्ति केस दर्ज करवाने जाता है तो वह केस दर्ज नहीं करती है। मेरे पास कई बार शिकायतें आई आठ-आठ महीने तक कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। मैं खुद भी जब थानें में जाता हूं तो उनसे कैमरा ऑन करवाता हूं, नहीं तो पता नहीं क्या आरोप लगा देंगे। मैं 4-5 फौजियों की बात बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आठ महीने हो गए हमारा केस दर्ज नहीं हो रहा है। जब वे एस0पी0 महोदय के पास गए, तो उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा, जब वे एस0एच0ओ0 के पास गए तो उन्होंने कहा कि यदि आप दोबारा आए तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। मुझे स्वयं वहां जाना पड़ा। मैंने उससे पहले वहां पर फोन भी किया और मैं कहा कि इसमें 420 का केस बनता है, मुझे कहने लगे कि आप खुद आ करके 420 का केस दर्ज कर दो। मैंने कहा कि मैं आपके पास खुद आता हूं, मैं पत्रकारों को ले करके वहां गया, तब जा करके उनका केस दर्ज किया गया। एडिशनल एस0पी0 ने वह इंक्वायरी की उसके बाद जो भी फैसला हुआ हो, परंतु केस तो दर्ज हुआ। इसके बाद एक केस और हुआ, वहां सनोली बाजार में शराब का ठेका है, , यह पंजाब के साथ लगता है, वहां पर कुछ लड़के रिवाल्वर ले करके गए और वहां पर एक लड़के को रिवाल्वर की हत्थी से पीटा गया और उनकी रिवाल्वर की मैग्जीन गिर गई। उस लड़के ने मैग्जिन ले करके थाने में रिपोर्ट करनी चाही लेकिन वहां पर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई। मैंने एस0पी0 महोदय से बात की तो उसके बाद केस दर्ज किया गया। परंतु कार्रवाई कोई नहीं हुई। जो व्यक्ति किसी-न-किसी तरह भाजपा संगठन से जुड़े हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह सब अच्छी बातें नहीं हैं, इसी तरीके से यदि हम उन्हें बचाते गए तो प्रदेश में अराजकता फैलेगी। ऐसे मैं पटाखों की फैक्टरी की बात करना चाहता हूं। महोदय, आपके हारे हुए लोग मंत्री बने हुए है वे आपसे ज्यादा चला रहे हैं। वहां पर दो पटाखों की फैक्टरी चलती

14.03.2022/1540/बी.एस./एच0के0/-2

रही और जब वहां पर विस्फोट हुआ, वहां पर कैसे माल आता रहा कैसे काम चलता रहा किसी को कोई पता पता नहीं। पुलिस सोई रही, अगर हमारे चीफ ऐसा बोलेंगे कि यह पुलिस के दायरे में नहीं आता तो पुलिस के नीचे के लोग आराम से बैठेंगे। क्या पुलिस के दायरे में यह आता है कि मोटर साइकिल का चालान करना है, यदि किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उसका चालान करना है? इस तरीके से पैसे इकट्ठे करने हैं। पुलिस का दायरा है क्या, हमें तो यह सुनने की जरूरत पड़ गई है।मैं पुलिस का विरोधी नहीं उनकी डइट का पैसा बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। यदि आप उनकी पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो वह इधर-उधर से निकालेंगे। मुझे गनमैंन नहीं दिया गया। मुझे विश्वास पात्र गनमैंन चाहिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1545/वाई.के.-एन.जी. /1

श्री सतपाल सिंह रायजादा जारी.....

हमने कहा कि उसने अपनी इंक्वायरी पूरी कर ली है और वह बिलकुल क्लीयर हो गया है लेकिन हमें वह गनमैन नहीं दिया गया। हमने जिनको हराया है उनके साथ 2-2, 3-3 गनमैन चले हुए हैं। सनौली नजारा में किसानों का प्रदर्शन चला हुआ था तो वहां पर उनकी रैली करवाने के लिए पूरी बटालियन गई हुई थी। ठीक है, यदि गनमैन नहीं देना है तो न दें, हमें गनमैन की कोई खास जरूरत भी नहीं है। इन बातों का तो चुनावों में ही पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की अनेक समस्याएं हैं उन्हें दूर करना चाहिए। पुलिस वालों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। उनकी डाइट मनी बहुत कम है जिसे बढ़ाना चाहिए। यदि उन्हें खाने के पैसे ही कम मिलेंगे तो वे इधर-उधर से ही खाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1962 से लेकर होम गार्ड के जवान पुलिस के

साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वह हर जगह पुलिस वालों का साथ देते हैं। जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो होम गार्ड का जवान सबसे पहले खड़ा मिलता है और मरीज को वह अंदर तक लेकर जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने होम गार्ड जवानों के लिए एक स्थाई नीति बनाने की बात कही है लेकिन अभी तक उनके लिए स्थाई नीति नहीं बनाई गई है। मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस या भाजपा, लेकिन होम गार्ड के जवानों के लिए एक स्थाई नीति बनानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि टालीवाल में 13 लोग मरे हैं जिस कारण वहां की चौकी के लोगों को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। वे लोग वहां पर कर क्या रहे थे क्योंकि वह स्थान उनके बिलकुल पास में था। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में शराब पकड़ी जाती है और उससे लोग मर जाते हैं तब जाकर उसकी जांच की जाती है। लेकिन इसकी जांच के लिए वहां के एस.पी. को ही जांच का इंचार्ज बना दिया जाता है। मेरा कहना है कि ऐसे केसिज़ में बाहर से किसी अधिकारी को जांच का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकरण में उनका भी कोई रोल रहा हो।

14-03-2022/1545/वाई.के.-एन.जी. /2

जैसा मैनें अभी बताया कि वहां के एस.पी. ने एक लड़के के साथ किस प्रकार नाइंसाफी की है और आप कहेंगे तो मैं आपको इसके कागज़ात दे भी सकता हूं। इनमें यदि हम देखेंगे तो बाकी सभी अभ्यार्थियों को 9-9 या 10-10 नम्बर दिए गए हैं लेकिन उस लड़के को केवल 5 नम्बर दिए गए हैं। इसके अलावा जिनके 57-58 नम्बर आए हैं उन्हें 10-10 नम्बर देकर उनके सीधे 5 नम्बर बढ़ाए गए हैं। मेरा कहना है कि इसके लिए वहां के एस.पी. को ही क्यों लगाया जाता है? मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी केस हो उसके लिए बाहर से एस.पी. या अन्य अधिकारी आने चाहिएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रक्कड कलोनी का एक छोटा लड़का किसी औरत के साथ चला गया या भाग गया। उसकी बुढ़ी मां मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे बेटा गुम हो गया है उसको वापिस लाने में मेरी मदद कीजिए। उसने यह भी कहा कि मैंने 5-7 माह तक बार-बार शिकायत दी है लेकिन अभी तक कोई

कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने एस.एच.ओ. को बोला कि इस केस पर कार्रवाई कीजिए और उस लड़के का मोबाइल चल रहा है इसलिए उसका पता लगाइए। जब मेरा हस्तक्षेप हुआ तब एस.एच.ओ. ने उसमें कार्रवाई करने का प्रयास किया। उस गरीब मां को पुलिस वालों ने कहा...व्यवधान...

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा का सुनने वाला सरकार को कोई भी प्रतिनिधि नहीं है यदि ऐसे ही माननीय सदन को चलाना है तो स्थगित कर दीजिए।...व्यवधान...

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर तो कोरम भी पुरा नहीं है। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चली हुई है और यहां पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहां पर मुख्य मंत्री ही नहीं है।...व्यवधान...

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1550/JS/AG/1

श्री सतपाल सिंह रायजादा:------**जारी**------

...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहूंगा कि ...व्यवधान...हमारे विपक्ष के सदस्य चले गए हैं और हम यहां पर बात रख रहे हैं ...व्यवधान...आप लोग कितने सीरियस हैं, आप लोग भी देखिये। वे इसलिए बाहर जा रहे हैं कि आप लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ...व्यवधान...आप लोग बाहर ही चले गए हैं और यह कोई सुनना नहीं हुआ। ...व्यवधान...मैं यह बोलना चाहूंगा कि फिर उस माँ को फोन गया कि आप गाड़ी ले करके आइये, हमने लड़के को ढूंढने जाना है। वह गरीब माँ वह कैसे गाड़ी ले करके जाएगी? वह कैसे गाड़ी का इंतजाम करेगी? मैंने खुद टैक्सी यूनियन से गाड़ी भेजी। मैंने पुलिस वालों को यह भी बताया कि मैं यह गाड़ी भेज रहा हूं। लेकिन जो औरत मेरे पास आई, उसके लिए मैंने गाड़ी भेज दी। ऐसे कितने लोग होंगे, कितने गरीब ऐसे होंगे कि उनके केस को, उनके बच्चों को ढूंढने के लिए तब तक बाहर पुलिस नहीं जाती है जब तक

उनके लिए इंतजाम न हो। यह इंतजाम आम व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर मैं बोलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन ऐसा प्रशासन होना चाहिए जो आम व्यक्ति को देखें। कम-से-कम जिस तरीके से पीछे भर्तियां हुई हैं, उस लड़के को भी सम्मान मिलना चाहिए, उस सारे मामले को देखिये। ...व्यवधान... मैं ज्यादा न बोलते हुए यही बोलूंगा कि हमारे जितने भी विपक्ष के साथी हैं और मुख्य मंत्री जी भी यहां पर खुद नहीं हैं। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपका धन्यवाद।

14.03.2022/1550/JS/AG/2

...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी, सत्र चला हुआ है और रिप्लाई देने वाला यहां पर कोई नहीं है। यहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। यह सरकार गिर गई है और हम अब जा रहे हैं। ...व्यवधान... कहां पर हैं, मुख्य मंत्री जी। ...व्यवधान...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बात सुनिये ...व्यवधान... अभी विक्रमादित्य सिंह को भी बोलना है। यहां पर उनका नाम आया है। ...व्यवधान... यहां लिस्ट में नाम है। ...व्यवधान... वे तो यहीं पर उपस्थित थे। ...व्यवधान...

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

14.03.2022/1555/SS-AG/1

अध्यक्ष महोदय क्रमागत :

माननीय सदस्य बात सुनिए। अभी विक्रमादित्य सिंह जी को भी बोलना है। उनका इसमें नाम है। ...व्यवधान... वे यहीं पर उपस्थित थे। ...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हिन्दुस्तान की किसी असैम्बली में नहीं हुआ कि जवाब देने वाला सदन में नहीं है।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

अध्यक्ष : अब चर्चा के अंत में माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे।

14.03.2022/1555/SS-AG/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया था उसमें विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विपक्ष के माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी, इन्द्र दत्त लखनपाल जी, राकेश सिंघा जी जोकि सी0पी0आई0(एम) से संबंध रखते हैं, श्री नंद लाल जी तथा श्री सतपाल सिंह रायजादा जी शामिल हैं। इन सभी की ओर से ये कटौती प्रस्ताव माननीय सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव सदन में लाए गए हैं मैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री राकेश सिंघा सहित विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए।)

विपक्ष के सभी सदस्यों का स्वागत है। कुछ पल का ही फासला था। ...व्यवधान... फूल हमेशा अच्छा ही होता है और यहां लगा हो तो और भी अच्छा होता है। धन्यवाद।

मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश को जब हम "देवभूमि" कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि आज की परिस्थिति में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से हम अभी भी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। हिमाचल प्रदेश के हम देवतुल्य लोग खासतौर से उन लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो कानून को मैंटेन करने में सहयोग देते हैं। उसके साथ-साथ में हिमाचल की जो हमारी संस्कृति है उसको कायम रखने व मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो विपक्ष की ओर से कहा गया कि सब कुछ खराब हो गया और अभी-अभी खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि कानून-व्यवस्था की सारी स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति में बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जोकि समाज में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे कानून-व्यवस्था थोड़े समय के लिए खराब हो जाती है। उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। ऐसे

में कई बार हम इस बात को देखते हैं कि उनकी संख्या कई बार ज्यादा होती है और कई बार कम होती है, ऐसा होता रहता है

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2022/1600/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी---

आमतौर पर सामान्य स्तर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज की तारीख में भी कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहतर है। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमें को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। यहां अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और अंजाम तक उसको पहुंचाया गया। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां रहीं जहां पर घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया गया। कई बार अंजाम देते-देते, जिस प्रकार से उनकी मंशा थी, उसको रोका गया। लेकिन फिर भी इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ जगह घटनाएं फिर भी घटित हो जाती हैं जिनके कारण समाज पर बुरा असर पड़ता है लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम कहे कि सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, पुलिस महकमा कुछ नहीं कर रहा है, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि पुलिस वर्ग कठिनाई और मेहनत से जिस तरह सफल हो कर सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम उनको दोष देते रहे तो इससे उनके मनोबल को भी क्षति पहुंचेगी। हां, अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी की किसी विशेष मसले को ले कर कहीं कमी रही है, त्रुटि रही है तो निश्चित रूप से उसके बारे में कहा जा सकता है। वैसे में हम कार्रवाई भी करते हैं। अगर किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी ने कोई कोताही की है, तो उस पर तो कार्रवाई होती रही है और ऐसे में हमने कार्रवाई की भी है लेकिन यह कतई उचित नहीं है कि हम इस तरह से कहें कि पुलिस वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। ऐसा कहने से हमें परहेज करना चाहिए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि हमारे पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी दिन-रात हमारे प्रदेश के अंदर सक्रिय हो कर अपनी भूमिका निभा

रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। अगर कोई गलत लोग किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हों, उन्हें रोकते हैं, उनके बारे में ऐसा कहें तो उससे उनके मनोबल पर असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए।

14.03.2022/1600/केएस/एजी/2

अध्यक्ष महोदय, खासतौर पर यहां पर जो आंकड़ों को ले कर कहा जाता है, पहले परिस्थिति अलग थी। मामले घटित हो जाते थे लेकिन उसके बावजूद मामला दर्ज नहीं होता था। अब लोगों में जागरुकता बढ़ी है जिसके कारण कहीं पर भी अगर कोई घटना होती है तो उसको लोग रिकॉर्ड पर लाते हैं। पहले ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं लेकिन उसके बावजूद पुलिस में वे दर्ज नहीं हो पाईं। हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि घटना चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पुलिस के रिकॉर्ड में उसका ज़िक्र होना चाहिए, वह पुलिस के रिकॉर्ड में रहनी चाहिए ताकि दोषियों पर हम कार्रवाई कर सके।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 से 2021 तक कुल 78,977 अभियोग पंजीकृत हुए। स्वभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, हम देख रहे हैं कि पिछले समय में केसिज़ की रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ी है। अब की बार इसमें थोड़ा और बढ़ौत्तरी हुई है। लेकिन उसका कारण मैं यह मानता हूं, जिस प्रकार से मैंने कहा कि हर मामले को दर्ज करने की हमारी सरकार ने प्रक्रिया सुनिश्चित की है ताकि वह रिकॉर्ड पर रहे, वह भी एक कारण है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुईं जिनका स्वरूप गम्भीर था और जो भी गम्भीर घटनाएं हुईं, उस पर हमने कार्रवाई की।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2022/1605/av/as/1

मुख्य मंत्री ---- जारी

पूर्व सरकार के कार्यकाल की तुलनात्मक अवधि में पंजीकृत अपराधियों के विश्लेषण से पाया गया कि इस सरकार के कार्यकाल में हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के प्रति क्रूरता, चोरी, घरेलू हिंसा, चोट व दंगे और वाहन दुर्घटनाओं के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में कमी आई है। अगर उसका जनरल पूरा अकाउंट निकाले तो मैंने स्वाभाविक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में एफ0आई0आर0 की पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी पाई जाती है। यहां पर मैं थोड़े आंकड़े देना चाहूंगा जिसके अंतर्गत पूर्व सरकार के समय में हत्या के 443 मामले हुए थे और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 345 मामले दर्ज हुए हैं जोकि पिछली सरकार की तुलना में 98 मामले कम हैं। हत्या का प्रयास करने के मामले 265 आपकी सरकार के कार्यकाल में दर्ज हुए थे और 250 हमारे टाइम में हुए हैं। महिलाओं के प्रति क्रूरता 1072 मामलों में एफ0आई0आर0 हुई थी और हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसे 892 मामले रजिस्टर हुए हैं जोकि 80 कम हैं। चोरी के मामलों में 2504 एफ0आई0आर0 पूर्व सरकार के समय में दर्ज हुई थीं और 2007 हमारी सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत हुएं जोकि 497 कम हैं। ट्रैसपासिंग के मामलों का जिक्र किया जाए तो पूर्व सरकार के समय में 2800 मामले दर्ज हुए थे और हमारे समय में 1621 हुए; इसमें भी 1189 केसिज कम हैं। डकैती और लूट में आपकी सरकार के समय में 66 मामले दर्ज हुए थे और हमारी सरकार के कार्यकाल में 40 आए; इसमें भी 26 मामले कम हैं। चोट व दंगे के 4466 मामले आपकी सरकार के समय में दर्ज हुए थे और हमारी सरकार के पिछले चार वर्षों के कार्यकाल में 4101 केसिज आए हैं; इसमें भी 365 मामले कम हैं। सड़क दुर्घटनाओं की बात की जाए तो आपकी सरकार के कार्यकाल में 12206 मामले हुए थे और हमारी सरकार के कार्यकाल में 10659 आए; इसमें भी 1547 कम दर्ज हुए हैं। अगर सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या की बात की जाए तो आपके समय में 4620 मामले दर्ज हुए थे और हमारी सरकार के कार्यकाल में 4287 आए

14.03.2022/1605/av/as/2

जोकि 333 कम हैं। घायलों की संख्या का जिक्र किया जाए तो 21660 आपकी सरकार के कार्यकाल में आए थे और हमारी सरकार के कार्यकाल में 17122 मामले दर्ज हुए हैं; इसमें भी 4538 मामले कम हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कुछ मामलों को लेकर सख्ती की है। पहले बलात्कार के ज्यादातर केसिज अन-रिकॉर्डिड रहते थे। समाज में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आ जाती है जब परिवार वाले सोचते हैं कि घटना तो घट गई; अब मामला दर्ज करवाने का क्या फायदा। जिसके कारण कई बार ऐसे केसिज में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती थी। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में यह सोच रखी गई कि जांच के बाद परिणाम जो भी निकले मगर हमें इस बारे में प्रयत्न जरूर करने चाहिए। यही कारण है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसे मामलों के पंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से हर सरकार के कार्यकाल में आंकड़े आगे-पीछे होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जिन बातों को लेकर के कार्रवाई सख्त होनी चाहिए थी हमने उनमें प्रयत्न किए हैं और संगीन अपराधों में संलिप्त एक-एक व्यक्ति को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

टी सी द्वारा जारी

14/03/2022/1610/टी0सी0वी0/ए0एस**00/1**

मुख्य मंत्री.... जारी

मैं इसलिए भी इस बात को कहना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल पुलिस को President's Colour से सम्मानीत किया। यह पुरस्कार पाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य है। यह सम्मान बेहतर कार्य एवं निर्धारित मापदण्डों पर खरा उतरने वाले अव्वल दर्ज़े के पुलिस बल को दिया जाता है। प्रेजीडेंट कल्लर हिमाचल प्रदेश को मिला इसके लिए मैं पुलिस विभाग को भी बधाई देता हूं और निश्चित रूप से अच्छे कार्य के लिए हमारी पुलिस जानी जाती है। इसलिए उनको सम्मानीत करने का भी हक होना चाहिए और वे सम्मानीत किए गए। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में भी हिमाचल प्रदेश पुलिस को 'सीलवर ट्रॉफी' से नवाज़ा गया। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य करने में हिमाचल प्रदेश ने

पहला स्थान प्राप्त किया और भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने प्रदेश पुलिस को ट्रॉफी प्रदान की। इसी प्रकार से सी0सी0टी0एन0एस0 में उत्कृष्ट कार्य के लिए समस्त भारत में पहाड़ी राज्य की श्रेणी में लगातार दो वर्षों से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया। Sexual offenders, Identified Dead Bodies, Abetment to Commit Suicide, Missing Woman and Children and NDPS में संलिप्त अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक थाने में रजिस्टर नम्बर 26,27,28 और 29 शुरू किया गया है जिसके बेहतर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहने का प्रयास किया गया कि पुलिस के कर्मचारी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुख्य मंत्री आवास पर आए। आखिरकार पुलिस कर्मचारी भी अपने ही लोग हैं। उनके भी को जेन्यूइन इशूज हो सकते हैं। एक Disciplined force के प्रतिनिधि होने के नाते वे आए और उन्होंने अपना मैमोरंडम सौंपा। उन्होंने न कोई प्रदर्शन किया और न कोई बात हुई। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी मांग रखी और वहां से चले गए। कई लोगों ने कई तरह की बातें करने की कोशिश की। सरकारें आती-जाती रहती है लेकिन हमें मानवीय दृष्टिकोण सदैव रखना चाहिए और हर वर्ग के लिए रखना चाहिए। अगर वह डिसिप्लेनरी फोर्स हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उनको अपनी बात करने का

अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने शालीनता के साथ अपनी बात कही, हमने उनकी बात को स्वीकार किया और उनकी मांग की दिशा में आगे कदम उठाकर, उनकी मांग को पूरा करने में सहयोग किया है। कुछ बातों को लेकर उनके आग्रह आज भी आते है कि कुछ कमियां और रह गईं हैं। जब वे अपनी बात कहते हैं तो हम नियमानुसार और सहानुभूतिपूर्वक जो कुछ किया जा सकता है, वह करने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि प्रदेश में आपके कार्यकाल में 80 हजार से ज्यादा मामले दर्ज़ किए गए हैं, माफिया कुर्सियों पर बैठें हैं और लोग बाहर लाइन में खड़े हैं और जिस सरकार ने पुलिस राज चलाया, उसे लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

14-03-2022/1615/NS/DC/1

मुख्य मंत्री .....जारी

हमने कभी भी वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में एक जगह भी लाठीचार्ज़ नहीं हुआ है। ...व्यवधान... यह हमारा धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आपने इन्हें भड़काने की पूरी कोशिश की है। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, हमने सभी वर्गों चाहे कर्मचारी हैं या विभिन्न वर्गों के अन्य लोग हैं जिनके जेन्यूइन इश्यूज़ हैं और जिनको लगता है कि उनकी समस्या का समाधान की दृष्टि से हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमने उनकी बातें सुनीं। हां, कुछ लोग सीधे ही कुछ नेताओं के कहने पर गुमराह हुए। ज्यादा ऊंचें बोल कर या ज्यादा हुड़दंग करके कुछ ज्यादा हासिल करेंगे, जल्दी कुछ हासिल करेंगे तो यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। इसके लिए हमने कहा कि अभी रूकना पड़ेगा। जो हुड़दंगबाजी करेगा और जो इस प्रकार का व्यवहार करेगा उनकी बात को सुना जाएगा लेकिन माना जाएगा यह जरूरी नहीं है। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, यहां पर आए और हमने पूरी कोशिश की यहां से विपक्ष के माननीय सदस्य छाप-छाप के गए या पोस्टर बना कर गए और चुपके से उनको दिखाते रहे और भड़काते रहे। आखिरकार शाम जब हुई वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद अपने-अपने रास्ते चले गए। ...व्यवधान... हां, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना पुलिस का दायित्व था और पुलिस का दायित्व है। ...व्यवधान... कोई नहीं दौड़ा रहा था। प्यार से कहा कि आप उठिए भाई, अब कुछ नहीं बचा है। जो लोग आपको इस प्रकार से उकसा रहे हैं वे अपने-अपने बिस्तर में सो गए हैं, आप यहां चौराहे पर कहां सो रहे हैं? वे शाम को अपने घर चले गए और आराम से सो गए। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, जो लोग आए थे उनमें से दर्ज़नों लोग रह गए बाकी सब अपने-अपने रास्ते चले गए। उन्होंने जाते हुए न किसी को बोला कि हम जा रहे हैं और न इनको पूछा और न

उनको पूछा और जो 3 दर्ज़न लोग वहां पर रह गए तो उनसे पुलिस वालों ने कहा कि बाकी सब चले गए तुम यहां पर क्यों बैठे हो? ...व्यवधान... जब बचा कोई नहीं तब उनको लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वे इस बात को मान गए और उन्होंने इस बात को माना कि जो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं तो कोई नहीं मिला न चट्टान मिली और न ही विपक्ष के नेता के दर्शन हुए, सब लोग अपने-अपने रास्ते चले गए। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी और रात को आराम व प्यार से गए। दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने सोश्ल मीडिया पर अपना स्टेटमैंट डाला कि

14-03-2022/1615/NS/DC/2

हमने प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन करना था और जो बात रखनी थी वह रख दी उनके अध्यक्ष ने कहा कि सभी भाईयों का धन्यवाद करता हूं और अब हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है और सब अपने-अपने घर चले जाएं। क्योंकि बड़े नेता जिनके कहने पर आए थे वे अपने-अपने घर चले गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में वे निराश हो कर चले गए। उनको लग रहा था कि सड़क पर बैठेंगे और उनके साथ बैठेंगे अगर कुछ ऐसा होगा तो वे भी साथ होंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात को रखा और चले गए तथा हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। यह भी बात सत्य है कि कुछ कर्मचारियों का इस प्रकार से व्यवहार जिस दायित्व के लिए उनको वहां पर रखा है उस काम को कम करना और राजनीति ज्यादा करना उचित नहीं है। मैं कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आप सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करने और आगे बढ़ाने के लिए हैं। अपनी मांग को लेकर जितनी बात कहनी है लेकिन इस तरह से नहीं कि आप बड़े स्तर पर ऐसा सोचें

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1620/RKS/DC-1

मुख्य मंत्री... जारी

वे अपनी मांग रख सकते हैं लेकिन आप इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो यह एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध अनेकों बार मामले दर्ज करवाए। आपकी सरकार के समय पुलिस वालों ने जिस तरीके से कर्मचारियों को पिटा है उसकी सारी तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध हैं। इस बात को कर्मचारी कभी नहीं भूल सकते। ...व्यवधान... हमारे पास ब्लैक कैट कमांडो तो है ही नहीं। लेकिन मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता। प्रदेश में एन.डी.पी.एस. के तहत 5, 856 मुकदमें दर्ज़ किए हैं। हम बड़े-बड़े तस्करों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं एवं उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। संपत्ति को जब्त करने की प्रकिया हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने होम डिपार्टमैंट का रिव्यू करके पाया कि बहुत सारे लोग जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं उनके विरुद्ध यहां पर केस दर्ज हुए हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। ये लोग एन.डी.पी.एस. के धंधों में संलिप्त पाए गए हैं। हमने इस विषय में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और सामूहिक स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में कहा। हम इस दिशा में आगे बढ़े और चंडीगढ़ में दो बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में काफी सार्थक चर्चा हुई और उसके बाद राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के अधिकारी भी उपस्थित हुए। सीमावर्ती क्षेत्रों में हम ज्वाइंट ऑप्रेशन कैस कर सकते हैं, इसके लिए एक मैकेनिज्म डवेलप किया। हम आरोपियों को पकड़ने के लिए इंटैलिजैंस ब्यूरो की फीडबैक आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं? जब हम यहां सख्ती करते थे तो वे हरियाणा चले जाते थे और जब हरियाणा वाले सख्ती करते थे तो वे पंजाब चले जाते थे। जब पंजाब वाले सख्ती करते थे तो वे किसी और जगह भाग जाते थे। ऐसे में यह करना जरूरी था और इसके लिए हमने सभी बातों को गंभीरता से लिया। ऐसे मामलों में हम तस्करों की 20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुके हैं जो आज से पहले कभी नहीं की गई थी। इस धंधे में आदमी ज्यादा पैसा कमाने के लिए जुड़ता है। वह रातों-रात अमीर होने के ख्वाब देखता है और सोचता है कि

उसके पास रातों-रात कोठियां और बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाएं। लेकिन जब हमने उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कही तो इससे उनमें काफी दहशत फैली। एक वर्ग इस धंधे से पैसा कमाने की सोच रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी चपेट में उलझ गए हैं। हमने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की है। खनन माफिया के मामले को यहां पर बहुत जोर से उठाया गया। जब हम विपक्ष में थे तो हम भी बड़े स्तर में खनन माफिया के मामले को उठाते थे। आपके समय में 29 एफ.आई.आर्ज. दर्ज हुई और हमारी सरकार ने अब तक 139 एफ.आई.आर्ज. दर्ज की हैं। यह नम्बर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने किसी के प्रभाव में आकर कार्रवाई नहीं रोकी। आपके समय में 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था और हमारी सरकार ने अब तक 18 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया है। खनन माफिया के बारे में मैं यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इसे आय का धंधा बनाया है उनकी संपत्तियों की जांच करके उन्हें जब्त किया जाएगा।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1625/बी.एस./एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

इसमें भी हमने बड़ा साफ कहा है कि जिन लोगों ने इसे आय का जरिया या पैसे कमाने का धंधा बना लिया है, उसकी संपत्ति की भी जांच होगी और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, यह भी हमने उसमें सुनिश्चित किया है। विपक्ष के नेता जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी एक बात और कही है कि पुलिस वालों ने मास्क न पहनने वालों के ऊपर कार्रवाई की है। उसमें 9-10 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कोविड का कठिन दौर था और उसमें सख्ती करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। पुलिस वालों ने यह सब खुशी से नहीं किया है। कोविड के फस्ट फेज के बाद दूसरा वेरिएंट दौर आया उसके कारण बहुत से लोगों की दुःखद मृत्यु हुई। उस वक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी और इसके लिए सबसे पहले मास्क पहना जरूरी था। जिन लोगों ने मास्क पहले थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिन लोगों ने

मास्क नहीं पहना था, यदि थोड़ी-बहुत कार्रवाई हुई होगी, तो वह पुलिस ने पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं की, परंतु जान बचाने के लिए की है।

माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि हिन्दुस्तान में मुख्य मंत्री जी के नाक के नीचे ऐसी घटना पहली बार हुई कि एक पुलिस अधिकारी ने दूसरे पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहताद हूं, जब यह घटना हुई, इस पर कार्रवाई की गई है। यहां पर यह भी कहा गया कि पुलिस कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों में इस बात को ले करके कोई असंतोष नहीं है, जिस दिन वे भर्ती हुए हैं, उन्हें पता है कि यह कोई ऐसा विभाग नहीं है, जिसमें सामान्य परिस्थितियों में काम करेंगे या घर या दफतर मैं बैठ करके काम करेंगे। उन्हे फील्ड में जाना होगा, कई जगह परिस्थितियां अनुकूल होंगी कई जगह प्रतिकूल होंगी और यह मानकर चलना पड़ेगा कि संघर्ष की परिस्थितियां हर जगह हो सकती है। उस वक्त आपको, उन्हें संभालना होगा। पुलिस एक अनुशासित फोर्स होने के नाते निष्ठा के साथ आपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। मुझे प्रशन्नता है कि जहां उनके इश्यूज को ले करके, सुविधाओं को ले करके कहीं बात होती है, उस बात को ले करके हमने कहा कि आप हमारे समक्ष अपनी बात रखिए और हम जो भी मदद कर सकते हैं, निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे।

14.03.2022/1625/बी.एस./एच0के0/-2

और हमने समय-समय पर की भी है। आपने ट्रेनिंग सुविधाओं को ले करके बात कही है, उसमें अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार पुलिस प्रशिक्षण को ले करके बेहतर एवं समय के अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत है, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षी पशिक्षण में दो बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तथा केन्द्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से उसे सम्मानित भी किया गया है। यहां पर एक और उस तरह का विषय आदरणीय नेगी जी ने उठाया और मैंरा मानना है कि माननीय सदन में उस तरह का विषय नहीं उठाना चाहिए। एक आई0पी0एस0 अधिकारी के खिलाफ जो एन0आई0ए0 ने जो कार्रवाई की है। अध्यक्ष जी , अगर एजेंसी ने कोई कार्रवाई की है और वह भी राष्ट्र स्तर की एजेंसी है। जिस तरह की बातें उसमें हैं वह बहुंत गंभीर हैं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1630/एच.के.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री जारी.....

इसलिए मेरा कहना है कि इस बारे में हमें इस माननीय सदन में कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वह कुछ तथ्यों के आधार पर ही की होगी और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह मैटर Under Investigation है इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि रिकांगपिओ में बिना मास्क के लोगों का चालान किया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस वायरस के कारण कुछ स्थानों पर इस प्रकार से करना पड़ा है। आज के समय में उसमें थोड़ी ढ़ील दी गई है क्योंकि कोविड के मामलों में गिरावट आई है लेकिन यह वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज की तारीख में किसी का भी चालान नहीं किया जा रहा है। यदि कहीं भीड़ में पुलिस वाले मास्क के लिए कहते भी हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसे अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए। माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने बिझड़ी और ढ़डवाल के लिए कुछ बातों का जिक्र किया है। मैं पिछले कल माननीय सदस्य के क्षेत्र में गया था और मैंने इनमें से कुछ बातों का जिक्र भी किया है। हम इनके कामों को कर रहे हैं। ...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी आपके स्वागत में वहां पर आए थे लेकिन आपने उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा। आपने उन्हें कहा कि माननीय सदन में मिलते हैं। जबकि मुख्य मंत्री का कार्यक्रम सरकारी होता है।

मुख्य मंत्री : आपकी बात ठीक है कि माननीय सदस्य वहां पर आए थे। मैंने उनसे कहा कि आपका कार्यक्रम क्या है तो उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वागत करने के लिए आया हूं। मैंने

उनका धन्यवाद किया और कहा कि मिलते हैं। वे कार्यक्रम में आते तो अच्छा होता क्योंकि हमने उनके ख़िलाफ एक शब्द भी नहीं बोला।

14-03-2022/1630/एच.के.-एन.जी. /2

जब आपकी सरकार थी तब आप लोग तो पानी पी-पी कर हमारे नेताओं के लिए बोलते थे। हम उस ढ़र्रे पर नहीं चल रहे हैं और आपके व हमारे बीच में यही अंतर है। माननीय सदस्य वहां पर अलग से खड़े हुए थे और मैं स्वयं उनके पास चल कर गया। चोपर से उतरने के पश्चात जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर हुआ उसके बाद मैं सबसे पहले माननीय सदस्य जी को मिलने गया और मैंने उनका धन्यवाद किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिससे किसी भी जन प्रतिनिधि को बुरा लगे क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति हमारा सम्मान सदैव बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि पुलिस में भर्तियां होनी चाहिए और मैं इस बात से सहमत हुं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा भर्तियां की जाएं ताकि खाली पदों को भरा जा सके। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ बातों का जिक्र बार-बार हुआ है और मैं उन सभी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बेहतर करने के लिए हमेशा एक स्कॉप बना रहता है। हम खुले मन से इस बात के लिए तैयार हैं कि जहां पर भी सुधार किया जा सकता है हम वहां पर सुधार करेंगे और हमें करना भी चाहिए। त्रुटि के मामले में हमने अधिकारियों को अनेक बार कहा है कि सुधार की दृष्टि से जो किया जा सकता है वह किया जाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारा

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1635/जेएस/वाईके/1

मुख्य मंत्रीः--- जारी---

पुलिस विभाग कानून-व्यवस्था को मेनटेंन करने में भी बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश को जो पुलिस बैंड की वज़ह से अलग से पहचान मिली है, उसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया है। कला का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने वहां कलर्ज़ चैनल पर अच्छा परफोर्म किया है। पुलिस वालों ने ऐसा पहली बार किया, नहीं तो डंडा ही मारते हैं। वे गाते हुए आपका मनोरंजन कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को भी पुलिस वालों को उसके लिए बधाई देनी चाहिए। कई लोग इसमें टिप्पणी भी करते हैं कि देखो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले जिम्मेदारी के साथ कानून-व्यवस्था को भी सम्भाल रहे हैं और पुलिस वाले उस काम को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, जिससे अलग से हिमाचल प्रदेश को पहचान मिली उसको भी दिल से कर रहे हैं। हमें इन सारी बातों को मान कर आगे चलना चाहिए। हर्षवर्धन सिंह जी जो आप कलाकारों की परमोशन का सुझाव दे रहे हैं, यह आपका ठीक सुझाव है, इस सुझाव पर हम विचार करेंगे। हमें भी अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस की भर्ती आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएगी। कमी है तो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। समय-समय पर पुलिस विभाग को जिन चीजों की जरुरत होती हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाता है। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यथा सम्भव जो भी पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए किया जा सकता था, वह हमने करने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। जो कटौती प्रस्ताव यहां पर माननीय विपक्ष के सदस्यों ने लाया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हिमाचल देव भूमि है। हम सब लोग इस देव भूमि में रहते हैं। घटनाएं जहां पर घटित हुई हैं वहां पर कार्रवाई हुई है। लोगों को पकड़ कर लाए हैं, चाहे एक्साइज का मामला है, चाहे खनन का मामला है, चाहे चोरी के मामले हैं और चाहे बलात्कार के मामले हैं। अधिकांश मामलों में हम अंजाम तक पहूंचे हैं। मैं दावे के साथ

कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बच करके निकला हो। जो भी दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो भी बैस्ट पोसिबल हो सका वह हमने किया है। प्रदेश के अन्दर और प्रदेश से बाहर भी यदि कोई चला गया है तो वहां से भी हम उसको पकड़ करके लाए हैं। इसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं विपक्ष के सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है जो भी आपने कहा है, वह सुधार की दृष्टि से कहा है। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। perfection can never be achieved. मेरा मानना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ-न-कुछ सीखने के लिए सदैव कुछ-न-कुछ मिलता रहता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। पुलिस विभाग सुनिश्चित करेगा कि जहां और बेहतर दृष्टि से कुछ कदम उठाने की जरूरत है, वह भी करेंगे और सरकार की ओर से भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि पुलिस और प्रशासन बेहतर काम कर सके ताकि जो भी मामले हैं, उनमें चाहे एन.डी.पी.एस., एक्साइज,खनन, चोरी, बलात्कार और चाहे डकैती के मामले हैं, उन सारी चीजों पर हम सख्त कार्रवाई करते हुए संदेश दे सकें, इस बात के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मेरा सभी माननीय विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि मेरे उत्तर को ध्यान में रखते हुए आप यह कटौती प्रस्ताव वापिस लें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के ज़वाब के बाद मैं यही कहना चाहूंगा किः-

देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें,
ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा ज़वाब दिया है।

श्री एस.एस. द्वारा अध्यक्ष जारी-----

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कटौती प्रस्ताव आपने दिए हैं क्या उन्हें वापिस लेंगे? मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सरलता, सहजता से सारे पक्ष को ध्यान में रखकर उत्तर दिया है और आपसे आग्रह किया है कि आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, जो बारूद प्रकरण हुआ उसमें एन0जी0टी0 का फैसला आ गया और 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया। जो 50 परसैंट घायल हुए उनको 15-15 लाख रुपया, 25 परसैंट जो घायल हुए उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। यह एन0जी0टी0 का फैसला बारूद प्रकरण में आ गया। आपने टाहलीवाल चौकी के ऊपर ऐक्शन तो क्या कोई बात तक नहीं की। चौकी की रैपुटेशन क्या है उसके बारे में आप सारे इलाके में पूछ सकते हैं। मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूं कि यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है। हमने यह मामला आपके ध्यान में लाया कि 13 लोगों की जान चली गई है। लेकिन आपने उसमें कोई जवाब नहीं दिया है। आपने उसको जम्प कर दिया है। इसलिए हम अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं ले रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की दिशा में है। वहां पर डी0जी0पी0 भी गए थे और उसके साथ-साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अन्य स्टाफ को भी लाइन हाजिर किया है। **इस घटना के पश्चात् विस्फोट के कारण जिनकी दुखद मृत्यु हुई थी, जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि विशेष तौर से उनकी ओर ज्यादा मदद होनी चाहिए उस दृष्टि से जो आपने एन0जी0टी0 का ज़िक्र किया है उसको हम एग्जामिन कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसमें हमें एतराज नहीं है, अगर प्रावधान में उनकी मदद में कोई कमी रह गई है तो उस पर विचार करेंगे।**

अध्यक्ष : तो फिर कटौती प्रस्ताव वापिस लेने में आपकी न है।

14.03.2022/1640/SS-YK/2

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जगत सिंह नेगी जी, नंद लाल जी, इन्द्र दत्त लखनपाल जी, राकेश सिंघा जी, सतपाल सिंह रायजादा जी; माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 7 - पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित मु0 16,14,37,53,000/- रुपये (राजस्व) एवं मु0 66,04,00,000/- रुपये (पूंजीगत) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

14.03.2022/1640/SS-YK/3

अब मांग संख्या : 10 लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन को चर्चा हेतु लिया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2023 को समाप्त समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 10 लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित मु0 34,32,63,74,000/- रुपये (राजस्व) एवं मु0 12,94,54,00,000/- रुपये (पूंजीगत) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं। इस पर माननीय सदस्य श्रीमती आशा आशा कुमारी जी, सर्वश्री जगत सिंह नेगी जी, हर्षवर्धन चौहान जी, नंद लाल जी, राजेन्द्र राणा जी, मोहन लाल ब्राक्टा जी, रोहित ठाकुर जी, राकेश सिंघा जी, विक्रमादित्य सिंह जी, आशीष बुटेल जी, सुन्दर सिंह ठाकुर जी, इन्द्र दत्त लखनपाल जी, पवन कुमार काजल

जी, भवानी सिंह पठानिया और श्री संजय अवस्थी माननीय सदस्यों की ओर से पांच कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2022/1645/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी----

क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से प्रस्तुत हुए समझे जाएं?

माननीय सदस्यः सर, कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ समझा जाए।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जोकि इस प्रकार हैं-

सदस्य का नाम	**कटौती प्रस्ताव**	**मांग संख्या**
	नीति का अननुमोदन	**10**
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **च्लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवनछ** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।	

1. **श्री जगत सिंह नेगी,**
2. **श्री हर्षवर्धन चौहान,**
3. **श्री नन्द लाल,**
4. **श्री राजेन्द्र राणा,**
5. **श्री मोहन लाल ब्राक्टा,**
6. **श्री रोहित ठाकुर,**
7. **श्री राकेश सिंघा,**
8. **श्री विक्रमादित्य सिंह,**
9. **श्री आशीष बुटेल,**
10. **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,**
11. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,**
12. **श्री पवन कुमार काज़ल,**
13. **श्री भवानी सिंह पठानिया,**
14. **श्री संजय अवस्थी ।**

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की ब्लैक स्पॉटस का सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के कार्यान्वयन की नीति का अननुमोदन ।

14.03.2022/1645/केएस/एजी/2

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
च्लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवनछ
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्रीमती आशा कुमारी:

मांग संख्या-10 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र डलहौजी में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क सगोटी, चीरी डराबड, जटरहन को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता ।

14.03.2022/1645/केएस/एजी/3

तो मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं। अब श्रीमती आशा कुमारी इस चर्चा का शुभारम्भ करेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन पर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव मैंने दिया था, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट है, 8 तारीख को पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था। मैंने मेंटिनेंस और नैचुरल केलेमिटीज़ का जो डिविज़न वाइज़ पैसा दिया जाता है, उसके बारे में पूछा था। मैंने नॉर्थ जोन के बारे में पूछा था। नॉर्थ जोन में जो हमारा सर्कल 7th डलहौजी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सलूणी डिविज़न के रोड्ज़ बहुत ज्यादा हैं, बैकवर्ड एरिया है, बर्फीला एरिया है। वहां मेंटिनेंस और केलेमिटी दोनों में फंड बाकी डिविज़न की अपेक्षा कम है। एक तो मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि जो लॉसिज़ होते हैं, उसके हिसाब से यह पैसा आबंटित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सलूणी का विधायक विपक्ष से है तो उसकी कटौती कर दी जाए और माननीय उपाध्यक्ष जी रूलिंग पार्टी से हैं तो इनकी बढ़ौत्तरी कर दी जाए। वैसे एक-दो चीजों में इनका भी वही हाल है जो मेरा है। इसी तरह से वेकेंसीज़ को ले कर जो बात है, सर्कल में भी अगर आप देखें तो 50 परसेंट से ज्यादा वेकेंसीज़ हैं। जब क्लैरिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ, पूरे स्टाफ की कमी होगी तो निश्चित तौर पर पी.डब्ल्यू.डी. का काम सफ़र करता है। इस बात को सभी जानते हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. में लेबर खत्म होती जा रही है। पी.डब्ल्यू.डी. में लेबर की भर्ती नहीं हो रही है। आपने कहा था कि मल्टी टास्क वर्कर्ज़ रखेंगे। पिछले साल भी आपने यह कहा था और इस साल भी कहा है। वह 30,000 का आपका तीस मार खां का फीगर कम नहीं होता है मगर बंदा एक भी नहीं रखा गया है। हालात यह है कि आज पी.डब्ल्यू.डी. में बेलदारों की कमी है।

14.03.2022/1645/केएस/एजी/4

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, अपने आप जो वे काम कर लेते थे, पी.डब्ल्यू.डी.जो डिपार्टमेंटली काम कर लेता था, वह काम आज नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि बेलदार नहीं हैं। जो नॉर्मल मेंटिनेंस सड़कों की होती थी, पी.डब्ल्यू.डी. का स्टाफ ही कर लेता था जिसमें बेलदार और मेट आदि होते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट बिल्डिंग्ज़ की यदि बात करें, तो हमारी बहुत सारी गवर्नमैंट बिल्डिंग्ज़ को रिपेयर की ज़रूरत है। उसमें पैसा कम आबंटित होता है। इस बार आपने बढ़ाया है, मगर उस इन्क्रीज़ में से चम्बा जिला के 7th सर्कल डलहौजी चुनाव क्षेत्र को आप उचित पैसा दें और कम से कम इतना तो दें कि आपकी बिल्डिंग्ज़ गिर न जाए। बहुत सारी बिल्डिंग्ज़ की रिपेयर की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बार यह कहा है कि रिन्यूवल कोर्ट पांच साल के बदले अब तीन साल में होगा, यह अच्छा कदम है।

उपाध्यक्ष जी, टूरिस्ट प्लेसिज़ में डलहौजी तो कवर होता है मगर जो हमारा बाकी एरिया है, आप उपाध्यक्ष जी, जानते ही हैं कि जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर डैमेज ज्यादा होता है। विशेषकर जब बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी लगाई जाती है और बहुत सारे जो ठेकेदार हैं या दूसरे लोग हैं, वे केयरफुली जे.सी.बी. नहीं चलाते। वे जे.सी.बी. के दांत को लगाकर बर्फ उठाते हैं और उसके दांत के साथ टारिंग भी निकल जाती है। आपको इसके लिए कोई ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि जो स्टेट हाईवेज़ हैं, वह चाहे टूरिस्ट प्लेस पर हों या न हों। स्टेट हाईवेज़ मेन हाईवेज़ को कनैक्ट करते हैं, जैसे हमारी सलूणी को जो रोड़ जाता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2022/1650/av/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी---- जारी

जो स्टेट हाईवेज हैं वह चाहे टूरिस्ट प्लेस के अंदर हो या न हो; मगर जो मेन हाईवेज को कनेक्ट करती हैं जैसे हमारा सलूणी, भांदल कीहार, तीसा, सतरुंडी या भरमौर इत्यादि को जो रोड्ज जाती हैं; उसको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आप यदि केवल टूरिस्ट प्लेस बोलेंगे तो डलहौजी में रिन्यूल कोट केवल कटोरी बंगला अलाउ करेंगे और बाकी सड़कें जो वास्तव में जीवन रेखाएं हैं; वहां कुछ भी नहीं करेंगे। सरकार ने डलहौजी में पीछे एक रोबो स्नो कटर दिया, मैं यह कहना चाहती हूं कि वह ज्यादा इफैक्टिव नहीं है। यदि डेढ़

फीट से ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो वह उस पर चलता ही नहीं है। वह शिमला के लिए तो ठीक है मगर वहां वह चलता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इस बजट में सलूणी, डलहौजी और तीसा डिवीजन के लिए एक-एक बड़ा स्नो कटर जरूर दिया जाए। मैं यह इसलिए कह रही हूं कि इन तीनों स्थानों पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। वह रोबो डेढ़ फीट से ज्यादा बर्फ के ऊपर चल नहीं पाता और इस बार डलहौजी में साढ़े चार फीट बर्फ पड़ी थी। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि मशीनरी की अपग्रेडेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या फोरैस्ट क्लीयरेंस की आ रही है। फोरैस्ट क्लीयरेंस के केस 5-6 वर्षों तक लटके रहते हैं, आपको इसके लिए कोई-न-कोई मेकैनिज्म निकालना पड़ेगा जिससे सभी मामलों में फोरैस्ट क्लीयरेंस निश्चित अवधि में हो। मैं यह नहीं कहती कि इसमें वन विभाग की ही गलती है मगर लोक निर्माण विभाग ही अपनी स्कीम्ज को समय पर अपलोड नहीं करता है। आपके पेपर्ज नहीं बनते हैं, आप पेपर्ज बनाने के लिए कम-से-कम लोक निर्माण विभाग की ओर से तो टाइम बाउंड किया जाए। फोरैस्ट डिपार्टमैंट अगर समय लगाता है तो मैं समझ सकती हूं कि उनके कुछ ऑब्जैक्शन्ज हो सकते हैं। मैंने यहां पर सगोठी, जटरैन, चीड़ी-द्रबड़ को लेकर अपने कट मोशन दिए हैं। चीड़ी-द्रबड़ डलहौजी डिवीजन के अंतर्गत आता है और बाकी दोनों स्थान सलूणी डिवीजन के तहत पड़ते हैं। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी सड़कें फोरैस्ट क्लीयरैंस न होने के कारण अभी भी पैंडिंग पड़ी हुई हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि फोरैस्ट क्लीयरेंस को

14.03.2022/1650/av/ag/2

एक्सपिडाइट करवाया जाए। फोरैस्ट क्लीयरेंस न होने के कारण हमारी सलूणी की बहुत सारी सड़कें पैंडिंग हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि लोक निर्माण विभाग अपनी ड्रॉईंग ब्रांच के स्टाफ और क्लेरिकल स्टाफ की पूर्ति जरूर करे। ड्रॉईंग ब्रांच में स्टाफ बचा ही नहीं है, जब ड्रॉईंग ब्रांच का स्टाफ ही उपलब्ध नहीं होगा तो बिल्डिंग्ज इत्यादि के काम आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है कि इन कार्यों के मामले में हम पीछे-पीछे जाते रहते हैं। मैं समझती

हूं कि इन सारी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्य मंत्री और लोक निर्माण विभाग निकालेगा। मगर जिस प्रेजेंट फॉर्मेट में यह बजट पेश हुआ है क्योंकि कई सड़कों में पैसे नहीं डालेगे। अगर कहीं डाले हैं तो किसी में 5000 रुपये; अब 5000 रुपये आप किस लिए डालते हैं? हमने पहले भी कहा था कि आपका बजटिंग स्टाइल सही नहीं है। आपकी एक ही सड़क दो-दो, तीन-तीन जगह अपीयर होती रहती है। आप इसको कंसोलिडेट कीजिए, आपकी एस0सी0सी0पी0 में रोड्ज इसीलिए रुकी रहती है। आपकी चीड़ी-द्रबड़ रोड भी इसीलिए रुकी हुई है। अभी यहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी बैठी नहीं है। चीड़ी-द्रबड़ रोड के लिए सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट ने पैसे भी डिपोजिट कर दिए मगर उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने उस सड़क को अपलोड नहीं किया है। चीड़ी-द्रबड़ रोड के केस को 5 वर्षों में अपलोड नहीं किया गया है this is shocking. इसके अपलोड न होने का कारण स्टाफ की कमी है। एस0सी0 और एक्सियन है मगर नीचे काम करने वाला कोई स्टाफ नहीं है। इसलिए आप अपने ड्रॉईंग ब्रांच और क्लेरिकल स्टाफ को स्ट्रैंग्थन कीजिए। इसी तरह से हमारी सड़कों और पुलों के लिए पैसा नहीं दिया गया है जबकि हमने उनको अपनी प्राथमिकता में दिया है। पिछले 5 वर्षों की हमारी प्रायोरिटीज में से बहुत कम डी0पी0आर्ज0 बनी हैं और वह भी वे बनी हैं जिनकी सेम रोड्ज की मैटलिंग और टारिंग थी तथा जिनकी फोरैस्ट क्लीयरेंस माननीय श्री वीरभद्र सिंह के टाइम में हो चुकी थी।

टी सी द्वारा जारी

14/03/2022/1655/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री आशा कुमारी ... जारी

उसकी मैटलिंग और टारिंग के लिए इनको फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेनी ही नही है। इन डी0पी0आर्ज0 के अलावा एक-दो हाईवे ब्रिजिज की डी0पी0आर्ज हुई हैं। मैं यह चाहूंगी कि भारत सरकार से वर्ल्ड बैंक फंडिंग में जो जीरो प्वाइंट से लेकर के खुंडीमराल बॉर्डर तक

रोड बनाने का टैंच-॥ में इन्कलूड हुआ है, उनकी डी0पी0आर्ज0 शीघ्र बनाई जाए ताकि वे सड़कें जल्दी बन सकें। मुझे नहीं लगता कि जो सड़कें ट्रैंच-॥ में थीं, उनका भी अभी काम शुरू हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी सड़कों को बनाने के बारे में कोई दृष्टि या धनराशि देता है। इसलिए मैं इसका अननुमोदन करती हूं और इसका समर्थन नहीं करती। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : मांग संख्याः 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन, इस कटौती प्रस्ताव पर अब मैं माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

14/03/2022/1655/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

श्री जगत सिंह नेगी, किन्नौर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से कोरम पूरा नहीं है। क्या सरकार इन चर्चाओं पर गंभीर हैं या लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदला जा रहा है? आप मांग पर वोटिंग करवा लें। कोई भी मंत्री माननीय सदन में नहीं है। कोरम तो सत्ता पक्ष को पूरा करना है और कंसर्न मंत्री भी सदन में नहीं है।

उपाध्यक्ष : मेरा मुख्य सचेतक और उप सचेतक से आग्रह है कि यह इंश्योर करें कि आपके माननीय सदस्य यहां सदन में उपस्थित रहें। कोरम पूरा करने की जिम्मेदार सत्ता पक्ष की होती है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी आप अपनी बात जारी रखें।

श्री जगत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन, यानी Public Works Department. यह काम कितना करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो माननीय सदस्य ही बताएंगे। हिन्दुस्तान में पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसके बाद जब केन्द्र की सरकार बनी तो सेंटर पीडब्ल्यू0डी0 और जब प्रदेश सरकारें बनीं तो प्रदेश में लोक निर्माण विभाग बना। आई0पी0एच0 विभाग जिसे अब जल शक्ति विभाग का नाम दिया गया है, यह भी कभी लोक निर्माण विभाग का ही हिस्सा था। अब इसका नाम जल शक्ति विभाग रखा गया है और आने वाले समय में

पाइप शक्ति या कोई और नाम से हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोक निर्माण विभाग का काम चला हुआ है, इस विभाग का काम केवलमात्र टेंडर देना, कमीशन लेना ही रह गया है। इसलिए क्यों न पब्लिक वर्कस डिपार्टमैंट का नाम बदल का पब्लिक टेंडर कमीशन डिपार्टमैंट रखा जाए। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह लोक निर्माण विभाग तक ही सीमित नहीं है जिस तरह से कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई है इसी तरह से

एन0एस0 द्वारा जारी ...

14-03-2022/1700/NS/AS/1

श्री जगत सिंह नेगी .....जारी

राजस्व विभाग में टोडरमल के जमाने से भ्रष्टाचार पहले से ही था। जब लोक निर्माण विभाग बना तो अंग्रेजों के समय से भ्रष्टाचार की बीमारी लग गई थी। अगर ठीक से कहूं तो नारीमन म्युनिसिपल कार्पोरेशन, मुम्बई में पार्षद थे और उनका मानहानि का एक केस चला था। कोई अंग्रेज सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने उस समय लोहे में गड़बड़ी की तो उन्होंने उसके बारे में अखबारों में बयान दिया था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यह मानहानि का केस हिन्दुस्तान में आज तक जितने मानहानि के केस हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। इस केस में पहली बार कोर्ट ने माना कि जो उन्होंने मानहानि या भ्रष्टाचार की बात की थी तो एक पार्षद ने तथ्यों के आधार पर in public interest जो भी एलिगेशन उस अधीक्षण अभियंता पर लगाया गया था उन्होंने उसको मानहानि नहीं माना। आज लोक निर्माण विभाग के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि काम होता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एक बिल्डिंग बनानी हो तो कम-से-कम 15 साल चाहिए। कोई सड़क बनानी हो तो भी 15 साल चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरा एक प्रश्न लगा था और मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि समय हो गया था। प्रश्नकाल एक घंटें का होता है। मंत्री इतना लंबा जवाब देते हैं कि हमारा एक प्रश्न ही उनके जवाब से खत्म हो जाता है। मैं सदन से निवेदन करने वाला था कि प्रश्नकाल में हमारा टाइम और मंत्रियों का जो उत्तर होता है उसको माइनस करके प्रश्नकाल को एक घंटे का रखा जाए तब हमारे प्रश्न लगेंगे। मैंने प्रश्न किया था कि मेरे क्षेत्र

में वर्ष 2017-18 में 800 मीटर सड़क का काम शुरू हुआ और आज 6 साल बाद 300 मीटर सड़क बनी है। लोक निर्माण विभाग को मैडल देना पड़ेगा और राष्ट्रपति महोदय से कहना पड़ेगा कि लोक निर्माण विभाग को अलग से मैडल तैयार किया जाए। बारो गांव में 2 किलोमीटर की कुल सड़क थी और 6 साल में इस सड़क को 1.190 किलोमीटर बनाया। यह भी रिकॉर्ड है। वर्ष 2014-15 में ग्रांगे पूजे सड़क का कार्य हमने शुरू किया और 2500 मीटर कुल सड़क थी लेकिन अभी तक 1.765 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। इसी तरह से रावा 4 किलोमीटर सड़क है और लोक निर्माण विभाग ने इसमें रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यह 165 मीटर मात्र सड़क बनी है। मेरे क्षेत्र की

14-03-2022/1700/NS/AS/2

निचार वांगतू सड़क है इसमें नाबार्ड और विधायक प्राथमिकता का पैसा लगा है और इसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह कुल 4 किलोमीटर सड़क है और अभी तक 3.765 किलोमीटर ही सड़क बना पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं भवनों की बात करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेकों भवन हैं जो वर्ष 2005 से बनने शुरू हुए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। एकलव्य स्कूल के लिए केंद्र सरकार के जनजाति विभाग मंत्रालय से एडवांस में लोक निर्माण विभाग के खाते में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन लोक निर्माण विभाग की कारगुज़ारी ऐसी है अभी वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2022 तक तीन होस्टल बने हैं जबकि छः होस्टल बनने थे। स्कूल भवन अभी तक कंप्लीट नहीं है। डाइनिंग हॉल की तो बात ही नहीं है अभी तक लैब ही नहीं बनी है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जबकि वहां पर जमीन उपलब्ध है लेकिन इनकी कार्य करने की नियत ही नहीं है। वहां से अधिशासी अभियंता का कार्यालय 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने ये जितनी भी सड़कें यहां पर बताई हैं ये सभी अधिशासी अभियंता के 7 किलोमीटर दायरे में हैं। अगर लोक निर्माण विभाग का कार्य इस किस्म का हो तो जनता को सुविधाएं कैसे मिलेंगी? यह मेरी समझ से बाहर है। आजकल लोक निर्माण विभाग में और नया चक्र 10 सी0सी0 देने का चला हुआ है। काम मत करो, लंबा खींचों, कोई बहाना ढूंढों और चिट्ठी पर चिट्ठी लिखो तथा 10 सी0सी0 ले लेंगे। इसमें अधिकारी भी खुश और ठेकेदार भी खुश। इधर से भी काम नहीं चला तो आर्बिट्रेशन में चले जाओ। आर्बिट्रेशन में केस की ऐसी सुनवाई करते हैं कि उतना मर्डर ट्रायल भी नहीं होता।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1705/RKS/DC-1

श्री जगत सिंह नेगी... जारी

हर महीने Xens फाइल उठाकर दो-तीन चक्कर आर्बिट्रेशन के पास लगा रहे हैं। आर्बिट्रेशन के पास दूसरा अधिकारी भी जा सकता है लेकिन वहां जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस ठेकेदार ने आर्बिट्रेशन का केस चलाया हुआ है उसे 50 प्रतिशत से ज्यादा फायदा होना है। उस फायदे को बांटने के लिए ये लोग वहां बैठे हैं। आज पी.डब्ल्यू.डी. का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ठेकेदार खुद एस्टीमेट बनाकर पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों को दे रहे हैं। एस्टीमेट बनाने में पैसा मिलता है, एस्टीमेट के बाद टेंडर अवार्ड होने में भी पैसा मिलता है और टेंडर के बाद बिल निकालने में भी पैसा मिलता है। इस तरह पी.डब्ल्यू.डी. में काम कैसे होंगे? मेरे क्षेत्र में एक टनल का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जा रहा है। उस टनल का कार्य वर्ष 2015-16 के बाद बंद हो गया था। यह टनल 200 मीटर की थी। पांच वर्षों में इस टनल का कार्य 70 मीटर भी नहीं हुआ है। इसके लिए पैसा उपलब्ध है लेकिन टेंडर अवार्ड नहीं किया जा रहा है। अगर आप काम ही नहीं करना चाहते तो पी.डब्ल्यू.डी. किसलिए बनाया गया है? कल मांग संख्याः 7 पर चर्चा हो रही थी। पुलिस विभाग के करीब 140 कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादातर काम पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किए जाने हैं। लेकिन यह कार्य पूर्ण नहीं किये जा रहे हैं। स्कूल भवनों के निर्माण कार्य का भी यही हाल है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में हांगो सबसे दूर-दराज का इलाका है। इस स्कूल भवन के निर्माण के लिए जगह और पैसा उपलब्ध हो गया है लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने अभी इसका कार्य शुरू नहीं किया है। नेशनल हाइवे के साथ सीनियर सकेंडर स्कूल, न्यूगलसरी का भवन तैयार कर दिया गया है लेकिन अभी तक इसे शिक्षा विभाग को हैंड-ऑवर नहीं किया गया है। विधान सभा परिसर के पास लाइब्रेरी स्थापित की गई है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो वर्ष पहले किया था। इस लाइब्रेरी में

आज तक लिफ्ट की सुविधा नहीं है। वहां पर लॉ-वोल्टेज की समस्या है। आप इस तरह कैसे उद्घाटन करवा देते हैं? किन्नौर में स्टेडियम का उद्घाटन करवा दिया गया। वहां पर पार्किंग की

14.03.2022/1705/RKS/DC-2

सुविधा नहीं है। खेल मैदान का सरफेस ठीक नहीं है। लेकिन आपने इस स्टेडियम का भी उद्घाटन करवा दिया। ऐसे अनेकों भवन हैं जहां न बिजली, न पानी, न सेफटिक टैंक और न अन्य सुविधाएं हैं लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इन भवनों के उद्घाटन करवा दिए गए हैं। मैंन आज विधान सभा प्रश्न किया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो वन निगम के वाइस चेयरमैन के नाम की पट्टिकाएं स्थापित की जा रही हैं वे किसके आदेश पर लग रही हैं? मुझे जवाब दिया गया कि वन विभाग द्वारा ऐसी कोई पट्टिकाएं स्थापित नहीं की गई हैं। मैंने वन विभाग के बारे में प्रश्न नहीं किया था। मैंने पूछा था कि 'जिला किन्नौर में मुख्य मंत्री द्वारा किए उद्घाटन व शिलान्यास की पट्टिकाओं में वन निगम के उपाध्यक्ष का नाम किस सरकारी नियम और आदेश के तहत लगाया जा रहा है?' जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, you are misleading the House. इसके लिए हमें कंटैम्प्ट का केस बनना पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर दिया गया- 'वन निगम के अंतर्गत।' मैंने वन निगम के अंतर्गत प्रश्न नहीं पूछा था। मेरा प्रश्न था कि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाई गई सड़कों, पी.एच.सीज. स्कूल भवनों और अन्य भवनों पर पट्टिकाएं कैसे लगाई जा रही है? क्या इसके लिए ए,बी,सी,डी, का नाम लगाने के लिए Xen कंपिटेंट है। हमने Xen से इसकी सूचना आर.टी.आई. के तहत मांगी कि किसके आदेश पर इसका नाम पट्टिका में लिखा है? मुझे जवाब आया कि इसके लिए कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो Xen व पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 8 करोड़ रुपये की रिब्बा-कंडा सड़क, थंगी की पौने चार करोड़ रुपये की सड़क में दो वर्ष पहले अनियमितताएं पाई गई थी लेकिन आज दिन तक इस मामले में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। जिस एस.डी.ओ. या जे.ई. ने फर्जी बिल बनाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या यह क्रप्शन एक्ट के तहत सही केस नहीं था? इसका मतलब यह है कि इस विभाग के नीचे से ऊपर तक सभी लोग मिले हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? किसी समय पी.डब्ल्यू.डी. वाले अच्छा काम करते थे। दूर-दराज के

इलाकों में सारा काम पी.डब्ल्यू.डी. वाले करते थे। पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने पहले काफी शानदार सड़कें बनाई हैं। आज उन दुर्गम क्षेत्रों में सड़क जाने के बावजूद भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले लोगों ने अपने सिर पर सामान उठाकर सुन्दर भवन बनाए हैं।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1710/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी...

हमारे दूरदराज के इलाकों में पहले ठेकेदार नहीं आते थे, सारे-का-सारा काम लोक निर्माण विभाग ने किया है और हमारे मजदूरों ने काम किया है। ऐसी शानदार सड़के बनाई हैं, वहां लोगों ने अपने सिर पर सामान उठा करके शानदार बिल्डिंग्ज बनाई हैं और आज तक इनका एक भी पत्थर नहीं गिरा है। आज क्या कारण है, कि सब प्रकार की सुख सुविधाएं इनके पास है, अधिकारी बाहर नहीं निकलते हैं। आज आप टारिंग का काम देखिए, आगे टारिंग हो रही है और पीछे वह उखड़ रही है। इस माननीय सदन में मुख्य मंत्री जी के सामने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को उठाया है। मुख्य मंत्री जी तो उड़न खटोले में उड़ते हैं, उन्हें तो सड़क से जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग बच्चों की तरह खिलौना लेने की जिद करते हैं और खिलौना नहीं मिलता है, तो लेट जाते हैं। अब मुख्य मंत्री जी को तो उड़न खटोला मिल गया है और इन्हें नीचे लेटने की भी जरूरत नहीं है, हमें ही लेटना पड़ेगा। आज सड़के के जो हाल खराब हैं, उस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी मैं उत्तरा खंड गया हुआ था, वहां पर कितनी अच्छी सड़के बनी हैं, अब में किसी के गाल से उन सड़को की तुलना नहीं करूंगा, वैसी वे सड़के थीं। परंतु हमारी सड़के अमरीश पुरी जी के गाल की तरह है। आप बताइए कि हम क्या करें। इस तरह के काम यहां पर हो रहे हैं। इतना पैसा अधिकारी और ठेकेराद खा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, इसके ऊपर हमें एक सोच बनाने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पर्यटक नीचे से नहीं ऊपर से ही आएंगे। वे 530 सीटर जहाज मण्डी में उतारना चाहते हैं। वहां से यदि मनाली जाना है, तो उसके लिए पर्यटकों को सड़कों से ही जाना पड़ेगा। यदि अटल टनल से जाना है, तो कहां से जाएंगे? आज सड़कों पर ध्यान देने की जरुरत है। आप कालका से शिमला आइए, पूरे किसान आंदोलन में सारे टोल बैरियर

बंद हुए थे, परंतु जाबली के पास टोल बैरियर शुरू हो गया, वहां पर सड़क अभी पूरी नहीं हुई परंतु टोल लेने के लिए लोग बैठ गए हैं। आपने बिना कोई सुविधा दिए वहां पर टोल खोल दिया है। आपने उसके ऊपर कोई चिंता जाहिर नहीं की। क्रैश बैरियर के बिना शोघी से ले करके शिमला तक कई दुर्घनाएं हुई हैं। इसका यह कारण है कि बरसात के दिनों में इस स्थान पर सबसे ज्यादा धुंध पड़ती है। वहां पर तीन माले

14.03.2022/1710/बी.एस./डी0सी0/-2

क्रैश बैरियर लगने थे, वे आपने नहीं लगवाए हैं। मैंने इसका प्रश्न किया था, तो थोड़ी सी जगह पर लगा दिए और बाकी वैसे ही पड़े हैं। इन्होंने ब्लैस स्पोट पर क्रैश बैरियर क्यों नहीं लगाए? यदि आप शिमला में इन्हें नहीं लगा रहे हैं तो बाकी जगह में तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। मुख्य मंत्री जी ने दो करोड़ रुपए पहले बजट में और अभी चार हजार करोड़ हवाई अड्डे के लिए रखा है। यदि आप क्रैश बैरियर 3-4 सौ किलोमीलटर सड़क पर लगाएंगे तो हमारे कई लोगों की जाने बचेंगी। यदि आपने इवाई अड्डे बेचने ही है, तो इन्हें क्यों बना रहे हैं? आप अडानी और अंबानी को बुलाइए क्योंकि आपने उन्हीं को इन्हें बाद में बेचना है। जब उनको बेचना है, तो हमारे संसाधन क्यों खर्च किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में एक नई सोच की आवश्यता है और जब तक यह नई सोच नहीं होगी और यह टैंडर में कमीशन का धंधा खत्म नहीं होगा, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। आज सड़कों के निर्माण हेतु समय सीमा निर्धरित होनी चाहिए। कुतुब मीनार को बनने में उतना समय नहीं लगा होगा, जितना आज सड़कों और भवनों को बनाने में लग रहा है। आज 20-20 साल से सड़कें व 15-15 साल से भवन नहीं बन रहे हैं। यह हमारा विभाग किस लिए रखा है? टैंडर तो कोई भी विभाग लगा सकता है, टैंडर को राजस्व अधिकारी भी लगा सकता है और हमारे पंचायत के अधिकारी भी टैंडर लगाने के लिए सक्षम हैं। अभी पुलों की बात करना चाहता हूं, टैंडर भी हो चुके हैं, 6-6 करोड़ रुपए के टैंडर हो चुके हैं, हमारे इलाके में 10-10 साल से पुल नहीं बन रहे हैं। अभी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सारा पैसा मंजूर होने के बाद ऐंपा-II का पुल नहीं बन रहा है, कलिंग का जीपेबल ब्रिज नहीं लग रहा है। जो पुल हमारे डेमेज हुए हैं, उनके लिए आपदा प्रबंधन में पैसा मिलता है, आप उसके लिए एक-एक साल टैंडर लगाने में लगा रहे

हैं। आप किस प्रकार की सुविधा हमें देने जा रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है? इधर आपके लोक निर्माण विभाग में एक-आध केस हम भी

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1715/एच.के.-एन.जी. /1

श्री जगत सिंह नेगी जारी.....

पकड़ा कर देते हैं कि किस अधिकारी ने कहां पर रिश्वत खाई है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। लोक निर्माण विभाग में सद्बुद्धि कब आएगी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हर वर्ष लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपये दिए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वाले इन्हें सारा पैसा दे देते हैं और फिर सो जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग का हाल है। ये विभागों के साथ न कोई बैठक करते हैं और न ही कोई काम समय पर करते हैं। इस प्रकार से तो हमारा सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोक निर्माण विभाग में जान डालनी है तो पुराने जमाने को दोबारा से वापिस लाना पड़ेगा। ठेकेदारी प्रथा को खतम करना होगा। आज लाखों लोग बेरोज़गार हैं। आप दोबारा से काडर बनाइए, जैसे टैकनिकल, लेबर का काडर। आप सभी मण्डलों में लोगों की भर्तियां कीजिए और लोग आपका काम बहुत मेहनत से करेंगे। जब मनरेगा में काम किया जा सकता है तो लोक निर्माण विभाग में भी किया जा सकता है। ऐसा करने से ठेकेदारी व कमीशन की प्रथा समाप्त हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव संख्या - 10 को प्रस्तुत करता हूं। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन 10 नम्बर अच्छा नहीं होता और मालूम नहीं यह नम्बर कैसे लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

समाप्त/-

14-03-2022/1715/एच.के.-एन.जी. /2

व्यवस्था का प्रश्न।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज चौड़ा मैदान में युवा कांग्रेस के लोग बेरोज़गारी को लेकर एक रैली कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में हम सब लोग भी सम्मलित हुए थे। वे सब धरना-प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि प्रदेश में लगभग 11 लाख लोग बेरोजगार हैं और वे रोजगार कार्यालय में नौकरी की कतार में खड़े हैं। आज प्रदेश में धर्मपुर और सिराज, दो स्थानों पर ही नौकरियां मिल रही हैं। आज धरने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें 10-12 युवा साथियों को चोटें आई हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री निगम भंडारी को फ्रैक्चर हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस प्रकार के मामलों में संज्ञान ले। लोकतंत्र में विरोध करना और धरना देना सभी का अधिकार है। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि सरकार के ध्यान में उन चीजों को लाया जाए जो सरकार गलत करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को दिशा-निर्देश दीजिए कि इस मामले में पुलिसवालों ने जो गलती की है उसके लिए उन पर उचित कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ठीक है। आपका विषय आ गया है और इसे सरकार को भेज दिया जाएगा।

समाप्त/

14-03-2022/1715/एच.के.-एन.जी. /3

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या-10 लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन पर

कटौती प्रस्ताव मैंने दिया था, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि सड़क नहीं है तो उसका विकास अधुरा होता है। जब किसी भी गांव या क्षेत्र में सड़क पहुंचती है तभी सम्पूर्ण रूप से उसका विकास होता है। उपाध्यक्ष महोदय, विकास तो पैसे देने से होता है। यदि फण्ड होगा तभी विकास होगा। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें कैपिटल आऊटले में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,098 करोड़ रुपये था और इस वर्ष आपका बजट कम हो गया है। इससे तो विकास पर सीधेतौर से फर्क पड़ेगा। इसमें आपने सड़कें, भवन, स्वास्थ्य संस्थान, स्कूल्ज़, आदि भी बनाने हैं और जब आपने 20 प्रतिशत बजट कम कर दिया है तो लोक निर्माण विभाग का बजट अपने आप कम हो जाएगा। आपके पास स्टेट हैड में पैसा नहीं है। आपने यहां पर लोक निर्माण विभाग का एलोकेशल 4,373 करोड़ रुपये लिखा है। इसमें तो आपने नाबार्ड, सी.आर.एफ. और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का भी पैसा मिला दिया है।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1720/जेएस/वाईके/1

श्री हर्ष वर्धन चौहानः--------जारी-----

आपका बजट केपिटल आउट ले मेंटिनेंस में, वह पिछले साल से कम होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन सड़कों की दशा खराब है, जिनमें गड्ढे पड़े हैं, जिनका जिक्र यहां पर माननीय सदस्यों ने किया, उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। मेरा चुनाव क्षेत्र शिलाई दुर्गम क्षेत्र है। मैं सरकार को आंकड़ें बताना चाहूंगा कि जो विकास की गाथा गाते हैं और सम्पूर्ण प्रदेश का एक समान विकास की बात करते हैं, उसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री सड़क योजना फेज़-॥ में पिछले तीन साल में शिलाई चुनाव क्षेत्र के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। श्री रोहित ठाकुर जी का 1705 अतारांकित प्रश्न था, जिसमें 11 डीविजन हैं, जिनको कोई पैसा नहीं दिया गया है और उसमें शिलाई चुनाव क्षेत्र भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल रोड़ फंड में पिछले चार सालों में 941 करोड़ रुपया आया है। यह मेरा प्रश्न है। उस 941 करोड़ रुपये में से मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र को एक भी पैसा सेन्ट्रल रोड़ फंड के तहत नहीं आया है। सेन्ट्रल रोड़ फंड का 50 प्रतिशत पैसा मण्डी जिला में गया है। मण्डी जिले के भी दो चुनाव क्षेत्र में वह पैसा गया है। विनोद कुमार जी यह मेरा प्रश्न सी.आर.एफ. का है। इसमें 941 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। आप लोग एक समान विकास की बात करते हैं। आप लोगों के क्षेत्रों का भी विकास नहीं हुआ होगा। नाबार्ड की फंडिग में 135 करोड़ से 150 करोड़ रुपये लाए हैं। मगर मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र में अभी केवल 55 करोड़ रुपये पहुंचा है। मैं तो अभी भी 95 करोड़ के डेफिसिट में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं, इनके जो डीविजन हैं, वहां पर भी यही स्थिति होगी। हमारी डी.पी.आर्ज़. नहीं बनती है। मेरे क्षेत्र की डी.पी.आर. बनी है, जो नबार्ड में फंडिंग के लिए भेजी है, वह सैंक्शन ही नहीं होती है। मुख्य मंत्री मंत्री जी यहां पर नहीं है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी बहुत कृपा शिलाई चुनाव क्षेत्र पर भी कर लो। दफ्तर खोलने से विकास नहीं होता। वहां पर दफ्तर खोल दिए। वहां पर अधिकारी नहीं है, वहां पर फंड भी नहीं है। मेरे मिल्ला-बड़वा-किमू रोड़ की डी.पी.आर. साढ़े 8 करोड़ रुपये की नबार्ड को भेजी है। मैं चाहूंगा कि उसकी स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां पर सड़क का काम शुरू हो जाए। अभी यहां

14.03.2022/1720/जेएस/वाईके/2

पर श्री जगत सिंह नेगी जी ने जिक्र किया कि सड़कों की हालत दयनीय है। ठेकेदार ने कई वर्षों से काम सड़कों के लिए कर रहे हैं, उनको तीन-तीन, पांच-पांच साल हो गए मगर फिर भी वे रोड़ कम्पलीट नहीं हैं। पांच साल उन ठेकेदारों को मेनटेंन करने की आवश्यकता होती है। मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि मेंटिनेंस के मामले पर सरकार ने किस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है? मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई की हो। अभी श्री जगत सिंह नेगी जी ने जिक्र किया कि ठेकेदार और पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी की आपस में मिलीभग्त है। आज विकास नहीं होता है। टेंडर अवार्ड नहीं होते,

टाइम से टेंडर अवार्ड नहीं होते। आज किस तरह से काम चल रहा है यह बात किसी से छुपी नहीं है। प्रधान मंत्री सड़क योजना फेज-। और ॥ में कम-से-कम 25 से 30 रोड़ज सैंक्शन हुए हैं। आज तक 5-6 साल हो गए मगर स्टेट हैड के नाम से उनके लिए कोई पैसा नहीं है। शिलाई डीविजन को जिला सिरमौर में मेंटिनेंस के हिसाब से सबसे कम पैसे की एलोकेशन हुई है। मैं चाहूंगा कि मेंटिनेंस के पैसे में वृद्धि की जाए। सत्तोन-चांदनी रोड़ पर इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि उस रोड़ की हालत ही खराब हो चुकी है। मेरे चुनाव क्षेत्र में मानन-कोड़ का रोड़ है, वह बैकवर्ड पंचायत में है, उसकी हालत दयनीय है। सरकार से निवेदन करूंगा कि उसकी डी.पी.आर. बनाई जाए, उसके बाद उसके लिए पैसा का भी प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष जी सत्तोन-चांदनी रोड़ पर एक टिक्कर-खाला आता है, वहां पर पुल बनाने की आवश्यकता है। मैंने उसको बजट में भी डाला है और उस रोड़ से पांच पंचायतों की कनैक्टिविटी होती है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

14.03.2022/1725/SS-YK/1

श्री हर्षवर्धन चौहान क्रमागत :

मगर बरसात में टिक्कर खाला बंद हो जाता है। जियोलोजिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर टिक्कर खाले पर रोड नहीं बन सकती तो एक ऑल्टरनेट रोड-नाडी वाले क्षेत्र से गिरी नदी पर पुल बनाकर इन पांच पंचायतों को जोड़ने की आवश्यकता है। शिलाई में मेरा रैस्ट हाउस है, तीन कमरे हैं, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि शिलाई में अतिरिक्त कमरे बनेंगे। बहुत सुन्दर रैस्ट हाउस बनेगा मगर उसके लिए कोई पैसा नहीं आया, टेंडर नहीं लगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मेरा अतारांकित प्रश्न सं0 2155 था। मैंने पूछा था कि पिछले तीन सालों में शिलाई चुनाव क्षेत्र में कितने शिलान्यास हुए हैं और उनकी अनुमानित लागत क्या थी और कितना पैसा स्वीकृत हुआ है। उसका जवाब मुझे दिया गया है 'the estimated cost of 10 projects was Rs. 74.70 Crore and Funds of Rs. 9.74 Crore

have been sanctioned.' 74 करोड़ रुपये के शिलान्यास और बजट का प्रावधान मु 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़ रुपये में से 6.16 करोड़ रुपये की एक रोड है जोकि सैक्रेटरी साहब के घर को जाती है। वह डल्यानू-नैनीधार रोड है। मैंने वह एम0एल0ए0 प्राथमिकता में सैंक्शन करवाई। 6 करोड़ रुपये तो एम0एल0ए0 प्राथमिकता के स्वीकृत नाबार्ड से आए हैं। मगर स्टेट गवर्नमैंट द्वारा 74 करोड़ रुपये के शिलान्यास के लिए केवल 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब जिन प्रोजैक्ट्स का शिलान्यास किया गया है इनका काम किस रफ्तार से चलेगा, इसका अंदाजा बजट एलोकेशन से लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्वालिटी ऑफ वर्क पी0डब्ल्यू0डी0 में बहुत पुअर है। सब कर्मचारी ऐसे नहीं हैं मगर एक समय में जो पी0डब्ल्यू0डी0 में डैडीकेशन होती थी वह कम हो गई है। आज सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो एक या दो मुख्य सड़कें होती हैं उसमें ट्रैफिक का इंफ्लो बहुत ज्यादा है मगर लिंक रोड में भी ट्रैफिक का इंफ्लो बहुत ज्यादा है। खास करके जो एप्पल बैल्ट्स हैं वहां पर हैवी ट्रक्स चलते हैं। हमारा रोड्स को मैटल करने का जो पैमाना है वह आज भी पुराने समय का है। हम तारकोल सिर्फ 20 एम0एम0 डालते हैं। आज हमको

14.03.2022/1725/SS-YK/2

उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। रोड की स्ट्रैंथ को बढ़ाने की जरूरत है। रोड हम बनाते हैं और एक या डेढ़ साल में उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अगर हम तारकोल की स्ट्रैंथ बढ़ाकर काम करेंगे तो हो सकता है कि रोड की लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की लाइफ लाइन पांवटा से शिलाई हाटकोटी रोड है। उसमें ग्रीन प्रोजैक्ट में 1365 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। काम चला हुआ है, अच्छी रोड बन रही है। मगर मैंने मुख्य मंत्री को कई बार कहा कि छोटी-छोटी लोकल दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए कोई कमेटी फोर्म करो। किसी उच्चाधिकारी को यहां से भेजो मगर सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती है। मैं हैरान हूं कि लोगों की जमीनें काट

दीं लेकिन उनको आज तक कम्पनसेशन नहीं दिया गया है। लोग कम्पनसेशन के इंतजार में हैं। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने पैसा दे दिया है। मगर जो कम्पनसेशन अथोरिटी है वह पैसा लोगों के खाते में नहीं डाल रही है। मैं क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में कहना चाहूंगा। अगर नेशनल हाईवे अथोरिटी के अधिकारियों को बोलते हैं वे हिमाचल सरकार की जो काला अथोरिटी है उसका पांवटा एस0डी0एम0 इंचार्ज है। वे कहते हैं कि एस0डी0एम0 क्या होता है, हम उसकी नहीं सुनते बल्कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की सुनते हैं। हमारे प्रिंसीपल सैक्रेटरी, पी0डब्ल्यू0डी0 बैठे हैं आप वहां जाकर देखिए कि डंगों में पत्थर खड़ा लग रहा है। पांवटा से शिलाई रोड पर पत्थरों के जो डंगे लग रहे हैं वे खड़े पत्थर लग रहे हैं। जब खड़े पत्थर लगेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डंगों की कितन मजबूती होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वर्क की क्वालिटी अवश्य चैक करें। कई जे0सी0बी0 ड्राईवर हैं, कई अन्य गाड़ी के ड्राईवर हैं उनको तनख्वाहें समय पर नहीं दी जातीं।

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2022/1730/केएस/वाईके/1

श्री हर्षवर्धन चौहान जारी----

कुछ जे.सी.बी. हायर की हैं, उनको समय पर पैसा नहीं दिया जाता। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि रोड़ बनें, उसमें कोई आंदोलन या विरोध न हो। मैं समय-समय पर सरकार को आगाह कर रहा हूं कि ऐसा विरोध न हो। सरकार इन छोटी-छोटी समस्याओं का हल करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इंजीनियर इन चीफ बैठे हैं, लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी बैठे हैं, मैं हैरान हूं कि आप जो रोड़ एस.सी. कम्पोनेंट में हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्ज़ नहीं दे रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र की एस.सी. कम्पोनेंट की दो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्ज़ मेरे ख्याल में इंजीनियर इन चीफ के पास हैं या चीफ इंजीनियर साउथ के पास होंगी, सेंक्शन ही आप नहीं कर रहे हैं। एक गंगटोली-बख्याड़ रोड़ है, इस

वित्त वर्ष की समाप्ति को 15 दिन रह गए मगर आपने अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दी है। अगर आप नहीं दोगे तो पैसा लैप्स हो जाएगा। मेरे शिलाई डिविज़न में खुद एस.सी. कम्पोनेंट में पैसा लैप्स हो गया है। आप कर क्या रहे हो? जगत सिंह नेगी जी ने ठीक कहा कि आज सेंक्शन्ज़ में क्या हो रहा है? टेंडर की सेंक्शन में, टैंडर अवार्ड करने में क्यों इतना समय लग रहा है? आप उसको फिक्स करिए, मगर जब आपकी सैटिंग नहीं होती तो टेंडर भी अवार्ड नहीं होते। इस सारे के सारे प्रोसैस के लिए हमें एक टाइम फ्रेम फिक्स करनी पड़ेगी ताकि सारे का सारा प्रोसैस जल्दी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी के साथ प्लानिंग की मीटिंग में कहा था कि फारैस्ट क्लीयरैंस के केस नहीं हो रहे हैं। जैसे आशा कुमारी जी ने ज़िक्र किया, हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारयों को शायद एफ.सी.ए. केसिज़ पुट अप करना और ऑन लाइन का प्रोसीज़र नहीं आता और इतने ऑब्जैक्शन लगते हैं। उदाहरण के रूप में मेरे यहां चिलौन-चौकीभड़वाल सड़क है। दो-तीन बार पहले डी.एफ.ओ. ने वहां

14.03.2022/1730/केएस/वाईके/2

ऑब्जैक्शन्ज़ लगाए फिर कंजर्वेटर ने लगाए फिर बड़ी मुश्किल से जब वह फाइल हमने शिमला पहुंचाई तो 14 ऑब्जैक्शन्ज़ उस रोड़ की एफ.सी.ए. में लग गए। आज दो साल हो गए, उस फाइल को घूमते-घूमते, मैं निवेदन करुंगा कि जब आप फाइल्ज़ प्रोसैस करते हैं, या ऑन लाइन पुटअप करते हैं तो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है, पैमाना है, हार्ड कॉपी चाहिए, डबल कॉपी चाहिए या थ्री कॉपी चाहिए, वे सारी चीजें तो देखो। दो-दो साल एफ.सी.ए. में टाइम लग जाता है। आपके लोक निर्माण विभाग में आजकल एक नया स्केंडल हो गया है। हायरिंग ऑफ जे.सी.बी. मशीन्ज़, जब बर्फ गिरती है उस वक्त भी ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग के बीच एक बहुत तगड़ा नैक्सस है। बरसात का मौसम आएगा उस वक्त भी एक बड़ा तगड़ा नैक्सस है कि पहाड़ आ गया, स्लिप आ गया, 200-300 घंटे जे.सी.बी. चला दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिपार्टमैंट को भी कहना चाहूंगा, ठीक है, टेंडर होते हैं मगर क्या कोई ठेकेदार साढ़े चार सौ-पांच सौ रुपये में जे.सी.बी. की

मशीन को प्रति घंटा चला सकता है? साढ़े चार सौ, पांच सौ रुपये प्रति घंटे में जे.सी.बी. मशीन जो टैंडर डाल रहे हैं, वे चला रहे हैं। मिलीभगत नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर उस ठेकेदार को 100 घंटे अलॉट किए हैं तो वह 100 घंटे नहीं चलाता। 50 घंटे जे.सी.बी. चलती है मगर घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। जो इतना बिलो रेट में टेंडर भर रहे हैं, आप उनको अवार्ड क्यों करते हो? आपको उनको अवार्ड नहीं करने चाहिए। हमारे शिलाई में तो एक प्रथा हो गई है कि अगर रोड़ज़ का काम रोकना है तो टेंडर बिलो रेट डाल दो। कई सड़कों में बिलो रेट टेंडर्ज़ डाल दिए, उसमें यह कंडिशन है कि इससे बिलो होंगे तो अवार्ड नहीं होंगे दोबारा से वह नया प्रोसैस फिर शुरू हो रहा है। आप ऐसे ठेकेदारों जिनकी काम को रोकने की टैंडैंसी बन चुकी है, डवलपमेंट को रोकने की, उनके खिलाफ आप एक्शन लो। जो ठेकेदार किसी भी रोड़ पर बिलो रेट भरता है, अगर एक या दो बार भरता है, आप उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, आप उस पर एक्शन लो। उसकी मंशा काम करने की नहीं है। जो व्यक्ति बिलो रेट टेंडर डाल रहा है, उसकी मन्शा काम करने की नहीं है, उसकी मन्शा सिर्फ

14.03.2022/1730/केएस/वाईके/3

काम रोकने की है। उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में मैन पावर बहुत कम हो चुकी है। आज सड़कों पर लेबर नहीं है। रैस्ट हाउसिज़ में बेलदार नहीं है। ऐसे लोगों को ट्रेंड करके उनको काम देने की ज़रूरत है। आपने पिछली बार कहा कि आप 5000 लोगों को नौकरी देंगे। मेरे ख्याल में लोक निर्माण विभाग में आपने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ओवरऑल पूरे हिमाचल प्रदेश में इवनली भर्ती होनी चाहिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2022/1735/av/ag/1

श्री हर्षवर्धन चौहान---- जारी

ऐसा नहीं कि सिराज और धर्मपुर में थोक में भर्तियां की जाएं और प्रदेश के बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में कम भर्तियां की जाएं। अगर ऐसा होता रहेगा तो इसका ख़ामियाजा तो सत्ता पक्ष के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में आप लोग भी जिस तरह से कुछ क्षेत्रों में डिस्क्रिमिनेशन्ज की बातें करते थें; उन बातों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक समान विकास होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में बहुत सारी बातें लाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोक निर्माण विभाग इनकी तरफ ध्यान दें। कहीं पर चाहे मुरम्मत का कार्य होना है या मशीनरी की डवलपमैंट होनी है; सरकार सब ओर एक समान ध्यान दें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

14.03.2022/1735/av/ag/2

उपाध्यक्ष : अब इस मांग संख्या 10 पर हो रही चर्चा में माननीय सदस्य श्री नन्द लाल हिस्सा लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मांग संख्या :10-रोड, ब्रिजिज एण्ड बिल्डिंग्ज पर आए कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हिमाचल प्रदेश जैसी हिली स्टेट में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट केवल रोड्ज हैं। हमारे यहां एयरवेज ज्यादा स्ट्राँग नहीं है। इसके अतिरिक्त रेल लाइंस तो नाममात्र हैं। इसलिए सारे-का-सारा परिवहन हमारा रोड्ज पर निर्भर करता है। इसलिए हमें रोड्ज के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारे यातायात के साधनों में सुधार आ सकें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में टोटल आउटले 4373 करोड़ रुपये है। पिछले बजट के मुकाबले इसको कम कर दिया गया है और उसके अनुसार आपके पी0एम0जी0एस0वाई0, सेंट्रल रोड्ज फेसिलिटीज, रिपेयर एण्ड मेंटीनेंस यानी हर जगह बजट में कमी की गई है। जब आप बजट में ही कमी कर देंगे तो अच्छे रोड्ज बनने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बजट में कहा गया है कि इस वक्त प्रदेश में 39000 किलोमीटर मोटरेबल रोड्ज हैं जिसमें से 32000 किलोमीटर रोड्ज मैटल्ड हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आप किसी भी रोड को यह नहीं कह सकते कि वह अच्छी तरह से मैटल्ड है। उनको अपग्रेड करने की जरूरत है और अपग्रेडेशन के लिए प्रायोरिटाइज्ड सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। बाकी जिन सड़कों की डी0पी0आर्ज0 बननी हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा है। नाबार्ड के अंतर्गत भेजी गई सड़कों के बारे में भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दो-तीन सड़कों को छोड़कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाकी सभी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कहा गया है कि इस वर्ष 12000 किलोमीटर एग्जिस्टिंग रोड्ज को अपग्रेड किया जाएगा। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जिन 12000 किलोमीटर सड़कों की आप अपग्रेडेशन करेंगे उसमें हमारी प्रायोरिटाइज्ड दो-तीन रोड्ज की ओर भी ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, मैं यहां पर पुल की बात करना चाहूंगा। हमारे रामपुर में बाई पास सड़क पर बस स्टैंड के आगे सतलुज रिवर पर एक पुल बनना है। इस पुल को प्रायोरिटाईज किए हुए चार वर्ष हो चुके हैं। मगर पिछले 4 वर्षों के दौरान उस पुल के बारे

14.03.2022/1735/av/ag/3

में कोई काम नहीं हुआ है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन यदि यह पुल बनता है तो सारे-का-सारा ट्रैफिक शहर के अंदर से आने की वजाय बाहर से निकल जाएगा और शहर के अंदर की कंजैशन खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जो इस वर्ष 23 ब्रिजिज बनाने जा रहे हैं उसमें हमारे रामपुर वाले इस पुल की ओर भी ध्यान देंगे ताकि इसके बनने से वहां सारे-का-सारा ट्रैफिक बाहर-बाहर से निकल जाए। इसके अतिरिक्त, यदि डी0पी0आर्ज0 की बात की जाए तो आपने कहा है कि जून, 2023 तक सारी डी0पी0आर्ज0 बनकर तैयार हो जाएंगी। हम हमेशा प्लानिंग की मीटिंग में उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष कोई-न-कोई डी0पी0आर0 जरूर बनेगी, मगर ऐसा होता नहीं है।।

टी सी द्वारा जारी

14/03/2022/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री नन्द लाल ... जारी

आपने कहा है कि आने वाले जून महीने तक सारी डी0पी0आर्ज0 बनकर तैयार हो जाएगी। हम प्लानिंग की मीटिंग में हर बार यह आग्रह करते हैं कि इस बार कुछ डी0पी0आर्ज तैयार की जाए लेकिन for the last four years डी0पी0आर्ज के मामले में हमने जितना सफ़र किया है, वह हम आपको बता नहीं सकते हैं।। don't know कि इस तरह से दूसरे माननीय सदस्यों के साथ भी किया जा रहा है लेकिन मेरे क्षेत्र में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आग्रह रहेगा कि हमारी सड़कों की जो डी0पी0आर्ज0 बननी हैं, उनको बनाया जाए। आपने वर्ष 2023 तक इनको बनाने का आश्वासन दिया है लेकिन इनको उससे पहले बनाने की कृपा करें। जब हम अधिकारियों से इन सड़कों के मेंटेनेंस के लिए फण्ड के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मेंटेनैंस में तो पैसा ही नहीं है। All the roads require maintenance. एक भी रोड upto the mark और फंक्शनल नहीं है। इसलिए इन रोड़ों की मेंटेनैंस के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाए। ताकि उन रोड़ों की मेंटेनैंस की जा सके। टिक्कर-खमाड़ी सड़क का पहले भी बहुत ज़िक्र हुआ। इसकी दो डी0पी0आर्ज0 सेंटर गवर्नमैंट को भिजवाई गई थी। इनको भी एक्सपीडाइट किया जाए ताकि इनकी सैंक्शन आ जाए और सड़क को पक्का किया जा सके। देवठी-ऊची सड़क कांग्रेस के समय की सैंक्शंड सड़क है। इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। लालसा-चिकसा सड़क लगभग पूर्ण हो चुकी है लेकिन इसको रफ़ रोड की तरह छोड़ा हुआ है। इसको भी कंप्लीट किया जाए ताकि दोनों एरियाज के लोगों को इस सड़क का लाभ मिल सकें। ब्रांदली खड्डु-सुंगरी सड़क की हालत बहुत खराब है। इस सड़क में रोड़े-ही-रोड़े हैं। उसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों पहले यह सड़क दो महीने तक बंद रही और पिछले महीने थ्रू हुई है। दरशाल-मतैलगी सड़क बन रही है, वहां पर दो पुल बनने हैं। इनमें से एक का कार्य

शुरू हो चुका है लेकिन दूसरे पुल का कार्य भी शुरू किया जाए। ये जो सड़कें नहीं बन रही हैं, इसका मुख्य कारण एफ0सी0ए0 केसिज की पेंडेंसी हैं।

14/03/2022/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

इसके लिए हमें एफ0सी0ए0 के केसिज को एक्सपीडाइट करना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एम0पी0 लैड और एम0एल0ए0लैड या डी0सी0 के फंड से जितनी भी सड़कें और ambulance roads and all बनाए जा रहे हैं, उनको सरकार टेकओवर कर लें ताकि इन पर यातायात बहाल हो सकें। मेरे चुनाव क्षेत्र में 10 बिल्डिंग्ज हैं जिनका कार्य कांग्रेस के समय में वर्ष 2017 से पहले शुरू हुआ था लेकिन वे आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। रामपुर में वर्ष 2017 में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया गया लेकिन आज तक उसका काम चल रहा है और वह बनकर तैयार नहीं हुआ है। Then we have Engineering College at Kotla. उसका भी पिछले चार साल से काम चल रहा है। उसका शिलान्यास भी वर्ष 2017 में हुआ था and our classes are being run at Sundernagar. हमने कहा था कि वहां से एक-दो कोर्सिज यहां पर लेकर आएं। लेकिन वे नहीं आ। ननखड़ी कॉलेज का काम भी पिछले पांच सालों से धीमी गति से चला हुआ है। Again we have a Degree College at Jeori, इसके लिए तो जगह ही नहीं ढूंढ पाए। उसका सिर्फ शिलान्यास हुआ है। Senior Secondary School, Khamadi; Senior Secondary School, Kungal Balti का शिलान्यास भी उसी दौरान का हुआ है लेकिन अभी तक इनका कोई काम नहीं हुआ है।

एन0एस0द्वारा जारी ...

14-03-2022/1745/NS/AS/1

श्री नन्द लाल .....जारी

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तीन पी0एच0सीज़0 हैं और पी0एच0सी0, गोरा की ड्राईंग में कुछ अल्टरेशन होनी थी और पिछले पांच सालों से इसकी ड्राईंग चेंज नहीं हो पाई तथा

उसी हालत में पड़ा हुआ है। पिछले पांच सालों से पी0एच0सी0, लालसा और पी0एच0सी0, कंगलबाल्टी में कुछ नहीं हुआ। पिछले पांच सालों से मेरे क्षेत्र में किसी भी भवन का काम नहीं हुआ। हम ये कहें कि हमारे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है, । don't know पर मैं यह समझता हूं कि इस वक्त सरकार अपने आपमें बेबस है क्योंकि कोई भी सड़क ठीक नहीं है, कोई बिल्डिंग के काम ठीक नहीं हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस है। हम लोक निर्माण विभाग को शाबाशी दें यह संभव नहीं है। अच्छे चुस्त-दुरुस्त अधिकारी होने चाहिए जो देंखे कि कहां से बजट होना है और इसको कैसे करना है तो इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया और लोक निर्माण विभाग की यह हालत है। जो कटौती प्रस्ताव यहां पर लाया गया है इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद।

14-03-2022/1745/NS/AS/2

उपाध्यक्ष : अब श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा, सुजानपुर : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 10 लोक निर्माण, सड़क पुल एवं भवन पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। लोक निर्माण विभाग किसी भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। प्रदेश में हम लोग जगह-जगह जा रहे हैं आपछोटी सड़कों की बात छोड़िए जो नेशनल हाइवेज हैं इनकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। आप शिमला से सोलन, शिमला से कांगड़ा की तरफ़ जाएं तो इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि नई सड़क दूर की बात है। अब सरकार और विभाग को चाहिए कि कम-से-कम उन सड़कों की मरम्मत तो कर दें। इसके पीछे कारण यह है कि पिछले दो सालों से दुनिया, पूरे देश और हिमाचल प्रदेश में कोविड महामारी की वज़ह से पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर एयर कनैक्टिविटी कम होने की वज़ह से लोग सड़कों से आते हैं और अगर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होगी, इनकी मरम्मत नहीं होगी तो लोग प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आना बंद कर देते हैं। हम लोग दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं और वहां पर कितनी शानदार सड़कें बनी हुई हैं। हमें चाहिए कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेट होने के नाते सड़कों की दशा को ठीक करें और नेशनल हाइवेज की स्थिति खराब हो चुकी है तो इनको भी ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुजानपुर क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। पिछले साढ़े चार सालों से सुजानपुर में सड़कों की स्थिति इतनी खराब हुई है और लोग जगह-जगह इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पहले भी सरकार थी सड़कों की स्थिति अच्छी होती थी और कहीं गड्ढे नजर नहीं आते थे। आज स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमें मुरम्मत के लिए धनराशि ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार दूसरे डिविजनों के लिए धनराशि उपलब्ध करवा रही है तो सुजानपुर भी हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा है। हालांकि सरकार यहां बैठी है, लेकिन इस सरकार को नया रूप देने में हमारे पांव में जो छाले पड़े हैं वह तो मैं ही जानता हूं कि मैंने इसके लिए कई लोगों को नाराज किया है परन्तु यह मेरी बात समझते ही नहीं हैं। जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी आज वो यहां पर अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। इन लोगों को कम-से-कम मेरा धन्यवाद तो करना चाहिए और न केवल धन्यवाद करना चाहिए बल्कि मेरे काम भी करने चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पहले तो सुजानपुर के काम करने चाहिए, मंडी तो बाद में आना चाहिए। आज क्यों चर्चा हो रही है कि मंडी जिले के केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों में ही काम हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

14-03-2022/1745/NS/AS/3

सरकार के ध्यान मे लाना चाहता हूं कि आज प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग व प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग यहां बैठे हैं, हमीरपुर से कुठेड़ा और कुठेड़ा से री सड़क जोकि बहुत शानदान सड़क थी, ठीक है इसके लिए नाबार्ड में पैसा आया और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1750/RKS/एएस-1

श्री राजेन्द्र राणा... जारी

उस रोड की अपग्रेडेशन के लिए काम शुरू किया गया। जिस ठेकेदार को यह काम अवार्ड किया गया है वह काम नहीं कर रहा है जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों को इस सड़क से रास्ता बदलकर दूसरी जगह से जाना पड़ रहा है। इससे इस विभाग की तो छवि

खराब हो ही रही है लेकिन सरकार की साख को भी बट्टा लग रहा है। इस रोड के लिए पैसा तो उपलब्ध है लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करें। मेरी गृह पंचायत, पटलांदर में घाटी से थाना-भडयाना रोड की भी ऐसी ही स्थिति है। उस रोड की अपग्रेडेशन का काम शुरू हुए काफी समय हो चुका है लेकिन यह काम भी अधर में लटका हुआ है। इसके लिए लोग सरकार को कोस रहे हैं। आज से ठीक पांच वर्ष पहले थाना-टिक्कर से परहियां-दी-धार सड़क के लिए नाबार्ड से पांच करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें पुल के कार्य भी किए जाने थे। लेकिन पांच वर्ष बीत जाने पर भी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। ठेकेदार काम को अधूरा छोड़ जाते हैं जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ककड़ पंचायत में छम्ब-रोपड़ी से बातर खड्ड तक सड़क के लिए नाबार्ड से 3.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन यह काम भी लटका हुआ है। ठेकेदार इस काम को अधूरा छोड़कर चला गया है। जब मैंने विभाग से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हम री-टेंडर कर रहे हैं। लोग काफी परेशान हो रहे हैं और वे अपना गुस्सा सरकार पर निकालेंगे। जब विधायक प्राथमिकता की स्कीमें डाली जाती हैं तो विभाग द्वारा लंबे अर्से तक उन स्कीमों की डी.पी.आर्ज. तैयार नहीं की जाती। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की जिन स्कीमों की डी.पी.आर्ज. नाबार्ड को भेजी गई हैं उनके लिए नाबार्ड से पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है। इस बजट में विधायक प्राथमिकता की स्कीमों की लिमिट 150 करोड़ रुपये की गई है लेकिन मुझे लगता है कि हमारी 70 करोड़ रुपये की स्कीमें भी स्वीकृत नहीं हो पाई हैं। जिस तरीके से यह भेदभाव का काम किया जा रहा है, वह सही नहीं है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की जो सड़कें नाबार्ड की स्वीकृति हेतु

14.03.2022/1750/RKS/एएस-2

भेजी गई हैं उनके लिए विभाग टेक-अप करें ताकि उन स्कीमों का काम शुरू हो सके। वर्ष 2016 में 65 हजार करोड़ रुपये के 69 नेशनल हाइवेज बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। सरकार को चाहिए कि

इन योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में काम करे। कई पी.डब्ल्यू.डी., डिविजन्स में अगर बी.जे.पी. का ठेकेदार न हो तो दूसरे ठेकेदारों को टेंडर फार्म नहीं दिए जाते। ब्रांडिड ठेकेदार को ही टेंडर फार्म दिए जा रहे हैं। इससे लोगों का पैसा मिसयूज होने की संभावना रहती है। सुजानपुर में छोटे-छोटे कार्यों जैसे लिंक रोड, मरम्मत के कार्यों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा जाता है लेकिन विभाग दो-दो, तीन-तीन वर्षों तक उस पैसे को खर्च नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि आप विपक्ष के विधायकों का काम नहीं करना चाहते। यह चीजें सही नहीं है। जो हमने शिलान्यास पट्टिका लगाई थी उन्हें भी तोड़ दिया गया है। पिछली सरकार के समय जिन पुलों के काम चले हुए थे उनका निर्माण कार्य भी कछुए की चाल में हो रहा है। सुजानपुर, मिनि सचिवालय का स्ट्रक्चर वर्ष 2017 में खड़ा हो चुका था लेकिन आज भी वह काम उतना ही हुआ है। भवन में तीन-चार टाइलें लगाकर काम को रोक दिया गया है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1755/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री राजेन्द्र राणा जारी...

मुझे लग रहा है कि यह चीजें सही नहीं हैं। इससे पहले एक और चीज मैं आपके माध्य से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बहुत सारे ठेकेदारों ने एक बात ध्यान में लाई है, पहले क्या होता था कि जो ठेकेदार काम लेता था, उसको सीमेंट लोक निर्माण विभाग से मिल जाता था और काम तुरंत हो जाता था। अब सिस्टम बदल दिया गया है कि अगर ठेकेदार ने सीमेंट लेना है, तो वह सिविल सप्लाई विभाग को पहले पैसे जमा करवाएगा और पैसे जमा करवाने के बाद उसे इंतजार करना पड़ता है कि अब उसका सीमेंट आएगा।

उसके बाद काम शुरू होगा, उससे काम में देरी हो रही है और जो छोटे लैवल का ठेकेदार है, जिसके पास पैसे कम हैं, उसका सिस्टम ब्लॉक हो रहा है। पहले विभाग से सीमेंट मिल जाता था और जब बिलिंग होती थी, तो सीमेंट का पैसा कट जाता था, यहां मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में निराशा है, इस सिस्टम को सरकार फिर से ठीक करे। मैं

कहना चाहता हूं कि जिन-जिन कार्यों के लिए पैसा गया हुआ है, उन्हें सरकार तुरंत करवाए। लोक निर्माण के संबंधित अधिकारी डिविजन में हैं, उन्हें आदेश करें कि वे इन कामों को समय पर पूरा करें। मेरे चुनाव क्षेत्र के ऐसे भी उदाहरण हैं कि वर्ष 2017 के जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार होती थी, उस वक्त के पैसे दिए हुए हैं और अभी तक वह काम पूरे नहीं हुए हैं। जब ठेकेदार की शिकायत होती है कि उसने काम नहीं किया, यदि काम नहीं किया तो उसे सजा क्या हुई, क्या उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है? इससे लोगों का विश्वास सरकार से उठता है और मेरा यही निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कें जो टूट गई हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही जो नाबार्ड में हमारी स्कीमें गई हैं, उनमें जल्दी स्वीकृति मिले, साथ में जो डी0पी0आर्ज0 हैं, उन्हें तुरंत पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को विकास का एहसास हो सके। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब मांग संख्या -10 में चर्चा के लिए आदरणीय मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगे।

14.03.2022/1755/बी.एस./डी0सी0/-2

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, रोहडू : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 10, सड़क व पुल एवं भवन है, जो यहां पर रखी गई है, मैं भी इसमें बोलने के लिए अपने-आप को शामिल करता हूं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक सड़कों की बात है,

श्रीमती आशा कुमारी: उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है और माननीय सदन में गणपूर्ति का अभाव है।

उपाध्यक्ष : यहां पर माननीय तीन मंत्री जी बैठे हैं और ये हर बात को नोट कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचेतक जी और उप मुख्य सचेतक जी आप लोगों को पहले भी कहा था, अन्यथा हम माननीय हाउस को स्थगित कर देंगे। इस पीठ से हमने बार-बार दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहा है और विशेषकर जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप यदि गंभीर नहीं हैं तो हमें हाउस को एडजोर्न करना पड़ेगा। अदरणीय

मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक तथा मंत्री लोग जो यहां पर बैठे है वे भी एंश्योर करवाएं और इस चर्चा को गंभीरता से ले।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : महोदय, सड़के हमारी जीवन रेखाएं होती हैं और जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है, यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय सदस्यों ने काफी बातें इस पर कह दी हैं, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज तक जो भी सरकारें आई हैं उन सभी ने विकास कार्यों के भरपूर प्रयास किए हैं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1800/डी.सी.-एन.जी. /1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी.....

सभी के समय में बहुत सड़कें निकली हैं। आज परिस्थितियां अलग हैं और आज विभाग को सतर्क होने की आवश्यकता है। विभाग को कुछ नए उपाए करने की आवश्यकता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि अनेक सड़कें, चाहे नाबार्ड की हों या पी.एम.जी.एस.वाई. की, इसके अलावा बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स के निर्माण कार्यों को एक ही ठेकेदार द्वारा लिए गए हैं। उसने इन्हें कैसे मैनेज किया यह तो विभाग या वह ठेकेदार ही जानता है। एक ही ठेकेदार ने 7-8 सड़कों का काम लिया हुआ है और कार्य एक भी सड़क पर नहीं हो रहा है। वहां पर सभी काम बंद पड़े हुए हैं। मेरे क्षेत्र की एक भी सड़क पूरी नहीं हो पा रही है। मैं सरकार व लोक निर्माण विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब ऑनलाइन टैंडर कॉल करते हैं उस वक्त एक शर्त लगानी चाहिए कि यदि पिछला कार्य पूरा नहीं किया है तब तक दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। आज मेरे क्षेत्र में अनेक सड़कें ऐसी हैं जो एक ही व्यक्ति को दी हुई हैं। जब मैं विभाग को पूछता हूं कि काम कैसे होगा तो वे कहते हैं कि हम इसके लिए नोटिस देंगे और उसका प्रोसेस बहुत लम्बा होता है। विभाग उसे नोटिस तब देगा जब काम करने की अवधि समाप्त होने वाली होगी। जब तक वह नोटिस का जवाब देगा या अन्य कार्रवाई होगी तब तक कार्य की लागत बढ़ जाएगी और

काम अधूरा फंस जाएगा, फिर विभाग उसका रि-टैंडर करेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे कार्यों के लिए फील्ड स्टाफ की तैनाती की जाए और उनकी जवाबदेही तय की जाए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि पैसा होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हमने एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मसली की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया था लेकिन आज तक उसका काम नहीं हो पाया। इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, रनौल के भवन के लिए तो विभाग से टैंडर भी नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, खशराह व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बलून के भवनों का हाल है।

14-03-2022/1800/डी.सी.-एन.जी. /2

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बरटू की बिल्डिंग में भी काम नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। पूर्व सरकार के समय मेरे क्षेत्र के पटाड़ा में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह स्वीकृत किया गया था और उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये भी दिए गए थे। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद वह पैसा भी वापिस ले लिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पैसे को वापिस दे देंगे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। विभाग में एक बहुत विचित्र बात देखने को मिलती है कि बहुत पुरानी सड़कें जो लोक निर्माण विभाग के नाम हैं और उनका रख-रखाव भी विभाग करता है। लेकिन जब हम उन्हें उस पर काम करने के लिए कहते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर गिफ्ट डीड नहीं है। पुरानी सड़कों में आज गिफ्ट डीड कौन देगा? मेरे क्षेत्र में अनेक ऐसी सड़कें हैं जिनकी देख-रेख लोक निर्माण विभाग करता है लेकिन यदि उनकी मुरम्मत के लिए अधिकारियों को कहें तो वे जवाब देते हैं कि फण्ड नहीं हैं। आपके अधिकारी कहते हैं कि पहले फण्ड लाओ फिर इस सड़क के चौड़ीकरण या सोलिंग का काम करेंगे। टारिंग-मैटलिंग के लिए तो पहले प्राक्कलन बनेगा फिर वह पास होगा और तब तक तो पांच साल निकल जाएंगे व सरकार चली जाएगी। दूसरी बात जो रोड्ज़ लोक निर्माण विभाग बनाता है,

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1805/जेएस/एचके/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः-----जारी-------

जो रोड्ज़ लोक निर्माण विभाग बनाता है, उनमें नालियों का प्रावधान नहीं रखा जाता । उससे भी सड़कों को बहुत नुकसान होता है। कई जगह कल्वर्ट नहीं डाले जाते। कई अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों व बगीचों में तो डंगे तक लग रहे हैं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर डंगे लग रहे हैं। इस तरह से विभाग का बहुत पैसा खराब हो रहा है। जहां तक विकास की बात है, वह बिल्कुल ठप्प है। सुंगरी-खदराला रोड़ बहुत पुराना है, इसकी आज बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी अब जवाब में कहीं यह न बोले कि आपकी सरकार में भी ऐसी ही स्थिति थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमारी सरकार में ऐसा था तो आप ऐसा न करें। लेकिन वैसी स्थिति हमारी सरकार के टाइम में नहीं थी। जुब्बल-कोटखाई के पास एक नाण-बलोखर रोड़ है, वह भी बहुत पुराना रोड़ है, जब ठाकुर राम लाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वह उस दौरान का रोड़ है। उसकी स्थिति भी आज दयनीय है। अगर विभाग को कहें कि इसकी देख-रेख करो तो वे कभी गिफ्टिड की बात करते हैं, कभी फोरेस्ट की बात करते हैं, इसलिए जब रोड़ बनाए जाते हैं तो इसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रोहड़ू में बखिरना पुल पब्बर नदी पर लग रहा था। हमारी सरकार के समय उसकी सैंक्शन आई थी और आपकी सरकार के समय वह टूट गया। आप उसको भी आज तक नहीं बना पाए। इसी तरह से कई रोड़ हैं। मैं कई लोअर और हाई लेबल के अधिकारियों से बात करता हूं। वे कहते हैं कि पैसा तो विभाग में बहुत आ रहा है लेकिन वह पैसा कहां जा रहा है इसका पता नहीं है? वहां धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहां तक मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर कोई भी फाउंडेशन स्टोन इस सरकार ने नहीं रखा है। वहां पर न कोई बिल्डिंग में और न कोई सड़क में पैसा लग रहा है लेकिन वह पैसा कहां जा रहा है? इतना जरूर है कि जो सीमा

कॉलेज की बिल्डिंग हमने बनाई थी, उसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। एक समोली पुल था, उसका उद्घाटन भी मुख्य मंत्री जी ने किया। समोली पुल के बारे में मैंने प्रश्न लगाया था और समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से ज़वाब आया था कि समोली पुल डबल लाइन पुल बन रहा है, जिसका 80 प्रतिशत काम

14.03.2022/1805/जेएस/एचके/2

पूरा हो गया है और 20 प्रतिशत काम रह गया है, जबकि उसका उद्घाटन 3-4 साल पहले हो गया था। विभाग की यह स्थिति है। मेरा एक भी रोड़ पास नहीं हुआ है। श्री सुरेश भारद्वाज जी ने एक रोड़ समाला से जुणी नाला की ओर बनाया था। वह भी 8-9 किलोमीटर रोड़ था लेकिन काम करवाया सिर्फ 3 किलोमीटर रोड़ का। उस 3 किलोमीटर रोड़ का आपने उद्घाटन किया, उसी दिन उसमें बस गई और उसके बाद आज दिन तक बस नहीं गई है। ऐसी बात नहीं है कि हम विपक्ष मे हैं इसलिए आलोचना कर रहे हैं। यह हकीकत है, यह बात धरातल पर है। यदि कोई अच्छा काम हुआ होगा तो मैं उसका भी धन्यवाद करूंगा। आपके पास स्टाफ भी नहीं है। रोहडू में एस.ई. नहीं है। वहां पर 10-11 महीने हो गए बिना एस.ई. के । जो एस.ई. लगाए जाते हैं, उसमें रामपुर या शिमला के एस.ई. को चार्ज दिया जाता है लेकिन वे रोहडू नहीं आते । जब मैंने अधिकारी से बात की तो कहने लगे कि मैं क्या करूं मेरे पास 11 लोगों का ही स्टाफ है और उसमें से 10 पोस्टें खाली हैं और एक आदमी से मैं क्या करूंगा? विभाग ऐसे कैसे चल सकता है? एक वहां पर सड़क बन रही है लेकिन उसमें पुल का प्रोविजन नहीं रखा गया है। कानू-जांगली सड़क पर पुल लगना है। मेरा विभाग से आग्रह रहेगा और मुख्य मंत्री से भी रहेगा कि उस सड़क के ऊपर पुल का प्रावधान किया जाए। पिछली बार एक अशारा पुल लगना था उसके लिए 80 लाख रुपये सैंक्शन करवाए थे लेकिन वह पुल भी नहीं लगा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

14.03.2022/1810/SS-HK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागत :

जब मैंने बाद में इंक्वायरी की तो पता चला कि वह 80 लाख रुपया कहां गया! मेरा एक प्रश्न भी लगा था, उसमें जवाब आया कि जो शिसारा पुल के लिए 80 लाख रुपया आया था उसका हमने सामान खरीदा है। वह पुल नहीं लगा है, उसको कोई सामान ही खरीद लिया। एक हमारी बरशील सड़क है उसका पैसा भी कहीं और ही डाईवर्ट कर दिया। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? आप रेलिंग लगाते हैं, वह भी आप वहां पर लगा रहे हैं जहां पर उसकी ज़रूरत नहीं है। जहां हम बोलते हैं कि रेलिंग लगाओ वहां पर नहीं लगाते। जहां पर डंगों की ज़रूरत है वहां पर नहीं लगाते। यही हो सकता है कि वह काम किसी आदमी को बेनिफिट देने के लिए दिया जाता हो। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि काम नहीं हुए। परन्तु मैंने काम में कमियां गिनाईं हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं।

मैं रोहडू चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा, बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में नहीं बता सकता। परन्तु रोहड़ में पी0डब्ल्यू0डी0 की स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं पिछली सरकार के समय के काम गिनाऊं तो रोहडू में बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स आए। अगर मैं उनको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। अब पता नहीं रोहडू के लिए सरकार का क्या रवैया है? दूसरा, मेरा माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह रहेगा कि हमारा रोहडू से सम्बाला के लिए बाईपास रोड बहुत आवश्यक है। उस पर भी गौर फरमाएं। एक मंडारली-करछाली-शिलान रोड है वह एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाला था। यह बन रहा था लेकिन अब इसका भी काम बंद हो गया। इस प्रकार स्थिति ठीक नहीं है। हालत खराब है।

दूसरा, मेन रोड डोडरा-क्वार की बात आती है। पिछली सरकार के समय में उसके लिए मु0 42 करोड़ का बजट आया था। जब मैंने पता किया तो अभी तक उसमें ढाई या तीन

करोड़ रुपये का काम हुआ है। वह काम कब करना है क्योंकि वहां वर्किंग सीजन बहुत कम है। शायद छः महीने तक का ही है। डोडरा में बिल्डिंग

14.03.2022/1810/SS-HK/2

समय से नहीं बन रही। आपकी क्वार में स्कूल की बिल्डिंग है जोकि नहीं बन रही। इस तरीके से बहुत सारी खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। बछलान टापू रोड है, बराड़ा से मल्खून रोड है, जिस्कून से जाखा रोड है। पी0डब्ल्यू0डी0 रैस्ट हाउस पटाड़ा के बारे में मैंने पहले कह दिया। तांगनू-जांगला रोड व पुल की बात आई। पेखा का एक सीनियर सकैंडरी स्कूल है जहां पर श्री सुरेश भारद्वाज जी पढ़े हैं। उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही। आप हर जगह बोलते हैं कि मैं पेखियन हूं, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।

दूसरा, सिविल हॉस्पिटल रोहडू है। उसमें डॉक्टर्स रेजीडैंस के लिए बहुत पहले टेंडर हो गए। लेकिन वह अभी तक अधूरा पड़ा है। डिपार्टमैंट को पूछते हैं तो पता चलता है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा। फिर काम किसने कराना है? अब एम0एल0ए0 ज्यादा-से-ज्यादा डिपार्टमैंट को बोलेगा, ठेकेदार के पीछे नहीं घूमेगा। आज की तारीख में यह स्थिति है। इसी तरह से हमारा सीमा कॉलेज में स्टाफ का रेजीडैंस था उसका बहुत पहले फाउंडेशन स्टोन रखा गया था लेकिन वह अभी तक नहीं बना है। सीनियर सकैंडरी स्कूल गौंसारी की बिल्डिंग पांच-छः महीने से बनकर तैयार है लेकिन बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि बच्चे अंदर क्यों नहीं बैठे तो बोलते हैं कि इसका उद्घाटन होना है। आपसे उसका उद्घाटन भी नहीं हो रहा जो हमने बिल्डिंगें बनाई हैं। आप उसका उद्घाटन तो करो ताकि बच्चे बिल्डिंग के अंदर बैठें।

उपाध्यक्ष महोदय, जलोहगाढ़ रोड की स्थिति ठीक नहीं है। शील-बराड़ रोड की स्थिति ठीक नहीं है। रोल रोड बहुत पुराना रोड है इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। खशधार रोड की स्थिति ठीक नहीं है।

जारी श्रीमती के0एस

14.03.2022/1815/केएस/वाईके/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी---

दूसरे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग यहां पर रखी है, जो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की कुछ बातें कही हैं तथा जो-जो मैंने सुझाव दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उन पर गौर करेगी। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.03.2022/1815/केएस/वाईके/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई)ः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10, "लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन" पर चर्चा मैडम आशा कुमारी जी, जो इस माननीय सदन की वरिष्ठतम सदस्या हैं, उन्होंने प्रारम्भ की, मैं भी उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। जैसे मुझसे पूर्व हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा विशेषकर अगर हम पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र की बात करेंगे, हमारे जो गत चार वर्षों के अनुभव रहे, सबसे पहले तो वर्ष 2018 में जो हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा थी, ठियोग-खड़ा पत्थर, हाटकोटी रोड़, उसका कार्य रोका गया। जिस तरह वर्तमान प्रदेश सरकार की बात हो या केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की बात हो, सबका साथ, सबका विकास की वो बात करते हैं लेकिन यह जो कथन है यह सबका साथ, कुछ का विकास ही लग रहा है। जैसे यहां पर हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा, इन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. फेज़-2 का आंकड़ा दिया, हमारे दुर्गम क्षेत्र जिनमें चाहे शिलाई की बात हो, जुब्बल-कोटखाई की बात हो और उसके अंतर्गत कुछ हमारे चम्बा के क्षेत्र भी आते हैं, वहां कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई और इससे पूर्व नरेन्द्र ठाकुर जी जो हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र से माननीय सदस्य हैं, इनका पिछले मार्च के सत्र के दौरान एक प्रश्न लगा था जिसका उत्तर था कि पूरे प्रदेश में गत तीन वर्षों में 2293 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हिमाचल प्रदेश को मिली और उसमें 13 मण्डल ऐसे थे जहां पर आपकी

एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। यही पी.एम.जी.एस.वाई. फेज़-2 का हमारा अनुभव रहा और पी.एम.जी.एस.वाई. फेज़-3 के अंतर्गत भी जो प्रथम चरण में आपने 15 ब्लॉक लिए हैं, उसमें हमारा ब्लॉक नहीं है। चाहे जुब्बल की बात करें या कोटखाई की बात करें। सैंट्रल रोड़ फंड जो एक और महत्वपूर्ण फंडिंग एजेंसी होती है, उसमें भी हमें मात्र लॉलीपॉप ही मिला। जिला शिमला का एक पुल बलबीर सिंह वर्मा जी ने अपने क्षेत्र के लिए लिया है बाकी जिला शिमला को इस 941 करोड़ रुपये में से विकास की कोई भी भागीदारी नहीं। फंड अलॉटमैंट में डिस्पेरिटी न हो, कथनी और करनी में कोई अंतर न हो, यह मेरा

14.03.2022/1815/केएस/वाईके/2

वर्तमान सरकार से आग्रह रहेगा। वर्ल्ड बैंक फेज़-1 या फेज़-2 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल के दौरान, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान 1365 करोड़ का प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2007 में स्वीकृत हुआ था और वर्ल्ड बैंक फेज़-2 की सैद्धांतिक मंजूरी भी वर्ष 2017 में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्राप्त हो गई थी। 770 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हिमाचल प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों को और इम्प्रूव करने के लिए मिलनी थी उसमें भी हमारे क्षेत्र का, जिला शिमला का कोई विवरण नहीं है। हालांकि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क छैला-नैरीपुल-सोलन-ओछघाट सड़क के माध्यम से हमारे तीन जिले जुड़ते हैं। चाहे शिमला की बात करें या सोलन और सिरमौर जिला की बात करें, उसमें हमारी इस सड़क का कोई विवरण नहीं है। आपके अनेकों पद खाली पड़े हैं। चाहे चीफ इंजीनियर्ज़ की बात हो या एस.ईज़. की बात हो। रोहड़ू का उदाहरण ब्राक्टा जी ने दिया और पूरे प्रदेश में लगभग एस.ईज़. के 11 पद खाली पड़े हैं। जैसे मैडम आशा जी ने फील्ड स्टाफ की बात कही। आपकी ड्रॉइंग ब्रांच बहुत कमज़ोर पड़ी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

14.03.2022/1820/av/yk/1

श्री रोहित ठाकुर---- जारी

इसके अतिरिक्त आपके सामने माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा ने रोहड़ू के एस0ई0 का उदाहरण दिया। इस वक्त पूरे प्रदेश में लगभग 11 एस0ई0 के पद खाली पड़े हैं। यहां पर माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी ने भी फील्ड स्टाफ की शॉर्टेज के बारे में बात कही है। आपकी हर डिवीजन में ड्रॉईंग ब्रांच एक बहुत कमजोर कड़ी है क्योंकि उनमें स्टाफ ही उपलब्ध नहीं है। आपने हमें कोटखाई में डिवीजन दिया जिसका हमने स्वागत किया है। मगर आप वहां एक सर्वेयर तो भेज देते, उस डिवीजन में एक भी सर्वेयर नहीं है। जब डी0पी0आर्ज0 ही समय पर नहीं बनेंगी तो हमारे प्रदेश का विकास कैसे संभव हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ0यशवन्त सिंह परमार की पहली प्राथमिकता सड़कें ही थीं। उसी वजह से 240 किलोमीटर सड़कों से बढ़कर आज 39000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। यह एक निरंतर प्रोसैस है मगर हर जगह लेबर की कमी है। आप हर बजट में 5000 नियुक्तियों की बात करते हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतिम बजट में ये सारी बातें धरी-की-धरी न रह जाएं। अतः मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि हर डिवीजन्स में लेबर्ज की नियुक्तियां शीघ्रातिशीघ्र हों ताकि हम ठेकेदारों की मर्सी पर न रहें। आप सब लोगों ने पीछे बर्फबारी के दौरान सारा प्रकरण खुद देखा होगा जब हमारे शहरी विकास मंत्री जी को स्नो बाउंड एरियाज को खोलने के लिए दो बार खुद प्रयत्न करने पड़े थे। इसलिए लोक निर्माण विभाग के पास अपनी लेबर्ज, मशीनरीज इत्यादि उपलब्ध होनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त बर्फीले क्षेत्रों में स्नो कटर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मैं पीछे पढ़ रहा था कि बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्ज से बर्फ हटाने के लिए अलग से स्नो कटर का प्रावधान कर रही है। इसी तरह का प्रावधान हमारे बर्फीले एरियाज के लिए भी किया जाना चाहिए। आपने विशेषकर टूरिज्म क्षेत्रों को विकसित करने के लिए वहां की सड़कों के रिन्यूल कोड के लिए 5 वर्ष का समय घटाकर 3 वर्ष किया है,

हम उसका स्वागत करते हैं। मगर इस प्रकार की छूट हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी हो क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र में वीयर एण्ड टीयर बहुत होता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे

14.03.2022/1820/av/yk/2

प्रदेश में टनल्ज की बहुत आवश्यकता है। मैंने इस संदर्भ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट पर हुई चर्चाओं के दौरान भी विस्तार से अपनी बात रखी है। मैंने कहा था कि आने वाले समय में टनल्ज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और प्रदेश के हर क्षेत्र की ऑल वैदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल डिस्टेंसिज शॉर्ट होंगे बल्कि आपके पर्यावरण की रक्षा भी होगी। प्रदेश में बहुत सारी बहुमूल्य जानें सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जा रही हैं। मैं यहां पर पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा देख रहा था जिसमें लगभग 3100 से ज्यादा बहुमूल्य जानें गई हैं तथा उसमें भी हमारा जिला शिमला अग्रणी रहा है। यहां पर सड़क हादसों में लगभग 612 जानें गई हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में क्रैश बैरीयर्ज का प्रावधान होना चाहिए था। मगर बजट में इसका अभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आपने प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र को लगभग 30-30 किलोमीटर की ए0एम0पी0 दी है। यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो हमारी सीमा एक तरफ उत्तराखंड के साथ लगती है और दूसरी तरफ हमारा एरिया नारकण्डा के साथ लगता है। इस प्रकार से 30 किलोमीटर तो 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी रोड्ज हैं उसकी लगभग 10 प्रतिशत के आस-पास की रोड्ज को प्रति वर्ष ए0एम0पी0 की अप्रूवल्ज मिलें।

आपने ए0एम0पी0 की स्पेसिफिकेशन्ज बढ़ाई हैं। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान आपकी प्रत्येक वर्ष लगभग 60-70 किलोमीटर सड़क हर डिवीजन की पक्की होती थी, वह घटकर अब 30 किलोमीटर रह गई है। इस तरह से आप एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से वापिस ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त ठियोग बाईपास है; जिसके बारे में शायद माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा अपनी बात में विस्तार से कहेंगे।

यह हमारे जिला शिमला का बोटल नैक है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण सड़क का काम हुआ था। इस सड़क के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। मुझे याद है कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के टाइम में पूरे 5वर्षों में आपका कुफरी का केवल एक किलोमीटर बाईपास नहीं बन पाया था। वही हाल ठियोग

14.03.2022/1820/av/yk/3

बाईपास का न हो; मैं ऐसा सोचता हूं। इसके अलावा बिल्डिंग्ज का निर्माण हो रहा है। उसमें चाहे हैल्थ डिपार्टमैंट की बात हो या शिक्षा विभाग की बात की जाए; ये सारे-के-सारे काम 'कछुआ चाल' से चले हुए हैं। मैं सबसे बड़ा उदारण अपने कोटखाई के विकास भवन का देता हूं। यहां पर माननीय सदस्य राणा जी पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल का स्मरण करवा रहे थे। हमारे कई ऐसे-ऐसे स्मरण हैं जो पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल के हैं। हमारे कोटखाई विकास भवन का शिलान्यास दिनांक 15 नवम्बर, 2008 को किया गया था यानी खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड और विकास भवन कोटखाई का शिलान्यास एक ही दिन किया गया था।

टी सी द्वारा जारी

14/03/2022/1825/टी0सी0वी0/एच0के0/1
श्री रोहित ठाकुर ... जारी

लेकिन ये कार्य दशकों तक लटके हुए हैं। इनको गति मिलनी चाहिए। हमारी जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर की बिल्डिंग्ज हैं, आपकी सरकार के चार साल के कार्यकाल के बावजूद भी इनके निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। चाहे पी0एच0सी0 देवरी-खनेटी, पी0एच0सी0, बखोल, पी0एच0सी0, भलोड़ या पी0एच0सी0 रामनगर की बात हो, ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनका कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कंप्लीट नहीं हो पाया। यही स्थिति हमारी शिक्षा की है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी

रिलेक्सेशन न हों। आपने इस बजट में एम्बुलेंसिज रोड्ज की पासिंग का भी प्रावधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और हमारे किसान लघु और सीमांत किसान है। जिस तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय में एंबुलेंस रोड्ज की पासिंग हो रही है, इसी तरह का अनुसरण लोक निर्माण विभाग को भी करना चाहिए। पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कार्य एक्सैस हो चुके हैं लेकिन फिर भी वे लम्बित पड़े हुए हैं। उनके बारे में भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो यहां पर जो कमियां गिनाई गईं हैं, वे अवश्य ही इनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14/03/2022/1825/टी0सी0वी0/एच0के0/2

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कितनी गंभीर है? पहले ये एक बिल लाए और अभी एक और बिल लेकर आए हैं। यह सरकार की विवेक को दर्शाता है। इन्होंने सलम बस्तियों में सम्पत्ति का अधिकार देना है, यह ठीक है, नगर निगम के चुनाव है और चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें याद आती है लेकिन बिल को रखने का एक समय होता है, एक तरीका होता है। हमने भी बिल को स्टडी करना है कि आप बिल के कौन से सैक्शन को चैंज कर रहे हैं? सरकार इनके प्रति गंभीर नहीं है, अगर गंभीर होती तो दो दिन पहले बिल लाती लेकिन अंतिम समय में बिल को इसलिए लाए हैं ताकि नगर निगम के चुनाव को जीता जा सके। चुनाव के नजरिए से यह सरकार काम करती है लेकिन बिल को नहीं देख रही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि जो इस माननीय सदन की परम्परा रही है, कम-से-कम दो दिन पहले बिल आना चाहिए। इसलिए आप इस पर कड़ा संज्ञान लीजिए और उचित कार्रवाई के निर्देश भी दीजिए।

श्रीमती आशा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये 6.30 बज़े नोटिस दे रहे हैं और बिल उसके बाद यहां आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को तत्काल विदड्रा किया जाए। आपके सचिवालय ने इसको अलाऊ कैसे किया? आप इनके प्रभाव में आएं। इस माननीय सदन की जो मर्यादा रही है, उसके मुताबिक चलकर इसको बिदड्रा कीजिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : उपाध्यक्ष महोदय, ये अमेंडमेंट एक-डेढ़ घंटे में नहीं आएगी सकती। इसके लिए आप 10-11 बज़े का समय दीजिए या फिर 1-2 दिन के लिए हाउस को एक्सटैंड किया जाए। ...व्यवधान...

एन0एस0द्वारा जारी .....

14-03-2022/1830/NS/AG/1

...व्यवधान...

श्री जगत सिंह नेगी : अमेंडमैंट्स देनी हैं। ऐसे कोई कानून पास नहीं हो जाता है। यह मर्यादा के अंगेंस्ट है। पहले अमेंडमैंट्स होंगी फिर बाद में बिल पास होगा। ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावना को समझता हूं। ...व्यवधान... हम अमेंडमैंट्स सुबह 10 बजे तक ले सकते हैं। समय बढ़ाया जा सकता है। अमेंडमैंट जो हैं आप सुनिए ...व्यवधान... माननीय संसदीय कार्य मंत्री आज तो हाउस एक्सटैंड नहीं होगा। आज वैसे भी नहीं होता। आज नहीं करेंगे। ...व्यवधान...

श्री जगत सिंह नेगी : आज हाउस एक्सटैंड नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव में वैसे भी हाउस एक्सटैंड नहीं होता है। ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : आप बैठिए। रूलिंग तो आने दो। ...व्यवधान... आज एक्सटैंड नहीं करेंगे। कट मोशन के दिन हाउस एक्सटैंड नहीं होता है और यह बात ठीक है इसको हम भी मानते हैं। ...व्यवधान... आप बैठिए तो सही। आप रूलिंग तो आने दीजिए। आप बैठिए। आपने प्वाईंट ऑफ आर्डर लिया और हमने दिया। माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, आप प्लीज़ बैठें। ...व्यवधान... इस पर रूलिंग दे रहे हैं। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री जगत सिंह नेगी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर व्यवस्था दो जो हमने मुद्दा उठाया है।

उपाध्यक्ष : आपके अमेंडमैंट्स हम सुबह 10 बजे तक ले लेंगे। नहीं-नहीं, श्री जगत सिंह नेगी जी सुबह 10 बजे तक ले लेंगे। यह आपका अपना समय है ...व्यवधान... माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री : जब बात आएगी तब करेंगे। ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : हां, ठीक है। ऐसा है कि आपने कहा कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है तो हमने सुबह 10 बजे तक का समय दे दिया। ...व्यवधान... 10 बजे तक का समय दे दिया गया। ...व्यवधान... एक ही दिन बचा है इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को लगा होगा कि जनता के हित के लिए यह जरूरी है तो इसलिए लाए होंगे। सुबह 10 बजे अमेंडमैंट्स ले लेंगे। ...व्यवधान... माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

14-03-2022/1830/NS/AG/2

संसदीय कार्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कट मोशन्ज़ पर बहस चल रही है और ये उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। यह मैटर अभी तक सर्कुलेट हुआ है और अभी तक हाउस में पुट तो किया ही नहीं है। जब यह हाउस में लाया जाएगा तब इस पर प्वाईंट ऑफ आर्डर भी होगा और इसकी रूलिंग भी होगी। अभी तो सिर्फ सर्कुलेशन है। ...व्यवधान... कोई चीज़ सर्कुलेशन से नहीं होती है। जब यह अभी तक इंटरोड्यूस ही नहीं हुआ, आपके पास आया है आपके पास सिर्फ यह सर्कुलेट हुआ है। जब यह हाउस में चेयर की ओर से आएगा तब खड़ा होता है। हाउस में तब आता है जब हाउस में रखा जाएगा। जब हाउस में रखा ही नहीं है ...व्यवधान... मैडम,

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

14.03.2022/1835/RKS/एएस-1

संसदीय कार्य मंत्री... जारी

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य, और सी.पी.आई.(एम) के श्री राकेश सिंघा बिल की प्रतियां लेकर अपने-अपने स्थान में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

...व्यवधान... मैडम, अभी यह हाउस में रखा नहीं गया है, अभी यह सर्कुलेट किया गया है। यह हाउस में पुट नहीं हुआ है। आप सर्कुलेशन की बात कर सकते हैं। ...व्यवधान... आपके

पास कट-मोशन पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप सड़कों के बारे में किसी चीज पर बोलना नहीं चाहते।...व्यवधान... आप गरीबों का कोई काम नहीं करना चाहते। ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। इस मांग पर चर्चा समाप्त होने के उपरांत हम इस बिल पर व्यवस्था देंगे। ...व्यवधान... अभी मांग संख्याः10 पर चर्चा पूरी नहीं हुई है। ...व्यवधान... आपकी पार्टी के सदस्य इस मांग पर चर्चा करने वाले हैं, कृपया इस मांग पर चर्चा पूरी कर लीजिए। ...व्यवधान...जब बिल पेश होगा तो आपको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर दे दिया जाएगा। पहले आप इस मांग पर चर्चा पूर्ण कर लीजिए। ...व्यवधान... कृपया एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। श्री जगत सिंह नेगी जी, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अब इस सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

14.03.2022/1845/बी.एस./डी0सी0/1

विधान सभा की बैठक पुनः आरम्भ हुई

उपाध्यक्ष : मांग संख्याः ।0 पर चर्चा जारी रखते हुए, अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कहीं पर गलती हुई है, तो मान लेनी चाहिए कोई भी गलती को स्वीकार करके छोटे नहीं हो जाते।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका समय है और मुझे लगता है कि आपको अपनी मांगो के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। माननीय सिंघा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और ये बोलना चाहते हैं, कृपया इन्हे बोलने दें। माननीय शहरी विकास मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल सदन में आता है तो उसकी पुरःस्थापना होती है और उस बिल को पीठ की ओर से पुकारा जाता है और मंत्री उसे

पुरःस्थापित करता है, अभी यह बिल पुरःस्थापित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विधान सभा को बिल दिया गया है और चिट्ठी लिखी गई कि यह जरुरी विषय है। दूसरा काग़ज जिसे हाउस की कार्यवाही के लिए पहले ही टाइप कर दिया जाता है और जब बिल पुरःस्थापित हो जाएगा उसके बाद उसे मान्य सदन में बांटना है। यह सदन कागज सदन में गलती से बांट दिया गया है। यदि आप इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति देंगे तभी पुरःस्थापित होगा। उसके बाद इसमें संशोधन मांगे जाएंगे। यह कागज गलती से बांट दिया गया है और यह मानवीय त्रुटि है। इसमें इन्हें ऐसी कोई चीज नहीं ढूंढनी चाहिए। सदन का हर व्यक्ति जानता है कि जब तक बिल पुरःस्थापित नहीं होगा, तब तक सर्कुलेट नहीं हो सकता।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-03-2022/1850/डी.सी.-एन.जी. /1

शहरी विकास मंत्री जारी.....

इस लिए ये जानबूझ कर नोन-इश्यू का इश्यू बनाना चाहते हैं। ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : आप लोगों (विपक्ष) का समय बहुत महत्वपूर्ण है। लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवनों से जुड़ी हुई मांग संख्या - 10 बहुत महत्वपूर्ण है।...व्यवधान... माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने कह दिया है कि मानवीय गलती हुई है। जो कल सर्कुलेट होनी थी वह आज हो गई।...व्यवधान... माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी को अपनी बात रखने दीजिए क्योंकि समय हो रहा है। ...व्यवधान... यह मानवीय गलती है।...व्यवधान... हम अनुमति देंगे तब पुरःस्थापित करेंगे।...व्यवधान...

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : ...व्यवधान... He is Minister in-charge of the Bill. He is responsible for the Bill... interruption... This is against the Rules... interruption...

Deputy Speaker: ...Interruption...This is not against the Rules. व्यवधान... माननीय शहरी विकास मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

शहरी विकास मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनको मालूम है कि इस माननीय सदन में कोई भी कागज़ात दिए जाते हैं तो वे विधान सभा सचिवालय द्वारा दिए जाते हैं। विधान सभा सचिवालय स्वतंत्र होता है और किसी भी मंत्री के अंतर्गत नहीं होता। ...व्यवधान...हमने जो बिल दिया है और वह विधान सभा सचिवालय द्वारा सर्कुलेट किया गया है। ...व्यवधान... यहां पर कोई सरकार या मंत्रालय का व्यक्ति नहीं बैठा है।...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : मैं इसमें व्यवस्था दे देता हूं।...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी, श्रीमती आशा कुमारी जी व अन्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं।...व्यवधान... आप सभी मांग पर चर्चा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी बहुत देर से

अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी आप अपना विषय रखें। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी से निवेदन है कि 5-6 मिनट बचे हैं और अपना विषय रखें।...व्यवधान... यह समय आप सब विपक्ष के लोगों का ही है। ...व्यवधान... सात बजने वाले हैं और फिर आप लोग कहेंगे की समय हो गया। ...व्यवधान... सरकार ने कह दिया है। ...व्यवधान... मैं आप लोगों को अलाऊ ही नहीं करूंगा। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी आप अपनी बात कहें। ...व्यवधान... आप सभी (विपक्ष) वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सब व्यवस्था को समझते हैं। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप कहें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शहरी विकास मंत्री जी कह रहे हैं कि गलती से बांट दिया गया है। माननीय मंत्री जी या तो इन शब्दों वापिस ले लें या फिर ...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्होंने नहीं यह तो विधान सभा सचिवालय द्वारा सर्कुलेट किया गया है और यह एक मानवीय भूल है। ...व्यवधान... इसमें सरकार की ओर से कुछ

नहीं है। ...व्यवधान... सरकार द्वारा विधान सभा सचिवालय में विषय रखा गया था और इस पर मानवीय भूल हुई है। ...व्यवधान... मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि इसमें हम देखेंगे कि किस की तरफ से इस प्रकार की भूल हुई है और जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी वह की जाएगी। ...व्यवधान... अब तो आसन की तरफ से व्यवस्था आ गई है।...व्यवधान... सरकार की ओर कभी भी कोई बिल सर्कुलेट नहीं किया जाता। सरकार तो विधान सभा सचिवालय में बिल की कॉपी देती है और कहती है कि यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसे सभा पटल पर रखा जाए। उसके बाद विधान सभा सचिवालय उस पर आगामी कार्रवाई करता है। ...व्यवधान... नहीं, यह विड्रोल नहीं हुआ है। ...व्यवधान... विधान सभा सचिवालय द्वारा समय को लेकर भूल हुई हैऔर इस विषय में हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। ...व्यवधान... आपने कहा कि संशोधन देने के लिए टाइम नहीं है ...व्यवधान...

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

14.03.2022/1855/जेएस/एचके/1

उपाध्यक्षः----जारी--------

...व्यवधान... हमने कहा 11.00 बजे तक टाइम आपको दिया जाता है। ...व्यवधान... राकेश सिंघा जी, यदि आप विषय रख लेते तो पांच मिनट में आप,...व्यवधान... महत्वपूर्ण मांग थी, जो आपका समय था ...व्यवधान...11.00 बजे तक का कहा। हम पुनर्स्थापित कर रहे थे। सरकार की तरफ से यह यहां आया हुआ है और हम इसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ...व्यवधान... माननीय सुरेश भारद्वाज जी,....व्यवधान... कृपया आप लोग बैठें। माननीय मुख्य मंत्री जी विषय में कुछ इंटरवीन कर रहे हैं। कृपया आप लोग बैठें।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि यह मानवीय त्रुटि हुई है और कई बार काम करते-करते आदमी से गलती हो जाती है और मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। बिल पुरःस्थापित होना है और उसके बाद स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा भी होगी और सिर्फ शब्दों पर जा कर, अगर इसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है तो आदमी से काम करते-करते गलती हो जाती है और गलती उसी

से होती है जो काम करता है, इस बात को इनको मानना चाहिए। इसको बहुत तूल नहीं देना चाहिए। कभी किसी से भी गलती हो सकती है और हुई है तो उसको स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने कहा कि इसमें ज्यादा तूल न दे कर जो पी.डब्ल्यू.डी. पर चर्चा चली है, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको हम आगे बढ़ाएं।

उपाध्यक्षः माननीय हर्षवर्धन जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे विषय को समाहित कर दिया है और मुझे लगता है कि अब विषय को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि राकेश सिंघा जी इस माननीय सदन के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ...व्यवधान.... इतनी देर से आप यही बोल रहे हैं। ....व्यवधान... आप पहले निर्णय कर लें कि कौन प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ले रहा है? सभी लोग न उठें। हर्षवर्धन जी, आप बोलें। लास्ट प्वाइंट ऑफ ऑर्डर होगा।

14.03.2022/1855/जेएस/एचके/2

श्री हर्षवर्धन चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, हम मान सकते हैं कि गलती हो जाती है। मगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। मंत्री जी ने हमको यह इशू किया है, उपरोक्त बिल हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 मार्च को पुनर्स्थापित किया जा चुका है। जब बिल को पुनर्स्थापित किया जाता है उसके बाद बिल की सर्कुलेशन होती है। आपने विधायकों को बिल को सर्कुलेट कर दिया। साथ में आपने इस अमैंडमैंट में लिख दिया कि 8.00 बजे तक जो संशोधन है, अगर अमैंडमैंट देनी है तो 8.00 बजे तक, ...व्यवधान... सारा कुछ तो हो चुका है और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तो बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। तो यह गलत है। मान लिया कि त्रुटि हुई है, हो जाती है मगर आप उसको मानो। मंत्री जी कह रहे हैं कि यह कागज गलत है, कागज झूठा है। यह कागज तो हमें विधान सभा ने प्रावाइड किया है। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल को मंत्री जी वापिस लें। अगर आपने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इसको वापिस ले लो। इस बिल को विद्ड्रॉ करो, हमारा इतना ही कहना है।

उपाध्यक्षः: क्योंकि 7.00 बजे तक आपका इस महत्वपूर्ण मांग का समय था और अब मुझे लगता है कि 1-2 मिनट ही बचे हैं। शहरी विकास मंत्री आप बोलिए।

शहरी विकास मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सारे माननीय सदस्यों को जो पहली बार भी चुनकर आए हैं, उनको भी चार साल से ज्यादा का समय हो गया है, रूल्ज़ ऑफ प्रोसिज़र उनको भी मालूम है। सरकार की ओर से कभी भी कोई बिल लाया जाता है तो वह माननीय स्पीकर या सचिव, विधान सभा को पत्र लिखा जाता है। कॉपियां इनको सर्कुलेट की जाती हैं और आग्रह किया जाता है कि इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस में लगाया जाए। ...व्यवधान... क्या बोल रहे हैं गलत आप, क्या गलत बोल रहे हैं? आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? ...व्यवधान...क्या गलत बोल रहे हैं आप? पहले मेरी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्षः आशा जी, सुन लीजिए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

14.03.2022/1900/SS-HK/1

...व्यवधान...

शहरी विकास मंत्री : देखिए, आप फिर आगे चले गए हैं। आप बात सुन लीजिए।
...व्यवधान...

उपाध्यक्ष : ऐसा है, यह ज़रूरी नहीं है। जब सरकार कहे कि यह महत्वपूर्ण विषय है और वह विधान सभा सचिवालय को तय करना होता है। जनहित से जुड़े हुए किसी भी बिल को सरकार ला सकती है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। हाउस रूल से ही चलता है।

शहरी विकास मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां सिक्वैंस है मैं वह बता रहा हूं। अगर उसमें गलती पाई जाती है तब ये बोलें। ...व्यवधान... मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ है, आप उसको सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष : माननीय सुरेश भारद्वाज जी, चूंकि सदन का समय हो गया है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक मिनट बैठें। सदन का थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि अभी एक सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना भी होनी है इसलिए माननीय सदन की कार्यवाही आगामी 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। ...व्यवधान... यह तो आपका समय था इसके बाद आसन समय बढ़ा सकता है।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

14.03.2022/1900/SS-HK/2

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय शहरी विकास मन्त्री हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

शहरी विकास मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

14.03.2022/1900/SS-HK/3

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 14 मार्च, 2022 **सचिव ।**